राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
वर्ष 8 अंक 60
मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, गुरुवार, 8 अगस्त, 2024
www.jagran.com
पृष्ठ 14

आज भाला फेंककर इतिहास रचने उतरेंगे नीरज चोपड़ा
>> 12

विश्वास.News

प्रवचन नहीं चंद्रयान 2 की लांचिंग देख रहे थे पीएम ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज-4

जागरण विशेष

कैंसर की पहचान व निदान करेगा आइआइटी का शोध

नई दिल्ली: आइआइटी दिल्ली ने एक ऐसा शोध किया है, जोकि न केवल कैंसर की पहचान करेगा बल्कि उसके निदान की राह भी खोलेगा। • पेज-7

100 ग्राम से चूकीं विनेश, सदमे में देश

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- विनेश के ओलिंपिक सफर का दुखद अंत, 100 ग्राम वजन अधिक होने से अयोग्य घोषित
- प्रधानमंत्री ने आइओए अध्यक्ष पीटी ऊषा से की बात, आइओए की अपील को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने किया खारिज
- ओलिंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान विनेश ने खेल पंचाट में अपील की

पेरिस में वजन कम करने के अभ्यास के दौरान पहलवान विनेश फोगाट। बाद में वजन किए जाने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। आइएएनएस

49.9 किग्रा छह अगस्त को पहली बाउट से पहले विनेश का वजन | **52.7** किग्रा सेमीफाइनल के बाद विनेश का वजन | **50.1** किग्रा सात अगस्त की सुबह फाइनल से पहले वजन

मंगलवार की रात को जब 140 करोड़ भारतीय इस उम्मीद में सोए थे कि भारत की सबसे बड़ी महिला पहलवान विनेश फोगाट बुधवार को देश को स्वर्णिम खुशी देंगी, तब वह रस्सी कूद, साइकिलिंग और सोना बाथ के सहारे अपना वजन कम करने में जुटी थीं। उनका खून भी निकाला गया लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, विनेश का पसीना निकलना बंद हो गया, वह पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गईं, वजन 50.1 किग्रा पर अटक गया। उनके पास मौजूद फिजियो और मुख्य कोच के हाथ पांव फूल गए। अगर वजन और कम करने का प्रयास किया जाता तो विनेश की जान को भी खतरा हो सकता था लेकिन भाग्य और नियमों ने 100 ग्राम का ऐसा धोखा दिया कि स्वर्ण तो छोड़ो रजत भी झोली से फिसल गया।

मूलतः 53 किग्रा भार वर्ग में कुश्ती लड़ने वाली विनेश को इस वर्ग में अंतिम पंघाल के क्वालीफाई करने के कारण 50 किग्रा भार वर्ग में उतरना पड़ा। उन्होंने मंगलवार को पेरिस में पहले दौर में विश्व की नंबर वन व गत ओलिंपिक चैंपियन जापान की यूई सुसाकी और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओसाना लिवाक को हराकर तहलका मचा दिया। इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की पैन अमेरिकन चैंपियन लोपेज गजमैन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। वह ओलिंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थीं। सभी भारतीयों को लग रहा था कि अब तो भारत का एक पदक पक्का हो गया तो बुधवार की सुबह भार कराते समय विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। छह अगस्त को पहली बाउट से पहले विनेश का वजन 49.9 किलोग्राम था। सेमीफाइनल के बाद विनेश ने एनर्जी ड्रिंक ली और भोजन किया तो उनका वजन 52.7 किलोग्राम हो गया। उन्होंने मंगलवार की पूरी रात वजन कम करने की कोशिश की, लेकिन बुधवार को वजन के समय भार 50.1 किग्रा पाया गया। भारतीय दल ने वजन कम करने को थोड़ा और समय देने की विनती की, लेकिन राहत नहीं मिली। (पेज 12 भी देखें)

क्या है नियम : यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम के अनुसार, ओलिंपिक में दो बार वजन लिया जाता है। एक बार शुरुआती बाउट से पहले और दूसरा पदक की बाउट से पहले। अगर कोई खिलाड़ी पहले और दूसरी बार वजन कराने के समय उपस्थित नहीं होता या उसका वजन ज्यादा है तो उसे अयोग्य बताकर अंतिम स्थान पर रखा जाता है। उसे कोई रैंक नहीं दी जाती। यही वजह है कि विनेश को अब पदक नहीं मिलेगा।

विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हो। आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं। लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। मजबूती से वापसी करो। हम सभी आपके साथ हैं।
– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

नियम से ऊपर कोई नहीं है। विनेश के साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है, भले ही वजन थोड़ा ही ज्यादा था, लेकिन हमें नियम का सम्मान करना होगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता।
– नेनाद लालोविक, अध्यक्ष यूडब्ल्यूडब्ल्यू

विनेश को अयोग्य घोषित किया जाना बहुत ही चौकाने वाला है। मैंने उनसे खेल गांव के पाली क्लीनिक में मुलाकात की है। आइओए, भारत सरकार व पूरा देश उनके साथ है। हम विनेश को हर तरह से भावनात्मक और मेडिकल सहयोग प्रदान कर रहे हैं। – पीटी ऊषा, अध्यक्ष आइओए

संसद में भी उठा मुद्दा, खेल मंत्री मांडविया ने दी जानकारी

देशभर में निराशा और साजिश की आशंका के बीच विनेश को अयोग्य घोषित करने का मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस मामले में खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) की अध्यक्ष पीटी ऊषा से बात की है और जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। इसके बाद आइओए अध्यक्ष ने इस निर्णय के विरुद्ध कुश्ती की वैश्विक संस्था युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) से अपील की, लेकिन वैश्विक संस्था ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बाल काटे जाने और कपड़े छोटा किए जाने के बाद भी विनेश का वजन 50 किग्रा नहीं हो पाया था। बाद में विनेश ने खेल पंचाट में संयुक्त रूप से रजत पदक देने की अपील की जिस पर गुरुवार को निर्णय आ सकता है। अगर निर्णय पक्ष में आया तो विनेश को संयुक्त रूप से रजत पदक दिया जाएगा।

संपादकीय

अस्थिर पड़ोसियों से घिरता भारत: बांग्लादेश में तख्तापलट और अराजकता के साथ ही दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है। यह स्थिति भारत के हित में नहीं। **ऋषि गुप्ता** का आलेख।

युवाओं में कौशल विकास की चुनौती: यह समझा जाना बहुत आवश्यक कि अपने देश में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है। डा. **सुरजीत सिंह** का दृष्टिकोण। • पेज-8

विमर्श

सवालों के घेरे में टलती जनगणना : विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग पर अड़े हुए हैं, पर बड़ा मुद्दा तो यह है कि आखिर हमारे देश में सामान्य जनगणना कब होगी जिसमें काफी विलंब हो चुका है। डा. संजय वर्मा का विश्लेषण।

देवभूमि की व्यथा-कथा : तमाम प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हिमाचल प्रदेश की समस्याओं से रूबरू कराती नवनीत शर्मा की डायरी। • पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का

लोकप्रिय एप के हैं बड़े धोखे भी

चैटबाट के इस्तेमाल में रहें सतर्कता

• पेज-13

बांग्लादेश में अराजक स्थिति, अवामी लीग के 20 नेताओं के शव मिले

50 पुलिसकर्मियों की मौत, थाने पड़े हैं खाली

जेएनएन, नई दिल्ली

- भयग्रस्त हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें

बांग्लादेश में इस समय सरकार नहीं है और थानों से पुलिसकर्मी नदारद हैं। ऐसे में हिंदुओं सहित देश के अल्पसंख्यक समुदाय में भय व्याप्त है। रविवार और सोमवार को बड़े पैमाने पर हुए हमलों के बाद हिंदू समुदाय के लोगों समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें और कैसे सुरक्षित रहें। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े लोगों का सबसे बुरा हाल है। पार्टी कार्यालयों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी तक अवामी लीग के 20 नेता और उनके परिवारों के नौ लोग मारे जा चुके हैं, उनके शव मिल चुके हैं, दर्जनों लापता हैं। ढाका में एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। सलीम खान अवामी लीग से जुड़े हुए थे।

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक दो दिनों में कम से कम 50 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं। दर्जनों थानों और पुलिस चौकियों पर हमले-आगजनी हुई हैं। देश के ज्यादातर थाने खाली पड़े हुए हैं। इसके चलते देश की कानून व्यवस्था भंग पड़ी है। प्रेट्र के अनुसार बांग्लादेश पुलिस के एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल एकेएम शहीदुर रहमान ने कहा है कि पुलिसकर्मी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। नागरिकों और युवाओं से भी कहा कि पुलिस उनकी मित्र है।

पाकिस्तान की आइएसआइ जुटी भारत विरोधी प्रचार में

एएनआइ : बांग्लादेश में इंटरनेट मीडिया पर भारत विरोधी दुष्प्रचार सामग्री बहुतायत में है। माना जा रहा है कि भारत और हिंदू विरोधी यह झूठी सामग्री पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा इंटरनेट मीडिया साइटों पर डाली जा रही है। इसके चलते बांग्लादेश में तेजी से अफवाहें फैल रही हैं और भारत के हितों पर चोट हो रही है। इन्हीं अफवाहों के बीच सोमवार को बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय के लोगों, उनकी संपत्तियों और मंदिरों पर हमले हुए। इन हमलों में कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं।

बांग्लादेश में तैनात रहेंगे भारतीय राजनयिक, परिवारों की वापसी पेज>>11

आज कार्यभार संभालेगी अंतरिम सरकार

फ्रांस में बुधवार को रोइस्सी-चार्ल्स डी गाल हवाई अड्डे पर मीडिया से वार्ता करते बांग्लादेशी अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस। एपी

- मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सलाहकार परिषद में होंगे 15 सदस्य
- यूनुस ने कहा, देश में सामान्य स्थिति कायम करने को प्राथमिकता
- प्रेम और शांति से होगा देश का पुनर्निर्माण : खालिदा जिया

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार गुरुवार को कार्यभार संभालेगी। यह जानकारी सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने दी है। बताया कि सरकार में शामिल लोग गुरुवार को रात आठ बजे शपथ लेंगे।

जनरल जमां ने बताया कि अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होंगे और उसके मुखिया मुहम्मद यूनुस होंगे। राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार रात यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने यह नियुक्ति शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद की है। बांग्लादेश के लिए रवाना होने से पहले पेरिस हवाई अड्डे पर यूनुस ने कहा, सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी प्राथमिकता देश में सामान्य स्थिति कायम करने की होगी। देश में स्थिति सामान्य हो और सभी पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए वह पहले दिन से प्रयास करेंगे।

यूनुस को दी गई छह माह कारावास की सजा रद पेज>>11

लोगों की मांग पर प्रापर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स के नियम में संशोधन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, प्रापर्टी से जुड़े लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नियम को सरल बनाना चाहती थी सरकार
- इस साल जो आइटीआर भरे गए हैं, उनमें 72.8 प्रतिशत लोगों ने नई व्यवस्था को चुना

नई दिल्ली में लोकसभा में वित्त विधेयक पर बोलतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एएनआइ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने लोगों की आवाज को ध्यान में रखते हुए बजट में लाए गए प्रापर्टी से जुड़े कैपिटल गेन टैक्स नियम को वापस लिया। हालांकि बजट में लाए गए नए नियम का उद्देश्य राजस्व में बढ़ोतरी करना नहीं था। हम प्रापर्टी से जुड़े लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नियम का सरलीकरण चाहते थे। फिर भी लोगों ने इस पर आवाज उठाई और हमने इसमें संशोधन का साहस दिखाया। लोकसभा में वित्त विधेयक-2024 पर अपने जवाब के दौरान सीतारमण ने कहा कि विपक्ष इस बजट को मध्यम वर्ग के खिलाफ होने की धारणा बना रहा है, जो गलत है। अगले छह महीने में टैक्स प्रारूप में वह कई बदलाव लाने जा रही हैं। वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने वित्त विधेयक-2024 को पारित कर दिया।

प्रापर्टी बिक्री से जुड़े संशोधित नियम के तहत 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई किसी भी प्रापर्टी को बेचने पर लांग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देने के लिए विक्रेता के पास बजट में लाए गए नियम के साथ इंडेक्सेशन से जुड़े पुराने नियम दोनों के विकल्प होंगे। दोनों में से जिस विकल्प के तहत उन्हें कम टैक्स लगेगा, विक्रेता उस विकल्प को चुन सकेगा। इंडेक्सेशन के साथ 20% तो बिना इंडेक्सेशन के 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। दस करोड़ तक की प्रापर्टी बिक्री के गेन का अगर प्रापर्टी में ही निवेश होता है, चाहे उस रकम से दो मकान खरीद रहे हैं तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के साथ पुरानी व्यवस्था जारी है और टैक्सपेयर्स डिडक्शन के तहत अपनी बचत के लिए निवेश कर सकता है। लेकिन इस साल जो आइटीआर भरे गए हैं उनमें 72.8 प्रतिशत लोगों ने नई व्यवस्था को चुना है।

सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब को उदार बनाया है पेज>>3

रास की 12 सीटों के लिए तीन सितंबर को होगा चुनाव

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने नौ राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान कर दिया है। उपचुनाव तीन सितंबर को होंगे। 10 सीटें रास सदस्यों के लोकसभा चुनावों में निर्वाचित होने से खाली हुई हैं, जबकि दो अन्य रिक्तियां राज्यसभा सदस्यों के इस्तीफे से रिक्त हुई हैं। (पेज-4)

'हमास के नए प्रमुख याह्या को जिंदा या मुर्दा पकड़ना लक्ष्य'

तेल अवीव: हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद याह्या सिनवार को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया है। इजरायल ने कहा है कि हम इस खतरनाक आतंकी को पकड़ कर रहेंगे, जिंदा या मुर्दा। (पेज-10)

झारखंड में ईडी, सीबीआइ को जांच के पहले लेनी होगी अनुमति

राज्य ब्यूरो, जागरण • रांची

- झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी

झारखंड में ईडी, सीबीआइ समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब प्रदेश सरकार के किसी अफसर-कर्मचारी या मंत्री-विधायक के खिलाफ जांच के पहले राज्य से लिखित अनुमति लेनी होगी। झारखंड सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी कवच के रूप में झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 में संशोधन किया है। इसके दायरे मे सभी केंद्रीय एजेंसियां आएंगी। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई।

पिछले दिनों झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार के कार्यालय की जांच करने के बाद जब ईडी ने कई सरकारी अफसरों को जांच के लिए समन किया था, तब झारखंड सरकार ने आदेश निकाला था कि किसी पदाधिकारी को बुलाने से पूर्व ईडी को राज्य सरकार को सूचित करना पड़ेगा। ईडी किसी पदाधिकारी को गवाही के लिए बुलाने से पहले भी सरकार से अनुमति ले। हालांकि, ईडी ने इन आदेशों को मानने से इन्कार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विरुद्ध हाई कोर्ट जज की टिप्पणी हटाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भविष्य में सावधानी बरतने को कहा; टिप्पणी को अनावश्यक, अनुचित व निंदनीय बताया
- कहा- शीर्ष कोर्ट के आदेशों का पालन पसंद का मसला नहीं, बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था
- अवमानना के एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने की थी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा शीर्ष अदालत पर कटाक्ष करते हुए की गई टिप्पणी को अनावश्यक, अनुचित और निंदनीय बताते हुए बुधवार को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने संबंधित जज को भविष्य में सावधानी बरतने की नसीहत भी दी। कहा कि शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन करना पसंद का मसला नहीं है, बल्कि बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षकार किसी आदेश से असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जज कभी भी उच्च अपीलीय कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट नहीं हो सकते। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजबीर सेहरावत के 17 जुलाई के आदेश से सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करने वाली टिप्पणियां हटा दीं।

जस्टिस राजबीर सहरावत ने अवमानना आदेश पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असंतुष्टि जाहिर करते हुए 17 जुलाई के आदेश में शीर्ष अदालत पर अनुचित टिप्पणी की थी। कहा था कि शीर्ष अदालत के ऐसे आदेश सर्वोच्च न्यायालय को वास्तविकता से अधिक 'सर्वोच्च' मानने और हाई कोर्ट को संवैधानिक रूप से कम उच्च मानने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सहरावत की टिप्पणी को न्यायपालिका की गरिमा कम करने वाली और अनुचित मानते हुए मामले पर मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम पांच जजों की पीठ में सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह टिप्पणियों से दुखी हैं। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने को बाध्य है क्योंकि इस तरह के आदेश न्यायिक तंत्र को बदनाम करते हैं और न्यायपालिका की गरिमा कम होती है। आदेश में की गई टिप्पणियां अनावश्यक व अनुचित हैं और चिंता का विषय है।

सुप्रीम कोर्ट ने की जजों से भविष्य में अधिक संयम बरतने की अपेक्षा पेज>>6

सूरत की एसीजेएम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की दोषी पेज>>6

सामयिक चिंता

लोकसभा में आज पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड में संशोधन का विधेयक, नकवी ने कहा, संशोधन से हितधारक और पीड़ित दोनों को होगा लाभ

वक्फ और वक्त दोनों की मांग है संशोधन : नकवी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कांग्रेस में मंथन जारी, खुलकर वक्फ की वकालत करती नहीं दिखना चाहती

मुख्तार अब्बास नकवी। फाइल

वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश हो सकता है। माना जा रहा है कि इसे तत्काल पारित कराने के बजाय सरकार भी चाहेगी कि पूरा सदन विस्तार से चर्चा करे। लिहाजा संभावना है कि विधेयक अगले सत्र में पारित कराने की कोशिश हो। लेकिन यह संदेश जरूर दिया जाएगा कि सरकार बोर्ड में संशोधन को जरूरी मानती है। फिलहाल कांग्रेस में मंथन चल रहा है क्योंकि वह खुलकर वक्फ की वकालत करती नजर नहीं आना चाहती और पूरी तरह चुप रहकर मुस्लिमों को यह संदेश भी नहीं देना चाहती कि वह कुछ नहीं कर रही। जबकि कुछ क्षेत्रीय विपक्षी दल मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं।

पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि कांग्रेस ने गलत मंशा के साथ राजनीति की। वक्फ में संशोधन वक्फ और वक्त दोनों की जरूरत है। इसे पहचानते हुए ही अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जेपीसी गठित हुई थी। लेकिन उसके सुझावों को कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया था। सच्चाई यह है कि वक्फ में संशोधन से हितधारक और पीड़ित दोनों को लाभ होगा और पारदर्शिता आएगी।

दरअसल, वक्फ को लेकर शिकायतें जनता से ही आ रही हैं। 2013 में कांग्रेस काल में वक्फ को दी गई असीमित शक्ति के कारण बोर्ड ने ऐसी संपत्तियों पर भी अपना अधिकार जमा लिया जिसका कोई प्रमाण नही है। यह बात तब भी आई थी जब नकवी के मंत्रित्व काल में वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन शुरू हुआ था। आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि पिछले 15 वर्षों में वक्फ की संपत्तियां दोगुनी हो गईं। 2009 में इसके पास लगभग चार लाख एकड़ संपत्ति थी जो अब 9.40 लाख एकड़ है। मथुरा की शाही ईदगाह, वाराणसी की ज्ञानवापी, धार की भोजशाला ये सभी वक्फ के कब्जे में हैं। अप्रैल, 2024 में तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने तो हैदराबाद के फाइव स्टार मैरियट होटल को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। इसी तरह सूरत नगर निगम को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति में दर्ज कर लिया। हाल में एक हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक महत्व के कई स्थलों पर वक्फ की ओर से जताए गए अधिकार के बाद कड़ी टिप्पणी में कहा था आप किसी दिन लाल किले और ताजमहल को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे।

नकवी ने कहा कि फिलहाल वक्फ संपत्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। वंचित मुस्लिम समाज को इसका लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे कई पीड़ित हैं, जिनकी जमीन पर बिना सत्यापन कब्जा हो गया है। विधेयक इससे मुक्ति दिलाएगा, लिहाजा इसका विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। गौरतलब है कि संशोधन विधेयक में 44 संशोधनों का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग

कार्य मंत्रणा समिति में बुधवार को विपक्षी दलों ने मांग की कि पेश किए जाने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक को जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि वह लोकसभा का मूड देखकर इस बारे में फैसला करेगी।

सीबीआइ ने अपने हाथों में ली दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की जांच

27 जुलाई को भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई थी तीन छात्रों की मौत

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के मामले की जांच का जिम्मा सीबीआइ ने संभाल लिया है और संस्थान के मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर शाम सीबीआइ ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में ले लिया। राव आइएएस स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, लापरवाही और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित इस कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण तीन अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। वे बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उसमें पानी भर गया था। ।

हाई कोर्ट ने इन छात्रों की मौत पर पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था- 'आप किस पहलू से जांच कर रहे हैं? अभ्यर्थी कैसे डूबे? बेसमेंट में अचानक इतना ज्यादा पानी नहीं भरता, कम से कम दो-तीन मिनट का समय लगता है। क्या दरवाजा बंद था या सीढ़ियां संकरी थीं?' कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग से इस मामले की सीबीआइ जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने को भी कहा था।

****

150 फीट लंबा, 75 फीट ऊंचा व 60 फीट रामेश्वरम धाम इस बार लालकिला परिसर में आकार लेगा। यह तीन मंजिला भव्य धाम होगा। एक मुखर शिखर के साथ पांच शिखर होंगे, जिस पर इस वर्ष अक्टूबर में रामलीला का मंचन होगा।

आज का मौसम

सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने एवं हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
8 अगस्त	33.0	25.0
9 अगस्त	33.0	26.0
नोएडा		
8 अगस्त	35.0	27.0
9 अगस्त	35.0	27.0
गुरुग्राम		
8 अगस्त	30.0	27.0
9 अगस्त	31.0	26.0

डिग्री सेल्सियस में

तो क्या केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार करेगी ईडी : हाई कोर्ट

ईडी से पूछा ▸ सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत के बाद अपील में क्या बचा

एजेंसी ने नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में दी है चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल। फाइल

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध ईडी की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से सवाल किया है। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, ऐसे में जमानत रद करने की उसकी अपील याचिका में क्या बचा है? न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पूछा कि अगर ईडी की याचिका को अनुमति दी जाती है, तो क्या एजेंसी फिर से केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी?

इस पर ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है और किसी भी अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किया गया था कि वह भ्रमित हो गई। उन्होंने कहा कि क्या यह जमानत, अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है? 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के पहलू पर तीन सवालों पर गहन विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया। लेकिन, सीबीआइ मामले में आरोपित होने के कारण वह अब भी न्यायिक हिरासत में हैं।

बुधवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता शोएब हुसैन ने अदालत से स्थगन देने और गुरुवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू एक अन्य अदालत में व्यस्त हैं। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करना संभव नहीं है और टिप्पणी की कि ईडी को अब मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। अदालत ने कहा कि पिछली बार भी स्थगन की मांग की गई थी। आप हर समय अदालत से अनुरोध नहीं कर सकते जैसे कि इस अदालत के पास कोई काम नहीं है।

अदालत ने टिप्पणी की कि यह मत सोचिए कि अदालतें बिना सोचे-समझे फैसला दे देंगी। इस पर ईडी ने स्पष्ट किया कि पिछली बार जांच एजेंसी के बजाय केजरीवाल के वकील ने तारीख मांगी थी। साथ ही उन्होंने मामले पर बहस के लिए नजदीक की तारीख देने का आग्रह किया। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है। 20 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके विरुद्ध ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने विभव की जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ आप की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला

▸ मामले में शीर्ष अदालत अब 27 अगस्त को करेगी सुनवाई

विभव कुमार। फाइल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने विभव की जमानत याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक का समय दे दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि विभव कुमार की ओर से 24 अगस्त तक संक्षिप्त प्रतिउत्तर दाखिल किया जा सकता है। मामले पर 27 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाती मालीवाल से बदसलूकी और पिटाई के आरोप में जेल में बंद विभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने विभव की याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था, साथ ही कोर्ट ने विभव कुमार के आचरण पर तीखी टिप्पणियां भी की थीं। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि क्या मुख्यमंत्री आवास कोई निजी आवास है। क्या यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्यमंत्री आवास पर 'इस तरह के गुंडे' काम करें। बुधवार को जैसे ही मामला सुनवाई पर आया तो दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सालिसटिर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। हालांकि विभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तो फिर किसी तरह का जवाब दाखिल करने की क्या जरूरत रह जाती है। हालांकि पीठ ने एसवी राजू का अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा कि वह 21 अगस्त या उससे पहले जवाब दाखिल कर दें। याचिकाकर्ता अगर चाहे तो 24 अगस्त तक संक्षिप्त प्रतिउत्तर दाखिल कर सकता है। स्वाती मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास में विभव कुमार द्वारा पिटाई किए जाने का आरोप लगाया था और केस दर्ज कराया था।

करंट से मौत पर आश्रित को मिलेगा 7.5 लाख मुआवजा

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: बिजली से संबंधित (करंट से) दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 7.5 लाख रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने वाले व्यक्ति को पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने डीईआरसी (विद्युत दुर्घटना के पीड़ित को मुआवजा) विनियम, 2024 जारी किया है। इसमें दुधारू पशुओं और पक्षियों को नुकसान होने पर भी मुआवजे का प्रविधान किया गया है।

नियम के अनुसार, यदि बिजली से संबंधित दुर्घटना में कोई व्यक्ति 40-60 प्रतिशत तक घायल होता है, तो उसे एक लाख, एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहने पर 25 हजार रुपये और सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में रहने पर 10 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। बिजली से संबंधित किसी दुर्घटना में पशु के मरने पर पशुपालक को प्रत्येक दुधारू पशु (भैंस, गाय, ऊंट) के लिए 50 हजार रुपये, भेड़, बकरी, सुअर व अन्य के लिए पांच हजार रुपये, घोड़े और बैल जैसे भार ढोने वाले पशुओं के लिए प्रति पशु 25 हजार रुपये, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पशुओं की संख्या अधिक होने की स्थिति पर प्रति परिवार दुधारू पशुओं के लिए तीन लाख रुपये या भारवाहक पशुओं के लिए डेढ़ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।

न्यूज गैलरी

विजेंद्र गुप्ता बने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

नई दिल्ली : रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता दी गई है। विधानसभा सचिव रंजीत सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। दक्षिणी दिल्ली से सांसद निर्वाचित होने के बाद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद से यह पद रिक्त था। भाजपा विधायकों ने विजेंद्र गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना था। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास से मिलकर उन्हें गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग का पत्र सौंपा। (जासं)

नीट पेपर से जुड़ी याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली: नीट परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न आने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वह न तो विशेषज्ञों की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर सकती है और न ही उसकी जगह राय थोप सकती है। (जासं)

डीएसईयू ने छह स्नातक कार्यक्रमों की फीस घटाई

नई दिल्ली: दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) ने अपने छह स्नातक कार्यक्रमों की फीस को घटा दिया है। वित्त समित की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने एससी, एसटी और दिव्यांग छात्रों को ट्यूशन फीस में 60 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है। डीएसईयू ने कहा कि बैंकिंग वित्तीय संवाएं और बीमा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग व डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मीडिया डिज़ाइन, आप्टोमेट्री और चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान, इन छह कार्यक्रमों की ट्यूशन फीस को 2024-25 सत्र के लिए 50 हजार से घटाकर 35 हजार कर दिया गया है। (जासं)

बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा

नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में बुधवार को जांच करते सीबीआई अधिकारी। इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में यूपीएससी के तीन छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। प्रेट्र

कोचिंग सेंटर हादसा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोचिंग सेंटर हादसे में बेसमेंट के चार मालिकों की जमानत याचिका पर अदालत ने सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि चूंकि प्राथमिकी की प्रति अदालत के समक्ष नहीं लाई गई है, इसलिए वह आरोपितों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकती।

राउज एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने गिरफ्तार आरोपितों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाओं पर सीबीआइ को नौ अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस से मामले को सीबीआइ को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और एजेंसी ने मामला दर्ज नहीं किया है। वहीं, आरोपितों के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों ने कानून से बचने की कोशिश नहीं की। घटना के बारे में पता चलने के बाद वे स्वेच्छा से जांच में शामिल होने पुलिस स्टेशन गए थे।

युवराज सिंह से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने नियुक्त किया मध्यस्थ

जासं, नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और एक रियल एस्टेट फर्म के बीच निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा देने में युवराज के गोपनीयता अधिकारों के कथित उल्लंघन और राष्ट्रीय राजधानी में उनके लिए एक आवास यूनिट के कब्जे में देरी से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया है।

न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआइएसी) के तत्वावधान में होगी और इसके नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए मामला अधिवक्ता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश गुप्ता के पास भेजा जाता है। अदालत ने युवराज सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया। बिल्डर के अधिवक्ता ने दावा किया था कि याचिकाकर्ता पर कोई राशि बकाया नहीं है और कहा कि उन्हें सिंह द्वारा भेजा गया नोटिस नहीं मिला है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 लोगों की मौत को बताया आपातकालीन स्थिति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

रोहिणी स्थित आशा किरण गृह। जागरण

दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में एक महीने में 14 लोगों की मौत की घटना को आपातकालीन स्थिति करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को समाज कल्याण विभाग के सचिव को आश्रय गृह के लिए डाक्टरों सहित कर्मचारियों की भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाने में तत्परता बरतने को कहा। अदालत ने कहा कि हमने 20 दिनों में 14 जिंदगियां खो दी हैं। आज मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। एक दिन पहले हमने ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में तीन मौतों के मामले को देखा और गाजीपुर में नाले में गिरने से मां-बेटे की मौत के मामले को। ऐसे में मामले में सरकार को तत्परता से काम करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने आपात स्थिति से निपटने के लिए संविदा के आधार पर भर्तियां करने और आवश्यक मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारियों के समक्ष फाइल को स्थानांतरित करने को कहा। इस दौरान सचिव ने अदालत को सूचित किया कि आश्रय गृह में भीड़भाड़ कम करनी होगी क्योंकि वहां 570 व्यक्तियों की क्षमता के मुकाबले 961 निवासी थे। पीठ ने कहा कि भीड़ कम करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह एक आपातकालीन स्थिति है क्योंकि 14 लोगों की जान चली गई है।

सचिव ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी करेंगे और आकस्मिक स्थिति का ध्यान रखेंगे। भीड़भाड़ से निपटने के लिए एमसीडी और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समक्ष उठाया जाएगा। पीठ ने सचिव को इस संबंध में सीधे एमसीडी आयुक्त से बात करने को कहा। अदालत ने सचिव को छात्रावास में एक एसी व मोबाइल शौचालय लगाने को कहा। सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड के वकील ने बताया कि परीक्षण में पानी ठीक निकला।

मुख्य सचिव को बताएं, आशा किरण में अच्छी नहीं है स्थिति : अदालत ने समाज कल्याण विभाग के सचिव से कहा कि वह मुख्य सचिव को सूचित करें कि आशा किरण में चीजें ठीक नहीं हैं। वहां एक समर्पित अधिकारी को तैनात करने की आवश्यकता है। अदालत को बताया गया कि वर्तमान में प्रशासक अतिरिक्त प्रभार के रूप में पद संभाल रहे हैं।

राजनिवास ने आप सरकार को दी आत्ममंथन की सलाह

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

एमसीडी में एल्डरमैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ की ओर से फैसला सुनाए जाने पर एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार व उसके नेताओं को आत्मावलोकन और आत्ममंथन करने की ओर इशारा करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फैसले के बाद नगर निगम में वैधानिक रूप से आवश्यक निकायों की स्थापना करने और 19 महीनों से लंबित प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाएगी।

राजनिवास ने कहा, यह चिंता का विषय है कि संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद आप सरकार बिना वजह मुकदमेबाजी में उलझती रही। इससे न केवल कोर्ट का समय और जनता का पैसा बर्बाद हुआ बल्कि निगम को भी पंगु बनाया गया। ऐसा नहीं होता तो जनवरी 2023 में उपराज्यपाल के फैसले के बाद वैधानिक समितियों के गठन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सकती थी।

अस्पतालों में भर्तियों को लेकर गुमराह कर रहे स्वास्थ्य मंत्री'

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : राजनिवास ने अस्पतालों में भर्तियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। राजनिवास ने कहा कि सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने डाक्टरों व अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती के लिए ठोस प्रयास नहीं किया। हमेशा झूठे बहाने बनाने का ही काम किया है। राजनिवास ने कहा कि डाक्टरों की नियुक्ति-भर्ती का कार्य राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसकी बैठक बुलाने और कोई भी निर्णय लेने का अधिकार कानून उन्हें देता है। यदि उनकी मंशा डाक्टरों आदि को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की होती, तो इसके लिए प्राधिकरण की बैठक बुलाई होती।

डीयू में प्रवेश का पहला चरण हुआ खत्म, प्राथमिकताएं भरने के लिए दो दिन बढ़ाए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगे स्पोर्ट्स और ईसीए के लिए ट्रायल

▸ अब तक 1.7 लाख छात्रों ने भरी हैं प्राथमिकताएं

दिल्ली विश्वविद्यालय। फाइल

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में प्रवेश का पहला चरण समाप्त हो गया है। दूसरे चरण के लिए कालेज और कोर्स की प्राथमिकताएं भरने के लिए छात्रों को दो दिन का और समय दिया गया है। इसे सात से नौ अगस्त कर दिया गया है। छात्र नौ अगस्त रात 11.59 मिनट तक प्राथमिकताएं भर सकते हैं। जिन्होंने अब तक प्राथमिकताएं नहीं भरी हैं, उन्हें डैशबोर्ड पर पहले लाग इन करना होगा। अब तक 1.7 लाख छात्रों ने प्राथमिकताएं भरी हैं। पहले चरण में तीन लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। सवा दो लाख छात्रों ने पंजीकरण शुल्क जमा किया है।

सीयूईटी के परिणाम जारी होने के बाद एक अगस्त से डीयू में प्रवेश का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। छात्र कामन सीट अलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस-यूजी) पर जाकर अपनी प्राथमिकताएं भर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने अधिसूचना में कहा है कि छात्रों की ओर से सहेजी गई प्राथमिकताएं आवंटन और प्रवेश का निर्धारण करेंगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अधिकतम संख्या में प्राथमिकताओं का चुनाव करें। नौ तारीख की आखिरी तिथि निकलने के बाद छात्रों को कोर्स और कालेज की प्राथमिकताओं को जोड़ने, हटाने या संपादित करने की सुविधा नहीं मिलेगी। छात्र की ओर से भरी गईं प्राथमिकताएं नौ अगस्त रात 12 बजे स्वतः आटो लाक हो जाएंगी। विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश की पहली आवंटन सूची 16 अगस्त को जारी की जाएगी। बता दें कि डीयू ने 28 मई को पहले चरण की शुरुआत की थी। डीयू ने 69 कालेजों में 71 हजार सीटों पर कुल 79 कार्यक्रमों में दाखिले की घोषणा की है। इन कालेजों में बीए प्रोग्राम में 183 विषयों के संयोजन उपलब्ध हैं।

ईसीए (पाठ्येत्तर गतिविधियों) व स्पोर्ट्स के लिए ट्रायल 12 अगस्त से शुरू होंगे। प्रदर्शन आधारित कार्यक्रमों बीए आनर्स संगीत, बैचलर आफ फाइन आर्ट्स, बीएससी शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा व स्पोर्ट्स, बीएससी (पीई, एचई एंड एस), अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए परीक्षण और स्पोर्ट्स कोटा 12 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। छात्रों को उसके अनुरूप व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। ईसीए व स्पोर्ट्स कोटे के प्रवेश की जानकारी देने के लिए डीयू की ओर से शुक्रवार नौ अगस्त अपराह्न तीन बजे से वेबिनार का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण डीयू के यूट्यूब चैनल पर होगा।

सिलेंडर में गैस रिसाव से लगी आग में पांच लोग झुलसे, बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

▸ दो बच्चे सहित छह लोग कमरे में थे मौजूद, चाय बनाने के लिए जलाया था चूल्हा

नीलमणी कालोनी में झुलसे लोग। वीडियो ग्रैब

साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र की नीलमणि कालोनी में बुधवार सुबह साढ़े सात बजे पांच किलो के सिलेंडर में गैस रिसाव होने से कमरे में आग लग गई। दंपती और उनके दो बच्चों सहित छह लोग झुलस गए। छह माह के एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। सभी झुलसे लोगों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है। तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाने के दौरान हादसा हुआ।

मूलरूप से बदायूं के उसहेद कालोनी के रहने वाले 26 वर्षीय प्रमोद परिवार के साथ नीलमणि कालोनी में किराये पर रहते हैं। उनके साथ उनका छोटा भाई 24 वर्षीय दीपक और साला 26 वर्षीय अजय भी रहते हैं। प्रमोद, अजय, दीपक मुरादनगर की रसोई गैस की एजेंसी पर सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते हैं। प्रमोद व उनकी पत्नी रेनू बुधवार सुबह छह बजे उठ गए। इनके दोनों बेटे छह माह का लव व दो साल का कुश चारपाई पर लेटे थे। छत पर सो रहे अजय और दीपक भी चाय पीने के लिए कमरे में आ गए थे। कमरे के दोनों दरवाजे बंद थे। रेनू ने चाय बनाने के लिए सिलेंडर का रेगुलेटर खोला। इसके बाद चूल्हा जलाने के लिए जैसे ही माचिस की तीली जलाई, आग का भभका उठा और कपड़ों को चपेट में ले लिया।

योजना

26 गैर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का होगा विकास

क्षेत्र का पुनर्विकास पूरा होने पर उसे कंफर्मिंग एरिया (नियोजित क्षेत्र) घोषित किया जाएगा, करीब छह लाख नई नौकरियां होंगी पैदा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र। फाइल

पिछले कुछ सालों से लटकी 26 गैर नियोजित (नान कंफर्मिंग) औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास की योजना पर सरकार तेजी से काम करने जा रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे करीब छह लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। पुनर्विकास कार्य पूरे होने के बाद इसे कंफर्मिंग (नियोजित) एरिया घोषित किया जाएगा। नियोजित क्षेत्र घोषित होने पर औद्योगिक इकाइयों को ऋण लेने में आसानी होगी। यहां तीन बिंदुओं पर काम किया जाएगा।

इन गैर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का होगा पुनर्विकास : आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पाकेट-ए, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव, ख्याला, हस्तसाल पाकेट-डी, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिठाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, करावल नगर, डाबरी, बसई दारापुर, प्रह्लादपुर बांगर, मुंडका उद्योग नगर दक्षिण, फिरनी रोड मुंडका, रणहोला, नंगली सकरावती व टिकरी कलां शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, गैर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में लेआउट प्लान बनाने का 90 प्रतिशत खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। केवल 10 प्रतिशत हिस्सा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से लिया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली सरकार का कहना है कि डीडीए ने समय पर औद्योगिक क्लस्टर नहीं बनाए, जिससे अवैध या गैर नियोजित औद्योगिक एरिया बनते गए। कई इलाकों में उद्यमियों को व्यवसायों व कारखानों को चालू रखने के लिए आवासीय जमीन का इस्तेमाल करने को मजबूर होना पड़ा।

इन तीन बिंदुओं पर होगा काम

1. मास्टर प्लान-2041 की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लेआउट योजना तैयार करेगी दिल्ली सरकार। लेआउट योजना बनाने में स्थानीय उद्योग एसोसिएशन या सोसायटी की मदद ली जाएगी।
2. औद्योगिक क्षेत्रों को हरा-भरा, स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सीवरेज, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था और सड़कों को बेहतर किया जाएगा। बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए डेवलपर्स को शामिल किया जाएगा।
3. औद्योगिक क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से अनुसंधान एवं विकास केंद्र, मान्यता प्राप्त टेस्ट लैब, प्रशिक्षण केंद्र, अनुभव केंद्र, टूल रूम, प्रोसेसिंग सेंटर, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, कच्चा माल गोदाम, लाजिस्टिक केंद्र समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

****

दुर्घटना रोकने के लिए सार्वजनिक बस संचालन की नई नियमावली लागू

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

▸ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सार्वजनिक बस संचालन की नई नियमावली लागू करने की घोषणा की

दिल्ली के अंदर बस दुर्घटना रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल की है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरकार की ओर से सार्वजनिक बस संचालन की नई नियमावली लागू करने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने बस दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों व राहगीरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई एहतियाती कदमों की घोषणा की।

जिसके तहत दिल्ली सरकार ने बस चालकों के लिए आधार-आधारित ड्यूटी आवंटन लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रत्येक चालकों के लिए एकल ड्यूटी शिफ्ट सुनिश्चित हो सके। कोई भी ड्राइवर एक से ज्यादा शिफ्ट में ड्यूटी नहीं कर सके। कई शिफ्टों में काम करने वाले चालकों की निगरानी के लिए सभी डिपो में एक बायोमीट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। बस दुर्घटनाओं से बचने के लिए नशे में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण (शराब सेवन की जांच) किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ बस दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें बड़ी दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। गहलोत ने कहा कि इन मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसकी डिटेल रिपोर्ट अभी आनी है। मगर अभी प्राथमिक स्तर पर जो बात सामने आ रही है, उसमें पता चला है कि कुछ चालक डबल ड्यूटी भी कर रहे हैं, जिससे थकान होती है। दिल्ली में हो रहीं बस दुर्घटनाओं के पीछे यह भी एक कारण सामने आया है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में आतिशी फहराएंगी राष्ट्रीय ध्वज : आप

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिख कर कहा है कि 15 अगस्त को सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री आतिशी उनके स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी।

केजरीवाल वर्तमान में आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। आप ने कहा है कि केजरीवाल ने जेल से एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि आतिशी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगी। हर साल दिल्ली सरकार का स्वतंत्रता दिवस समारोह छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। हर साल केजरीवाल संबोधित करते रहे हैं। यह पहला साल होगा, जब केजरीवाल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उधर, केजरीवाल के पत्र की बात पर राजनिवास ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई भी पत्र उन्हें नहीं मिला है।

73 लाख मोबाइल कनेक्शन पुनर्सत्यापन में विफल रहने के कारण दूरसंचार कंपनियों द्वारा अब तक काटे गए हैं। संचार राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने के लिए अपने राज्यों के वित्त मंत्री से पूछें

आरोपों पर दिया जवाब ▶ लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को दिखाया आईना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी हटाने को लेकर जारी हंगामे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर विपक्ष के नेताओं को अपने-अपने राज्यों के वित्त मंत्री के पास प्रदर्शन करना चाहिए। उन्हें अपने राज्य के वित्त मंत्री से पूछना चाहिए कि वे जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जो 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है, उसमें से 50 प्रतिशत राजस्व सीधे तौर पर राज्यों को चला जाता है और केंद्र के 50 प्रतिशत राजस्व में से भी 41 प्रतिशत राज्यों के बीच वितरित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी का बड़ा हिस्सा राज्यों को ही जाता है, जिसमें कई राज्य गैर भाजपा शासित हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने इसके विरोध में सदन में प्रदर्शन किया था।

लोकसभा में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक पर हुई चर्चा के बाद जवाब देती हुईं। एएनआइ

बुधवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर अपने जवाब के दौरान सीतारमण ने कहा कि जीएसटी प्रणाली के लागू होने से पहले भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की खरीदारी पर टैक्स लगता था। लेकिन तब किसी सांसद ने अपने राज्य के वित्त मंत्री को इसे हटाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी और अब ये संसद में इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे एक मंत्री ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की मांग को लेकर पत्र लिखा और वह सार्वजनिक हो गया और विपक्ष इसे लेकर यह धारणा बनाने में जुटा है कि सरकार के बीच आपस में ही मतभेद है। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि जीएसटी काउंसिल में दो तिहाई राज्यों की तो एक तिहाई केंद्र की हिस्सेदारी है। ऐसे में राज्य इस मसले को गंभीरता से क्यों नहीं उठाते हैं। काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 31वीं, 37वीं और 47वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी और वे काउंसिल के समक्ष इस मुद्दे को जरूर रखेंगी।

पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की मांग पर भी गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारें कठघरे में

वित्त मंत्री सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में केंद्र की तरफ से कटौती की विपक्ष की मांग पर उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 के नवंबर में और फिर वर्ष 2022 के जून और उसके बाद इस साल मार्च में उत्पाद शुल्क में कटौती की, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकार ने राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को बढ़ा दिया। हिमाचल और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने-अपने राज्यों में वैट बढ़ा दिया। तमिलनाडु की सरकार ने भी चुनाव में वैट में कटौती का वादा किया था, लेकिन डीजल पर वैट में कोई कटौती नहीं की गई।

वित्त मंत्री बोलीं, केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब को उदार बनाया है

नई दिल्ली, एएनआइ : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं और व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया है। लोकसभा में वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले महीने पेश किए गए बजट में नई कर-फाइलिंग व्यवस्था में स्लैब को फिर से संशोधित किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए कोरोना के दौरान अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला। सरकार का नजरिया कराधान को सरल बनाना और करदाताओं पर बोझ कम करना है। विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से करदाताओं पर बोझ डालने के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती बढ़ा दी है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 के लिए संसद में पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री ने मानक कटौती 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने की घोषणा की थी। हालांकि यह नई व्यवस्था में आइटीआर भरने पर लागू होगी।

संसद प्रश्नोत्तर

एनपीएस से ओपीसी में बदलाव का समय बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना को फिर चुनने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा कि एक जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सभी नई भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए एनपीएस अनिवार्य है। केंद्र के कर्मियों के लिए 2003 में एनपीएस की शुरुआत की गई थी। कर्मियों द्वारा विकल्प चुनने की समय सीमा 31 अगस्त 2023 थी, जबकि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विकल्प की जांच और निर्णय के लिए समय सीमा 30 नवंबर, 2023 निर्धारित थी। उन्होंने कहा कि तीन मार्च, 2023 को जारी आदेश के संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जितेंद्र सिंह। फाइल

केंद्र को इस साल 14.41 लाख सार्वजनिक शिकायतें मिलीं

इस साल जनवरी से जुलाई के बीच केंद्र को लगभग 14.41 लाख सार्वजनिक शिकायतें मिलीं, जिनमें से 13.75 लाख का निपटारा किया गया। जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि कुल 66,060 सार्वजनिक शिकायतें लंबित है। 2024 में प्राप्त शिकायतों में पिछले वर्ष की 71,177 शिकायतें शामिल थीं। कोई भी व्यक्ति मंत्रालय, विभाग के लिए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल www.pgportal.gov.in पर सार्वजनिक शिकायतें दर्ज कर सकता है। मंत्री ने कहा कि 31 जुलाई 2024 तक 26,22,426 नागरिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

भारत ने अप्रैल-जुलाई में 2.6 लाख टन प्याज का निर्यात किया

भारत ने चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक 2.6 लाख टन प्याज का निर्यात किया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने चार मई, 2024 से प्याज पर प्रतिबंध हटा लिया है और 550 डालर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य तथा 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ निर्यात की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई, 2024 तक चालू वित्त वर्ष में कुल 2.60 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 16.07 लाख टन प्याज का निर्यात किया था।

उपभोक्ता अदालतों में रियल एस्टेट के 50,258 मामले लंबित

रियल एस्टेट से जुड़े 50,000 से ज्यादा मामले उपभोक्ता अदालतों में लंबित हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में बीएल वर्मा ने रियल एस्टेट से संबंधित उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों के विवरण की जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतों में 2,44,813 मामले दायर किए गए हैं। उनमें से 31 जुलाई 2024 तक 1,94,555 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और 50,258 मामले लंबित हैं।

कर्नाटक, हिमाचल, असम को बाढ़ राहत के रूप में सबसे अधिक धनराशि जारी

सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले दो वर्षों में एनडीआरएफ के तहत कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और असम को राहत और पुनर्वास के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक राज्यसभा को बताया कि 2022-24 में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित कर्नाटक के लिए 941 करोड़, हिमाचल और असम के लिए क्रमश : 873 करोड़ रुपये और 594 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। असम को 160 करोड़ रुपये जारी किए गए।

पीएम केयर्स फार चिल्ड्रेन पोर्टल पर प्राप्त 4,264 आवेदन खारिज

सरकार ने बुधवार को कहा कि पीएम केयर्स फार चिल्ड्रेन पोर्टल पर प्राप्त लगभग 4,264 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना के तहत अस्वीकृति का कारण गैर पात्रता को बताया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा को बताया कि 33 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के 613 जिलों से पीएम केयर्स फार चिल्ड्रेन पोर्टल पर 9,331 आवेदन पंजीकृत किए गए हैं।

पंजाब, बंगाल सहित चार राज्यों में अब तक लागू नहीं आरटीई कानून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **बच्चों की शिक्षा से जुड़े सवाल पर केंद्र ने राज्यसभा में दी जानकारी**

▶ **राज्यों से अपील, बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द करें लागू**

छह से चौदह साल की उम्र के सभी बच्चों को नजदीक के स्कूल में निश्शुल्क व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने से जुड़े आरटीई (राइट टु एजुकेशन) कानून को लागू हुए वैसे तो करीब 15 साल होने को हैं, लेकिन अभी भी पंजाब, बंगाल, केरल और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने इस कानून को नहीं अपनाया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। केंद्र ने राज्यों से अपील की है कि वह गरीब व कमजोर वर्गों के बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करें।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आरटीई को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस की ओर से सवाल पूछे गए थे। इस सवाल का जवाब पहले शिक्षा राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने दिया और बताया कि सभी बच्चों को हर हाल में स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए उसने आरटीई कानून भी बनाया है, लेकिन पंजाब, बंगाल, तेलंगाना और केरल इसे लागू नहीं कर रहे हैं। इससे गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल रहा है। जबकि इस कानून के तहत निजी स्कूलों में भी गरीब व कमजोर बच्चों के लिए प्रत्येक कक्षा में उसकी कुल क्षमता की कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। इस बीच सदन में हो-हल्ला भी हुआ। इसी मामले में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी एक पूरक प्रश्न किया। जिसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहा कि स्कूली शिक्षा का नामांकन दर प्राथमिक स्तर पर तो शत-प्रतिशत है। लेकिन जैसे-जैसे यह बड़ी कक्षाओं की ओर बढ़ता है, उनमें गिरावट आने लगती है।

इस दौरान स्कूलों में मनमानी फीस पर भी सदस्यों ने सवाल किए, जिसे राज्य का विषय बताते हुए उसे राज्यों के सामने रखने का सुझाव दिया। जयन्त चौधरी ने बताया कि देश के कई राज्यों ने इसे लेकर नियम बनाए भी हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान टोल की दरें पांच बार की गईं संशोधित : गडकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टोल संग्रह कुल 54,811.13 करोड़ रहा और यह वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले 1400 करोड़ रुपये अधिक था। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान टोल दरों को पांच बार संशोधित किया गया है। मंत्रालय ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर 6,523 करोड़ रुपये खर्च किए।

20 प्रतिशत जैव ईंधन का उपयोग करने लगेगा भारत का विमानन उद्योग : गडकरी ने यह भी बताया कि अगले पांच वर्षों के दौरान भारत का विमानन उद्योग 20 प्रतिशत जैव ईंधन का उपयोग करने लगेगा। इसकी शुरुआत पराली से होगी और किसानों को इसके लिए 2500 रुपये प्रति टन की दर मिलेगी। अब राजमार्ग मंत्रालय सड़कों के निर्माण में जैव-बिटुमिन का उपयोग कर रहा है, जिससे भारत को बिटुमिन के आयात को कम करने में मदद मिल रही है। जैव-बिटुमिन जैव-आधारित बाइंडर है जो फसल के ठूंठ जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है और इसका उपयोग पक्की सड़कों की सतहों को बांधने के लिए किया जाता है।

नई दिल्ली में बुधवार को राज्यसभा में बोलते नितिन गडकरी। प्रेट्र

35 प्रतिशत तक बायो-बिटुमिन मिश्रण की अनुमति देगी सरकार: गडकरी ने कहा कि सरकार पेट्रोलियम आधारित बिटुमिन (तारकोल) में 35 प्रतिशत तक लिग्निन के मिश्रण की अनुमति देगी, जिसका एक बड़ा हिस्सा अन्य देशों से आयात किया जाता है। बिटुमिन एक काला पदार्थ है जो कच्चे तेल के रिफाइन से प्राप्त होता है और इसका व्यापक रूप से सड़कों और छतों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। गडकरी ने राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 90 प्रतिशत सड़कें बिटुमिनस परतों का उपयोग कर रही हैं। 50 प्रतिशत बिटुमिन का आयात किया जाता है।

सरकार उत्तराखंड में भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध : चारधाम परियोजना पर चिंताओं के बीच गडकरी ने कहा कि सरकार तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करते समय और चीन सीमा तक भारी रक्षा उपकरणों के परिवहन के लिए सड़क का निर्माण करते समय भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का खयाल रखेगी। कुल 900 किमी लंबी चारधाम परियोजना में से केवल 150 किमी का निर्माण बाकी है। दूसरी ओर, कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण मणिपुर में राजमार्ग निर्माण कार्य में देरी हो रही है और मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना हटाने पर राज्यसभा में तीखी बहस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **मल्लिकार्जुन खरगे ने लगाया प्रस्तावना को हटाने का आरोप**

▶ **नड्डा ने किया खारिज, कहा- सुनी सुनाई बात पर सवाल उठाने के स्थान पर तथ्यों पर बात करनी चाहिए**

लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान एक मुद्दा बना था। कांग्रेस अभी भी किसी न किसी तरह इसे हवा देने की कोशिश में है। एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना हटाने के मुद्दे पर एक दिन पहले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया था यह गलत जानकारी फैलाई जा रही है। लेकिन, बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे फिर से उठाया और कहा कि पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तावना को फिर से जगह दी जाए। हालांकि, उनके इन आरोपों का सदन के नेता व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया। कहा कि सुनी सुनाई बात पर सवाल उठाने के स्थान पर तथ्यों पर बात करनी चाहिए। संविधान का जितना आदर मोदी सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस ने तो संविधान पर 1975 में डाका डाला। 19 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। इस दौरान सदन में जमकर शोर-शराबा हुआ।

मल्लिकार्जुन खरगे

जेपी नड्डा

राज्यसभा में इस विवाद की शुरुआत सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हो गई। खरगे ने पाठ्य पुस्तकों से संविधान का प्रस्ताव हटाने के आरोपों के साथ ही बाबासाहेब की प्रतिमा हटाने और आरएसएस को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। नड्डा ने अपनी बारी में इस पर जवाब दिया और कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। आपकी सरकार ने तो दो बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। मीसा के तहत लोगों को जेल में डाला, लेकिन संघ हर बार उतना ही मजबूत होकर निकला। इस बीच, सभापति ने खरगे से उनके आरोपों का आधार जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी जानकारी मिली है। इस पर सभापति ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि बगैर प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है।

यह विवाद यहीं नहीं थमा। सदन में जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होने वाला था, उससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सदन में पहुंचे। उन्होंने इस मुद्दे पर सभापति से अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। साथ ही बताया कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है, वह पूरी तरह से गलत है। एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। राष्ट्रगान और संविधान की प्रस्तावना दोनों को ही एनईपी की सिफारिशों की तरह पाठ्य पुस्तकों में उचित स्थान दिया गया है।

गोयल ने बिम्सटेक देशों को प्रस्तावित एफटीए पर पुनर्विचार का दिया सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिम्सटेक के सातों सदस्य देशों को मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की प्रगति पर पुनर्विचार करने का बुधवार को सुझाव दिया। वार्ता काफी धीमी गति से जारी है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते के बजाय अधिमान्य व्यापार समझौते पर बातचीत करने के बारे में सोच सकते हैं। बिम्सटेक बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों को एक साथ लाता है। यह दक्षिण एशिया के पांच देशों (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका) और दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों (म्यांमार और थाइलैंड) को जोड़ता है। यह समूह 2004 से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत कर रहा है। अभी तक 20 से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है। 2018 में आखिरी बातचीत हुई थी।

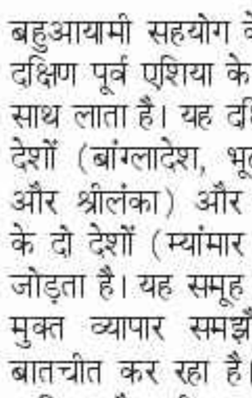

पीयूष गोयल। फाइल

नए सेवा गुणवत्ता मानदंडों पर पुनर्विचार से ट्राई का इन्कार

▶ **कंपनियों को सेवा बाधित होने पर उपभोक्ताओं को देना होगा मुआवजा**

▶ **प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा न करने पर जुर्माना अब एक लाख रुपये**

नई दिल्ली, प्रेट्र: दूरसंचार नियामक ट्राई ने नए सेवा गुणवत्ता मानदंडों पर पुनर्विचार की संभावना से बुधवार को इन्कार कर दिया। इन मानदंडों के तहत दूरसंचार कंपनियों को सेवा बाधित होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। ट्राई ने नए नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि ये मानदंड गहन परामर्श और उचित विचार-विमर्श के बाद जारी किए गए हैं। लाहोटी ने ब्राडबैंड इंडिया फोरम (बीआइएफ) द्वारा आयोजित इंडिया सैटकाम 2024 से इतर कहा, 'हमने इस प्रक्रिया पर बहुत गहन विचार किया है, मानदंड गहन परामर्श तथा समुचित विचार के बाद जारी किए गए। इन्हें उस सेवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया, जो ग्राहक को मिलनी चाहिए तथा जिसे सेवा प्रदाता को प्रदान करना चाहिए।' लाहोटी ने कहा कि ट्राई को उम्मीद है कि सेवा प्रदाता अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत करेंगे ताकि उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता वाली सेवा मिल सके।

अनिल कुमार लाहोटी। फाइल

अवांछित काल पर अंकुश के लिए नियमनों को मजबूत बनाएगा ट्राई : ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा है कि नियामक अवांछित काल पर अंकुश लगाने के लिए नियमों की समीक्षा करेगा और उन्हें मजबूत बनाएगा। ट्राई के एजेंडे में अवांछित काल पर कार्रवाई करना शीर्ष पर है। अनधिकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों से अनचाहे संचार के बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बीच नियामक इस मुद्दे पर अपना सख्त रुख अपना रहा है। ट्राई ने मंगलवार को एक बैठक आयोजित कर सेवा प्रदाताओं और उनकी टेलीमार्केटिंग कंपनियों को कड़ा संदेश दिया कि वे वायस काल का उपयोग कर बड़े पैमाने पर संचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। कार्रवाई के तौर पर नियामक ने सभी हितधारकों, विशेष रूप से एक्सेस सेवा प्रदाताओं (दूरसंचार कंपनियों) और उनके डिलिवरी टेलीमार्केटर्स से सक्रिय कार्रवाई करने की मांग की है। तत्काल कार्रवाई के तहत पहचान के लिए तकनीकी समाधान लागू करना और 10 अंक वाले नंबर का उपयोग करके उद्यम ग्राहकों द्वारा 'एक साथ कई काल' को रोका जाएगा।

नए पाठ

तीसरी और छठी कक्षा के लिए एनईपी के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकें की गईं जारी, इसी सत्र से इन किताबों को पढ़ सकेंगे बच्चे, अन्य कक्षाओं की किताबें भी जल्द

अब बच्चे पढ़ेंगे चंद्रयान सहित देश पर गर्व करने वाली कहानियां

अरविंद पांडेय • जागरण

▶ **बाकी अन्य कक्षाओं की किताबें भी दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लाई जाएंगी**

▶ **आने वाली पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का काम अंतिम चरण में**

नई दिल्ली : बच्चों को पढ़ाई के दबाव से निकालने और उन्हें खेल-खेल में पढ़ाने का जो सपना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के जरिये देखा गया था, अब वह आकार लेने लगा है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर तीसरी और छठी कक्षा के लिए एनईपी के तहत नई पाठ्य पुस्तकें बाजार में उतार दी गई हैं। उसमें बच्चों को चंद्रयान अभियान से जुड़ी रोचक कहानी से लेकर देश पर गर्व करने वाली कविताएं, जीवन मूल्यों और पारिवारिक जुड़ाव को बढ़ाने वाले पाठ के साथ भारत को अच्छी तरह से जानने-समझने वाली विषय वस्तु पढ़ने को मिलेगी।

एनईपी के तहत हालांकि अभी सिर्फ तीसरी व छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही तैयार होकर आई हैं। बाकी अन्य कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें भी चरणबद्ध तरीके से अगले दो वर्षों में लाई जानी हैं। एनसीईआरटी की मानें तो इनमें से सभी किताबों को तैयार करने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इस बीच, जिन दो कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें सामने आई हैं, उसमें तीसरी कक्षा के गणित विषय की पाठ्य पुस्तक सबसे रोचक है। जिसका नाम 'गणित मेला' दिया गया है। वह बच्चों के कौतूहल को ठीक वैसे ही बढ़ाने वाली है, जैसे मेले में बच्चे हर खिलौने को देखकर इतराने लगते हैं। इनमें वैसे तो 14 पाठ हैं, लेकिन प्रत्येक पाठ का नाम रोचक है।

एनईपी पर अमल को बढ़ते कदम। प्रतीकात्मक

भारत को क्यों इंडिया नाम दिया गया

भारत और इंडिया नाम को लेकर अब अक्सर राजनीति होती रहती है। ऐसे में छठी कक्षा के सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी ने 'इंडिया, दैट इज भारत' नाम से एक पाठ रखा गया है। इसमें बताया गया है कि देश का प्राचीन नाम क्या था। साथ ही देश का इंडिया नाम कैसे विदेशी लोगों ने रखा। इसके साथ ही इनमें देश की संस्कृति और इसके इतिहास की भी पूरी जानकारी दी गई है।

पहले पाठ का नाम है 'नाम में क्या है' तो वहीं अन्य पाठों के नाम दोहरा शतक, नानी मां के साथ छुट्टियां, कुछ लेना कुछ देना, सूरजकुंड मेला जैसे नाम हैं। इतना ही नहीं, तीसरी कक्षा के बच्चों को चंद्रयान मिशन की कहानी को जिस अंदाज में परोसा गया है, वह बच्चों के मन-मस्तिष्क पर सदैव के लिए छप जाने वाली है।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, एनसीईआरटी की तीसरी और छठी कक्षा की सभी पाठ्य पुस्तकें बाजार में आ गई हैं। जिन्हें छात्र इस सत्र से ही पढ़ सकते हैं। राज्यों को भी इन पाठ्य पुस्तकों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। गौरतलब है कि स्कूलों के लिए नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का काम जुलाई 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जाने के बाद शुरू किया गया था।

उल्लेखनीय है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनिवार्य स्कूली शिक्षा को 6-14 वर्ष की उम्र सीमा से बढ़ाकर 3-18 वर्ष तक बढ़ाती है। एनईपी में स्कूली पाठ्यक्रम में 3-6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए पहले से गैर-मान्यता प्राप्त प्री-स्कूलिंग के तीन साल शामिल हैं। नई शिक्षा प्रणाली में 12 साल की औपचारिक शिक्षा और तीन साल की आंगनवाड़ी/पूर्व-स्कूल शिक्षा का प्रविधान शामिल है।

****

कह कर रहेंगे माधव जोशी

चुनाव आयोग आज जम्मू-कश्मीर दौरे पर, चुनाव से पहले हालात का लेगा जायजा

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर

चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का बहुप्रतिक्षित दौरा वीरवार से शुरू हो रहा है। अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान आयोग पहले कश्मीर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात कर हालात का जायजा लेगा, फिर वह जम्मू पहुंच कर सुरक्षा परिदृश्य की संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा करेगा। स्थानीय राजनीतिक दल भी आयोग के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। उम्मीद है कि यह दौरा जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा। चुनाव आयोग का दौरा पहले तीन दिन का था, लेकिन अब यह दो दिन तक ही सीमित रहेगा।

बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंतिम बार विधानसभा चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य थे। पांच अगस्त 2019 को संसद में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार सुबह 10 बजे श्रीनगर पहुंचेगा। दोपहर दो बजे तक वह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से और उसके बाद जिला उपायुक्तों व एसएसपी के साथ बैठक करेगा। देर शाम गए करीब सात बजे जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के नोडल अधिकारी से मुलाकात करेगा। शुक्रवार सुबह आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात करने के बाद जम्मू रवाना होंगे।

दो दिवसीय दौरा

- श्रीनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से और उसके बाद उपायुक्तों-एसएसपी के साथ बैठक
- जम्मू में सुरक्षा परिदृश्य की संबंधित अधिकारियों के साथ होगी चर्चा
- स्थानीय राजनीतिक दल भी आयोग के दौरे को लेकर उत्साहित

क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टी के नेता

अपने पक्ष से अवगत कराएंगे नेंका

उमर अब्दुल्ला।

चुनाव आयोग के साथ अपना पक्ष रखने के लिए नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक की। नेकां प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और हम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उसे अपने पक्ष से अवगत कराएंगे।

दौरे से पहले पीडीपी ने की बैठक

महबूबा मुफ्ती।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक की है। पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने कहा कि अब बहुत हो गया, चुनाव का एलान होना चाहिए। चुनाव आयोग को अब यहां विधानसभा चुनाव

जल्द चुनाव कराए जाएं : कांग्रेस

रविंद्र शर्मा

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि हमारा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव का एलान करे।

सुरक्षा को देख निर्णय होगा : भाजपा

अल्ताफ अहमद।

भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ अहमद ठाकुर ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि यहां जल्द चुनाव हों। अंतिम फैसला तो चुनाव आयोग को ही लेना है। वह यहां के सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे।

विधानसभा चुनाव नेशनल कान्फ्रेंस किसी पार्टी से नहीं करेगा गठबंधन : फारूक

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर : नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस एलान से किसी को कोई ठेस पहुंची हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस को जरुर पहुंची होगी, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जम्मू प्रांत की 43सीटों में से लगभग 30 सीटों पर नेशनल कान्फ्रेंस से समर्थन की उम्मीद बांधे हुए है। बदले में वह कश्मीर की 47 सीटों में 30 सीटों पर नेशनल कान्फ्रेंस के समर्थन में अपना कोई उम्मीदवार न उतारने के मूड में थी। लोस चुनाव में कांग्रेस-नेशनल कान्फ्रेंस के बीच गठजोड़ रहा है।

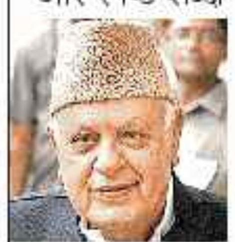
फारूक अब्दुल्ला।

राज्यसभा की 12 सीटों के लिए तीन सितंबर को होगा चुनाव

- चुनाव अयोग के अनुसार, बिहार, महाराष्ट्र और असम में दो-दो सीटों पर होंगे चुनाव
- हरियाणा, मप्र, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की एक-एक सीटों पर चुनाव

नई दिल्ली, प्रेट्र: चुनाव आयोग ने नौ राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान कर दिया है। बुधवार को आयोग की घोषणा के अनुसार, उपचुनाव तीन सितंबर को होंगे। 10 सीटें राज्यसभा सदस्यों के लोकसभा चुनावों में निर्वाचित होने से खाली हुई थीं, जबकि दो अन्य रिक्तियां राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से हुई हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, उपचुनाव की अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी, जबकि नामांकन 21 अगस्त तक होगा। 22 अगस्त को नामांकन-पत्रों की जांच होगी। 27 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

आयोग की ओर से कहा गया है कि जरूरी हुआ तो तीन सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम में मतगणना भी होगी। उपचुनाव छह सितंबर से पहले संपन्न हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि जो राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनावों में चुनकर आए हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (महाराष्ट्र), दीपेंद्र सिंह हुडा (हरियाणा), ज्योतिरादित्य सिंधिया (मध्य प्रदेश) और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल (राजस्थान) शामिल हैं। बिहार से लोकसभा चुनाव जीतने वालों में राजद की मीसा भारती और भाजपा के नवादा से सांसद विवेक ठाकुर तो असम से कामाख्या प्रसाद तासा और सर्बानंद सोनोवाल हैं। इनके अलावा त्रिपुरा से बिप्लब कुमार देब भी लोकसभा चुनाव जीतने वालों में शामिल हैं। इनके अलावा बीआरएस सांसद के.केशव राव ने पांच जुलाई को और बीजद सांसद ममता मोहंता ने 31 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। रिकेवल बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग मतपत्र पर वरीयताओं को चिह्नित करने के लिए किया जा सकेगा। जिन 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें असम की दो, बिहार की दो, महाराष्ट्र की दो और हरियाणा, मप्र, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना व ओडिशा की एक-एक सीट शामिल है।

प्रतीकात्मक

खरगे-राहुल ने महाराष्ट्र की चुनावी तैयारियों पर उद्धव से की मंत्रणा

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, अवसरवादी गठबंधन से परेशान महाराष्ट्र की जनता चाह रही बदलाव

चुनावी मुद्दों से लेकर रणनीति पर हुई बात, संकेत साफ महाविकास आघाड़ी का चेहरा रहेंगे उद्धव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करते शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे। प्रेट्र

लोकसभा चुनाव में मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए ने अब अगले कुछ महीनों के दौरान चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा-राजग को थामने की कसरत तेज कर दी है। इस क्रम में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चुनावी रणनीति पर बातचीत की। विपक्षी नेताओं ने इस बैठक में महा विकास आघाड़ी गठबंधन के एकजुट होकर चुनाव लड़ने और भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को शिकस्त देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सीट बंटवारे पर जल्द आपसी सहमति बनाने की बात कही। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी की मौजूदगी में शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की खुद ही पुष्टि की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'महाराष्ट्र के किसान और नौजवान अवसरवादी भाजपा गठबंधन से परेशान हैं। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता बदलाव की ओर देख रही है।' कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ उद्धव की इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने किसानों के मुद्दे, महाराष्ट्र की बड़ी विकास परियोजनाओं को गुजरात ले जाने से लेकर प्रदेश की दूसरी ज्वलंत समस्याओं पर भाजपा को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव सितंबर-अक्टूबर तक कराए जाने हैं और चुनाव आयोग आने वाले दिनों में इसकी घोषणा करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने की समय सीमा तय कर रखी है। वहीं, झारखंड में वर्ष के आखिर में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यह लगभग तय है कि महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में जाएगा। कांग्रेस ने भले ही लोकसभा चुनाव में राज्य में सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती हों, मगर विपक्षी गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए शिवसेना (यूबीटी) को नेतृत्व देने से उसे गुरेज नहीं है। इस लिहाज से माना जा रहा कि उद्धव महाविकास आघाड़ी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे।

प्रकाश आंबेडकर ने ओबीसी कोटे के तहत मराठा आरक्षण का किया विरोध

राज्य ब्यूरो, मुंबई : वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे के तहत मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 'निजामी मराठा' ओबीसी के लिए निर्धारित कोटा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जालना में अपनी 'आरक्षण बचाओ यात्रा' के तहत आयोजित एक जनसभा में उन्होंने कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ओबीसी को ऐसी साजिशों को विफल करना चाहिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने फरवरी में एक कानून बनाकर मराठा समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण का कोटा प्रदान किया है। कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल सहित अन्य ओबीसी नेता भी पिछड़े समुदायों के लिए मौजूदा कोटे को कम करने का विरोध कर रहे हैं। जबकि मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र के संपूर्ण मराठा समाज को कुनबी (खेती करनेवाला मराठा) का दर्जा देकर उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। जरांगे पाटिल अपनी मांग को बल देने के लिए आजादी से पहले निजाम हैदराबाद द्वारा अपने क्षेत्र में मराठों को कुनबी का दर्जा दिए जाने का उल्लेख कर रहे हैं।

प्रकाश आंबेडकर।

राज्यसभा चुनाव : सिंघवी की याचिका पर सुनवाई अब 21 अगस्त को

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला

भाजपा से राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 21 अगस्त को होगी। मंगलवार को न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में बराबर मत मिलने के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले परिणाम को चुनौती दी है। सांसद हर्ष महाजन ने इस चुनाव याचिका में जरूरी पक्षकारों को प्रतिवादी न बनाए जाने को गंभीर त्रुटि बताते हुए खारिज करने की मांग की है। सांसद के अनुसार चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाए बगैर यह याचिका मान्य नहीं है। प्रार्थी सिंघवी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजेता घोषित कर दिया।

अभिषेक मनु सिंघवी। फाइल

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 27 फरवरी को हुए चुनाव में 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में महाजन व सिंघवी को 34-34 मत मिले थे। पर्ची सिंघवी के नाम की निकली थी, लेकिन महाजन को विजयी घोषित किया गया। पर्ची निकलने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की पर्ची निकली, उसकी जीत होनी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत दूसरे उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया, जो कानूनी रूप से गलत है। इनको आधार बनाते हुए याचिका दायर की है।

अब हरियाणा की जनता के पास सशक्त विकल्प के रूप में है आप : भगवंत मान

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी

- दादरी में आप की बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए
- कहा-पंजाब -हरियाणा छोटे-बड़े भाई हैं, हम एक ही पानी पीते हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को दादरी में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के लिए प्रदेश की जनता से समर्थन मांगा। भगवंत मान ने कहा कि हम आम घरों से निकले हुए लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से जब आम आदमी पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी बनाते हैं जिसमें आम घरों के बेटे बेटियां हों। क्योंकि दूसरी पार्टियों में विधायक, मंत्री और नेताओं के बेटे, बेटियां और रिश्तेदार ही शामिल थे। उन्होंने कहा कि यदि 75 साल की आजादी के बाद भी जनता का ये हाल है तो कहीं न कहीं सिस्टम की गलती है। इसमें जनता का कोई दोष नहीं था। क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। अब हरियाणा की जनता के पास एक मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी है। भगवंत मान ने कहा कि 44295 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं। यदि किसी ने एक रुपए की भी रिश्वत ली हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिसने चुनाव से दो महीने पहले बोला कि दिल्ली वालों अगर मेरे काम से संतुष्टि है तो मुझे वोट दे देना नहीं तो मत देना। ये वही कह सकता है जिसने काम किया हो। भाजपा ने उस व्यक्ति को जेल में डाल रखा है जिसने जनता के लिए काम किया। जिस दिन अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ उस दिन जन्माष्टमी थी। भगवान उनसे कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं। यदि नौकरी किसी को दोगे नहीं, जनता पर हड़ताल करने पर लाठियां और गोलियां चलाओगे और विपक्ष के नेताओं को अंदर करते जाओगे तो फिर हेलीकाप्टर में भागना पड़ता है। उन्होंने कहा पीएम मोदी कह रहे थे कि हरियाणा में डबल इंजन की जरूरत है। जब इंजन लगा दिया था तो इंजन क्यों बदल दिया। क्या मनोहर लाल वाला इंजन खराब हो गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं। हम एक ही पानी पीते हैं। हमारे दुख सुख सांझे है। हमारी फसलें, मुसीबतें और रिश्तेदारियां सांझी है। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पूरी दुनिया हिला दी है और जिनका नाम एक इमानदार के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। उसको इस बार हरियाणा में भी लाएं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि चरखी दादरी की धरती खिलाड़ियों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। यहां लड़ने वालों में संघर्ष का जबरदस्त जज्बा है। उन्होंने कहा आप लोगों ने हर पार्टी को वोट देकर देख लिया। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, एक भी मुद्दे पर काम नहीं हुआ। दस साल से भाजपा की सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में विस चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। टिकट वितरण से लेकर रणनीति तैयार करने के लिए बैठकों को दौर शुरू हो गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जागरण

18 महीने का डीए का एरियर नहीं देने पर अखिलेश ने केंद्र को घेरा

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

- सपा मुखिया ने पूछा-कहां जा रहा जीएसटी संग्रह का पैसा?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) का 18 माह का एरियर नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने केंद्र सरकार से पूछा कि लगातार बढ़ते जीएसटी संग्रह और कई ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का पैसा कहां जा रहा है? कटाक्ष किया कि अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा हैं, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं हैं। अखिलेश ने बयान जारी कर सवाल किया कि सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले? केंद्र सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर देने से मना करना, एक तरह से सरकारी गारंटी से इन्कार करना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई का बढ़ना, दूसरी तरफ महंगाई भत्ता न मिलना, सीमित आय वाले कर्मचारियों पर दोहरी मार है। घर की चिंता जब सिर पर हावी होगी तो कार्य क्षमता पर असर होगा और खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में मिलने वाली रियायत को बंद कर दिया गया है। भाजपा सरकार बुजुर्गों की भी सगी नहीं है। उनकी दवा के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन पेंशन नहीं। सरकार क्या यह चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए अनशन करें?

अखिलेश यादव। फाइल

कांग्रेस आंदोलन और संघर्ष के रास्ते संसद तक का सफर तय करेगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- कांग्रेस सेवादल पश्चिमी जोन के तीन दिवसीय प्रशिक्षण का समापन

उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवादल पश्चिमी जोन के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राष्ट्र के प्रति त्याग और निष्ठा के बलबूते कांग्रेस और सेवादल ने एक सदी का सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से मजबूत इरादों वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयार कर हम आंदोलन और संघर्ष के रास्ते प्रदेश और देश की सत्ता पर काबिज होकर देश-प्रदेश का उद्धार करेंगे। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व से सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। इससे साबित होता है वह दिन दूर नहीं जब भाजपा सड़क पर होगी और कांग्रेस सांसद में होगी। उन्होंने स्वयंसेवकों के बारे में कहा अब स्वयं सेवकों के जत्थे बनाकर प्रभात फेरी और ध्वज वंदन के माध्यम से नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास तेज करना होगा। पूर्व मंत्री दीपा कौल ने कांग्रेस की विरासत अनुसरण स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को आत्मसात करने की बात की। भारत और भारतीयता के अनुसरण करते हुए बिखरते हुए समाज को जोड़ना और बचाने की जिम्मेदारी में कांग्रेस सेवा दल की विशेष भूमिका है। शिविर का आरंभ ध्वज रक्षक सुशील तिवारी सोनू ने शारीरिक व्यायाम और परेड कक्षा के बाद राष्ट्रगान से शिविर का समापन हुआ। सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष डा. प्रमोद पांडे, अनिल देव त्यागी, अजय शुक्ला, डा. संजीव शर्मा, जुबैर खां, रिजवान, पारस शुक्ला, बिजेंद्र यादव, मांगेराम त्यागी, विनीत त्यागी, लेखराज त्यागी, डाली शर्मा, दिनेश कौशिक, प्रेम प्रकाश चीनी, सतीश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जागरण

गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, खैर और मंझवा पर कांग्रेस का दावा मजबूत : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी संगठन और पार्टी कार्यकर्ता तैयार हैं। सपा के साथ गठबंधन में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर गाजियाबाद के अलावा मीरापुर, फूलपुर, खैर और मंझवा पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। जिसमें अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान लेगा। उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी सपा के साथ गठबंधन में मजबूती के साथ उतारेगी। अभी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

प्रवचन नहीं चंद्रयान 2 की लांचिंग देख रहे थे पीएम

विश्वास.News क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें उन्हें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को बड़ी स्क्रीन पर ध्यान से सुनते हुए दिखाया गया है। इंटरनेट मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे सच मानकर प्रसारित कर रहे हैं।

पड़ताल: विश्वास न्यूज ने प्रसारित पोस्ट की जांच के लिए सबसे पहले वीडियो के कई कीफ्रेम्स निकाले। फिर इन्हें गूगल लेंस टूल के जरिये सर्च किया। हमें एएनआइ और दूरदर्शन पर असली वीडियो मिला। इसे 22 जुलाई, 2019 को अपलोड किया गया था। इसमें बताया गया कि पीएम मोदी ने चंद्रयान 2 की लांचिंग देखी। वीडियो में पीएम मोदी को चंद्रयान-2 की लांचिंग को देखते हुए देखा जा सकता है। गूगल ओपन सर्च टूल से सर्च करने पर भी हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिससे यह पुष्टि हो सके कि पीएम मोदी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का प्रवचन सुना हो।

निष्कर्ष : विश्वास न्यूज की जांच में पता चला कि प्रसारित वीडियो एडिटेड है। इसे एडिटिंग साफ्टवेयर के जरिये तैयार किया गया है। इसमें अलग से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की क्लिप को जोड़ा गया है। असली वीडियो में पीएम मोदी चंद्रयान-2 की लांचिंग का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे।

क्या हो रहा है प्रसारित

फेसबुक यूजर कुणाल गुटगुटिया ने 27 अगस्त को एक वीडियो को पोस्ट किया। इसके साथ लिखा, 'अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं 3 काम करता।' वीडियो में पीएम मोदी को एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़े दिखाया गया है। स्क्रीन पर अनिरुद्धाचार्य का प्रवचन चलते हुए देखा जा सकता है।

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

बंगाल के राज्यपाल व ममता सरकार में टकराव बढ़ा

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- राज्यपाल बोस ने लगाया आर्थिक अराजकता का आरोप, आंदोलन की तैयारी में तृणमूल

बंगाल के राज्यपाल डाक्टर सीवी आनंद बोस व ममता बनर्जी की सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन के बाद राज्यपाल बोस ने बंगाल सरकार को हिदायत देते हुए कहा है कि विभिन्न विषयों को लेकर जो तथ्य मांगे गए हैं, वे नहीं दिए जाने पर उन्हें 'दूसरा रास्ता' अपनाना पड़ेगा। राज्यपाल ने बंगाल में आर्थिक अराजकता का आरोप लगाते हुए इसे लेकर श्वेतपत्र जारी करने की भी मांग की है।

दूसरी तरफ बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राज्यपाल बोस के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है। लोकसभा में तृणमूल के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने कहा कि विरोधी दलों के गठबंधन आइएनडीआइए के साथ अगले दो-तीन दिनों में बातचीत करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मालूम हो कि राज्यपाल बोस ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार संवैधानिक तरीके से काम कर रही है अथवा नहीं, यह देखना राज्यपाल का काम है। बंगाल सरकार के आर्थिक क्रियाकलापों में अनियमितताएं हैं। रिजर्व बैंक और कैग की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। बंगाल में आर्थिक अराजकता व्याप्त है। इसे लेकर श्वेतपत्र जारी किया जाना चाहिए। मालूम हो कि इससे पहले बंगाल के पूर्व राज्यपाल व वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बंगाल सरकार द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आए निवेश प्रस्तावों पर श्वेत पत्र लाने की मांग की थी।

****

800 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित ड्रग्स मेफेड्रोन जब्त की गुजरात एटीएस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक विनिर्माण इकाई पर छापा मारकर। पांच और छह अगस्त को किए गए कार्रवाई में एटीएस ने चार लोगों को पकड़ा।

विनेश फोगाट को लेकर राजनीति गर्म, केंद्र ने बताया तैयारी पर खर्च किए 70 लाख रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम ने विनेश का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें चैंपियन करार दिया
- खेल मंत्री के वक्तव्य के बावजूद विपक्ष का संसद से वाकआउट

संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते खेल मंत्री मनसुख मांडविया। एएनआइ

ओलिंपिक में स्वर्ण पदक के करीब पहुंचकर वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित हुई विनेश फोगाट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भारत का दिल तोड़ दिया। लेकिन राजनीति में विनेश के साथ एकजुटता दिखाने के बजाय जंग छिड़ गई। विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से इसमें साजिश की बात करते हुए जांच की मांग की गई। वह भी ठीक था। लेकिन, हालात ऐसे बने कि सरकार की ओर से बयान पर विरोध दर्ज कर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा से वाकआउट कर दिया।

इससे पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय ओलिंपिक संघ ने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही जहां एक्स पर पोस्ट कर विनेश का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें चैंपियन करार दिया था, वहीं भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से फोन पर बात कर हर कदम उठाने को कहा था। इस पर लगभग 70 लाख रुपये खर्च हुए। बहरहाल, मांडविया जब बयान दे रहे थे, तभी विपक्षी सदस्यों ने खड़ा होकर विरोध करना शुरू कर दिया। महिला पहलवानों के साथ सरकार के पहले के व्यवहार का जिक्र करते हुए नारेबाजी करने लगे। मांडविया ने विनेश को आर्थिक सहायता के साथ उनके लिए फिजियो ट्रेनर अश्विनी पाटिल और हंगरी के एक्सपर्ट कोच वोलेर अकोस को नियुक्त किया गया था। व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई।

सूरजेवाला बोले, सांत्वना ट्वीट से नहीं चलेगा काम

खेल मंत्री ने बताया कि विनेश को स्पेन में ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने के लिए आर्थिक मदद दी गई। तीन से 13 जुलाई तक मैड्रिड के इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया। प्री ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए केंद्र के खर्च पर फ्रांस भेजा गया। इसके पहले हंगरी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ की सीरीज में भी विनेश की भागीदारी का सारा खर्च सरकार ने जुटाया। बाद में 13 से 16 जुलाई तक हंगरी में चौथी रैंकिंग सीरीज में भी भेजा गया। टार्गेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम के तहत उन्हें कुल 53 लाख 35 हजार रुपये और एसीटीसी के लिए 17 लाख 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के दौरान भी उन पर एक करोड़ 13 लाख 294 रुपये खर्च किए गए थे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे विपक्ष ने विनेश फोगाट के लिए न्याय की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा से वाकआउट किया। मोदीजी ने एक सांत्वना ट्वीट किया। सांत्वना ट्वीट से काम नहीं चलेगा मोदीजी। उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विपक्षी सांसदों ने 'विनेश फोगट के खिलाफ साजिश बंद करो' और 'हमें उनके लिए न्याय चाहिए' जैसे नारे लगाए।

ओडिशा में अपनी शिकायत लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा पाएंगे सरकारी कर्मचारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

मोहन मांझी। फाइल

जारी की गई अधिसूचना, समस्या का समाधान नहीं मिलने पर ही जा सकेंगे कोर्ट

ओडिशा सरकार में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अब सीधे कोर्ट नहीं जा पाएंगे। यदि कोई कर्मी ऐसा करता है तो उसे ओडिशा सरकारी सेवक आचरण नियम-23 का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही सरकार ऐसे मामलों में अदालत से उसकी याचिका निरस्त करने का अनुरोध करेगी। लोक प्रशासन और लोक शिकायत विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार किसी भी समस्या के समाधान के लिए कर्मचारियों अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत करानी होगी। इसके बाद उनकी शिकायत विभागीय प्रमुख के पास भेज दी जाएगी। अगर संबंधित अधिकारी 30 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो यह स्वतः निदेशालय और इसके बाद सचिवालय स्तर पर पहुंच जाएगी। सभी स्तर पर समस्या के समाधान के लिए 30-30 दिनों की अवधि निर्धारित होगी। अगर इन स्तरों से गुजरने के बाद भी संबंधित कर्मचारी को न्याय नहीं मिलता है तो उनकी शिकायत मुख्यमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ में चली जाएगी। कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेकर मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। अगर फिर भी न्याय नहीं मिला तो वे कोर्ट जा सकते हैं।

राजस्थान में सरकारी कार्यों में जूम एप के उपयोग पर रोक

जासं, जयपुर : राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने जूम एप के माध्यम से होने वाली सरकारी बैठकों को असुरक्षित माना है और सरकारी कार्यों में इस एप के उपयोग पर रोक लगा दी है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी साइबर मामलों में आवश्यक दिशा-निर्देश के तहत ऐसा किया गया है।

आदेश को चुनौती देने के लिए पूजा खेडकर को कैट के पास जाना होगा : हाई कोर्ट

नई दिल्ली: उम्मीदवारी रद करने के आदेश को चुनौती देने के लिए पूर्व आइएएस पूजा खेडकर को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के पास जाना होगा। यह कहने के साथ ही हाई कोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा कर दिया। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को सूचित किया कि दो दिन में पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद करने के आदेश के बारे में सूचित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि पूजा खेडकर ने अपनी चुनौती के साथ कैट से संपर्क क्यों नहीं किया, जिस पर खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि चूंकि उन्हें यूपीएससी की ओर से आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। इस पर यूपीएससी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील नरेश कौशिक ने कहा कि आयोग की ओर से आदेश दो दिन के अंदर खेडकर को उनकी ईमेल आइडी के साथ-साथ उनके अंतिम ज्ञात पते पर भेज दिया जाएगा।

न्यूज गैलरी

छत्तीसगढ़ में गांव को घेरकर 10 गो तस्करों को पकड़ा

जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ में जशपुरनगर जिले के साईटांगर टोली गांव में पुलिस ने बुधवार तड़के 10 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। दंगारोधी दल के साथ जिला पुलिस की टीम ने गांव को चारों ओर से घेर कर अभियान चलाया। मवेशी तस्करों के कब्जे से 14 वाहन जब्त किए गए, जबकि 39 गोवंशीय पशुओं को संरक्षित किया गया। बता दें कि जशपुरनगर जिला पुलिस ने बीते सात माह में 39 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 340 गोवंशीय पशुओं को उसे मुक्त कराया गया। (नईदुनिया)

बीआरएस नेता रामा राव के खिलाफ मामला दर्ज

हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के खिलाफ जयशंकर भूपालपल्ली जिले में मेडीगड्डा बैराज के हाल के दौरे के दौरान बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर मामला दर्ज किया गया है। रामा राव की अगुआई में बीआरएस नेताओं के एक दल ने कांग्रेस सरकार को बेनकाब करने व तथ्यों से अवगत कराने के लिए कालेश्वरम सिंचाई परियोजना के तहत 26 जुलाई को बैराज का दौरा किया था। (प्रेट्र)

गुजरात में कुएं में गिरने से शेरनी की मौत

बोटाद: गुजरात के बोटाद जिले के इटारिया गांव में कुएं में गिरने से एक शेरनी की मौत हो गई। रेंज वन अधिकारी (गढ़दा) आइएस प्रजापति ने कहा कि घटना मंगलवार रात को हुई और बुधवार सुबह इसकी सूचना मिलने के बाद वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शेरनी के शव को कुएं से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए पशु देखभाल केंद्र भेज दिया गया। (प्रेट्र)

बसपा नेता हत्याकांड में एक और गिरफ्तार

चेन्नई: तमिलनाडु में पिछले महीने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की नृशंस हत्या के आरोप में 32 वर्षीय एन अश्वथमन गिरफ्तार किया गया है। आरोपित शहर के व्यासरपाडी का निवासी है। इस मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को उस समय मार गिराया था, जब भागने की कोशिश की थी। (प्रेट्र)

कोच्चि हवाई अड्डे पर बम की झूठी धमकी से उड़ान में देरी

कोच्चि: केरल के कोच्चि हवाई अड्डे पर बुधवार को एक यात्री ने सुरक्षा जांच के दौरान बम होने की धमकी दी, हालांकि यह मात्र अफवाह निकली। इससे थाइलैंड जाने वाली उड़ानें दो घंटे विलंब हुईं। (प्रेट्र)

योगी बोले, हिंदुओं को इतिहास से सीख लेकर अब एकजुट होना होगा

उप्र के सीएम ने कहा-पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को मारकर मठ-मंदिर तोड़े जा रहे

योगी ने परमहंस रामचंद्रदास की पुण्यतिथि पर किया उनकी मूर्ति का अनावरण

जागरण संवाददाता, अयोध्या

- मंदिर आंदोलन को स्मरण करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था
- सम्मान मिलना पर्याप्त नहीं, उसे सुरक्षित करना होगा
- आपसी मनमुटाव मिटाकर सारे सनातनियों को एक होना होगा

अयोध्या में बुधवार को मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्रदास के समाधि स्थल पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में दिगंबर अखाड़ा के अन्य महंत। इंटरनेट मीडिया

राम मंदिर आंदोलन के महानायक ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्रदास की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिगंबर अखाड़े में उनकी मूर्ति का अनावरण करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोजकर मारा जा रहा है। मठ-मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में हमें इतिहास से सीख लेकर एकजुट होना होगा। एक होकर संकल्प के साथ काम करना होगा। योगी ने मंदिर आंदोलन और परमहंसजी को याद करते हुए कहा कि गोरक्षपीठ और दिगंबर अखाड़ा एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सरयू के संत तुलसीदास घाट तट पर स्थित परमहंसजी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परमहंस रामचंद्रदास व मंदिर आंदोलन का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। उन्होंने राम मंदिर को अपने जीवन का मिशन बनाया था। कहा कि गोरक्षपीठ के तत्कालीन महंत अवेद्यनाथ के सानिध्य में परमहंसजी का दिगंबर अखाड़ा आंदोलन में अग्रणी रहा। परमहंसजी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी प्राप्त हुआ। आज मेरा सौभाग्य है कि परमहंसजी वापस दिगंबर अखाड़ा में विराज गए हैं। उनकी सरलता के कारण कोई नहीं जान सकता था कि वह कितने बड़े नेतृत्वकर्ता हैं। कितने बड़े गुरु हैं। कितने चमत्कारी हैं। मूल्य व आदर्श के लिए परमहंसजी हमेशा डटे रहे। दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। आज अयोध्यावासियों को पूरे देश में सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिलना पर्याप्त नहीं, उसे सुरक्षित करना होगा। जिस तरह से सनातनधर्मियों पर आक्रमण हो रहे हैं, वे चिंता का विषय है। इतिहास में भी सनातन धर्म पर कई बार आक्रमण किए गए, लेकिन यह समय एकजुट होकर अपने सम्मान के लिए लड़ने का है। आपसी मनमुटाव मिटाकर सारे सनातनधर्मियों को एक होना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार से रामनगरी अयोध्या के दो दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने मंगलवार देर रात लता मंगेशकर चौक व धर्म पथ के बीच विकसित हेरिटेज वाल का लोकार्पण किया। हेरिटेज वाल में राम कथा पर केंद्रित 163 चित्र संयोजित किए गए हैं। इन चित्रों की विषयवस्तु का चयन और परिकल्पना प्रख्यात साहित्यकार यतींद्र मिश्र ने की है।

घर छोड़कर भागे हिंदू परिवारों में कई वापस लौटे, कुछ घरों में अब भी ताला

जागरण संवाददाता, जागरण • पाकुड़

जान की चिंता
- पाकुड़ के मुस्लिम बहुल तारानगर में जानलेवा हमले के बाद घर छोड़कर भाग गए थे 40 हिंदू परिवार
- गांव में कैंप कर रही पुलिस, प्रशासन के अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि दे रहे सुरक्षा का आश्वासन

झारखंड के पाकुड़ में हिंसाग्रस्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारानगर पंचायत के मुस्लिम बहुल उल्लू टोला गांव में फिलहाल शांति का माहौल है। यहां 18 जुलाई को मोहर्रम के समय भारी उपद्रव के बाद 40 हिंदू परिवार घर छोड़कर भाग गए थे। डर के मारे वह वापस नहीं आ रहे थे। पुलिस-प्रशासन व स्थानीय लोगों द्वारा काफी समझाने-बुझाने तथा सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बाद पिछले दो दिनों में कुछ लोग घर लौटे हैं। हालांकि कई घरों में अब भी ताला लटका है। लोगों के घरों के सामने ही एक अर्धनिर्मित हनुमान मंदिर में पुलिस कैंप कर रही है। गांव में घूम-घूमकर पुलिस लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रही है। पुलिसकर्मी यह बता रहे हैं कि अब सबकुछ पहले जैसा सामान्य हो गया है। उधर, घर छोड़कर पाकुड़ तथा आसपास के अन्य इलाकों में शरण लिए पीड़ितों का कहना है कि जिस तरह उनके घरों पर भीड़ का हमला हुआ, उसके बाद वह काफी डरे हुए हैं। इस कारण वापस अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं हो रही है। बता दें कि इंटरनेट मीडिया में एक युवती का वीडियो प्रसारित होने को लेकर उल्लू टोला में दो समुदाय के बीच भारी तनाव हो गया था। पहले युवती के परिवार को लोगों ने आरोपित मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी और बाद में आरोपित युवक के समर्थन में एकजुट होकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया। हिंसा भड़की तो डर के मारे 40 हिंदू परिवार अपना घर-परिवार छोड़कर भाग गए थे। गांव में पंचायतकर्मियों ने घर-घर जाकर जांच करने के बाद रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। अन्य परिवारों को भी वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं।

भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोरंजन सरकार ने बताया कि अब तक 20 परिवार ही अपने घर वापस लौटे हैं, जबकि 20 अन्य परिवारों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो नहीं लौटे हैं, उनमें कुछ ऐसे परिवार भी हैं, जिन पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जिनके पुरुष सदस्य दिन में आकर अपने घर का हाल-चाल देखकर रात में वापस चले जाते हैं। जो परिवार लौटे हैं उनमें भी कई परिवारों की महिला सदस्य अभी गांव नहीं लौटी हैं।

मप्र में मंत्री बनाने के लिए विधायक से सवा लाख मांगने वाला गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल

- भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली कार्यालय में बताई अपनी पदस्थापना

योगेश पंडाग्रे। फाइल

विधायक की शिकायत पर बैतूल पुलिस ने आरोपित को कानपुर से पकड़ा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यालय में स्वयं को कार्यरत बताकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला क्षेत्र से विधायक डा. योगेश पंडाग्रे से सवा लाख रुपये की मांग करने वाले नीरज सिंह राठौर को मप्र पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपित विधायक को लगातार फोन करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम कराने और मंत्री बनाने का झांसा देकर रुपये की मांग कर रहा था। एसडीओपी बैतूल शालिनी परस्ते ने बताया कि आमला विधायक डा. पंडाग्रे ने चार अगस्त को गंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विधायक के अनुसार, उन्हें तीन-चार दिन से मोबाइल नंबर-9336218380 से काल आ रही थीं। काल करने वाला नीरज सिंह राठौर स्वयं को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यालय में कार्यरत होने की बात कह कर सवा लाख रुपये की मांग कर रहा था। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने धारा 308 (2) बीएनएस 2023, 66 (डी) आईटी एक्ट का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 39 वर्षीय नीरज उप्र के जालौन का रहने वाला है।

नड्डा का नाम बताकर किसी से बात भी कराई : विधायक डा. योगेश पंडाग्रे ने बताया कि आरोपित नीरज ने पहली बार फोन किया तो बोला- वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यालय से बोल रहा है। आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बात करना चाहते हैं, आप तैयार रहना। शाम को फिर फोन आया और कहा- राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। इसके बाद किसी ने बात की। विधायक के अनुसार, उन्हें आवाज से ही समझ आ गया था कि यह फर्जी काल है, इसलिए वह सतर्क हो गए। फिर कहा कि आंध्र प्रदेश में होने वाले कार्यक्रम के लिए सवा लाख रुपये दीजिए। आनलाइन पैसे भेजने के लिए क्यू आर कोड भी भेजा था।

विकसित भारत के लिए एडमिरल त्रिपाठी ने पेश किया नौसेना का विजन

नई दिल्ली, एएनआइ : नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बुधवार को "सीएनएस कोर्स टू स्टीयर-2024 (सीटीएस-2024)" नामक एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें विकसित भारत के लिए नौसेना के विजन को पेश किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के अनुसार यह दस्तावेज युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार नौसेना पर प्रकाश डालता है। नौ सेना प्रमुख ने नौसेना को भारत की समुद्री शक्ति के प्रमुख के रूप में लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्पण और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया है।

उन्होंने नेतृत्व के पदों पर बैठे अधिकारियों से बदलाव का प्रबंधन करने और देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना को सही रास्ते पर रखने के लिए सीटीएस-2024 का लाभ उठाने का आग्रह किया। बता दें कि एडमिरल त्रिपाठी ने 30 अप्रैल को भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया था।

अग्रोहा टीले के सर्वे में मिले ईंट-पत्थरों के मजबूत समूह, एक मंच भी मिला

खोदाई के दौरान मिला अग्रोहा का टीला। जागरण आर्काइव

1939 और सन 1979 में दो बार हुई खोदाई

हरियाणा विधानसभा सचिवालय में हाल ही में अग्रोहा डेवलपमेंट कमेटी की विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अग्रोहा में स्थापित की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। अग्रोहा के विकास का खाका तैयार कर अब उसे डेवलप किया जाएगा। बैठक में अग्रोहा टीले के अध्ययन के लिए की गई जीपीआर (ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ड्रोन से टीले की डिजिटल मैपिंग की गई है। महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा में टीले के नीचे ईंट-पत्थरों (टूटी संरचना) के मजबूत समूह दिखाई दिए। हिसार से रिपोर्ट :

.05 मीटर गहराई पर प्रोफाइल ग्रिड का मजबूत प्रतिबिंब

टीले में जमीन के नीचे स्तूप के निकट 0.05 मीटर की गहराई पर प्रोफाइल ग्रिड का मजबूत प्रतिबिंब दिखा है। मजबूत क्लस्टरिंग प्रतिबिंब प्रोफाइल पर एक मंच या ईंट-बैट संरचना मिली है। यहां नीचे दबी हुई दीवारें भी दिखाई दी हैं।

10 एकड़ जमीन मांगी

अग्रोहा में मौजूद लोक निर्माण विभाग की करीब 10 एकड़ भूमि हरियाणा पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित करवाने के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। अग्रोहा डेवलपमेंट कमेटी पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं स्थापित करेगी। म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो के लिए ओपन थियेटर बनाया जाएगा।

ये सामग्री मिल चुकी है अभी तक

अग्रोहा टीले से पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा मुहरें, लोहे और तांबे के उपकरण, जनपद के गोले और सिक्के पाए गए थे। उत्खनन से लगभग चौथी शताब्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी ई.पू. तक के पांच सांस्कृतिक कालखंड प्राप्त हुए हैं। एक बौद्ध स्तूप और एक हिंदू मंदिर का भी पता चला है। 4 इंडो ग्रीक, एक पंच-मार्क और अग्रोदका के 51 अन्य सिक्कों सहित सिक्कों का एक संग्रह मिला है। विभिन्न कालखंडों के चांदी, कांस्य के सिक्के भी पाए गए हैं। वे रोमन, कुषाण, यौधेय और गुप्त साम्राज्य से संबंधित हैं। लगभग सात हजार कलाकृतियां बरामद हुईं।

अग्रोहा को अंग्रेजों ने 1926 में घोषित किया था संरक्षित स्थल

महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन काल सभ्यता आजतक दबी हुई है। ऐतिहासिक पुरातन स्थल अग्रोहा के बारे में प्राप्त दस्तावेजो के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन काल में एक रोबोट्स नाम के वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने 15 दिन का पुरातत्व सर्वे किया था। 1926 में नोटिफिकेशन जारी किया अग्रोहा के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया था।

पहल

बाढ़ से कट गया था मणिकर्ण घाटी के तीन गांवों बलाथी, फागटा व पौहल का संपर्क, पंचायत प्रधान नीरज ने बलाथी खड्ड पर झूला पुल बनाने के लिए दिए 50,000 रुपये

किसी ने नहीं ली सुध तो ग्रामीणों ने खुद बना लिया 'पुल'

संजय कुमार • जागरण

- लोगों ने श्रमदान कर किया पुल का निर्माण, तीनों गांवों के 400 लोगों को मिली सुविधा
- इससे पहले मलाणा, तोष व तिऊण गांवों के लोगों ने भी सुविधा के लिए स्वयं किए प्रयास

बलाथी खड्ड पर ग्रामीणों द्वारा तैयार किया गया झूला पुल। जागरण

कुल्लू : बाढ़ प्रभावित लोग अब राहत कार्यों के लिए सरकार या प्रशासन की ओर नहीं देख रहे हैं। कोई श्रमदान कर रहा है तो कोई धन से सहायता। बाढ़ प्रभावित मणिकर्ण घाटी के तीन गांवों के लोगों की पांच दिन तक किसी ने सुध नहीं ली तो ग्रामीणों ने स्वयं पहल की। श्रमदान कर झूला पुल का निर्माण कर सरकार व प्रशासन को आईना दिखाया है। इसके लिए जां पंचायत प्रधान नीरज शर्मा ने 50,000 रुपये दिए। झूला पुल बनने से तीनों गांवों के 400 लोगों को सुविधा मिलेगी। बाढ़ प्रभावित मलाणा गांव के लोगों ने पुल का निर्माण कर ऐसी ही मिसाल पेश की थी। अब गांववासी श्रमदान कर हेलीपैड बना रहे हैं। कुछ दिन पहले कुल्लू जिले के तोष में बादल फटने से बहे पुल के स्थान पर लकड़ी का पुल बना लिया था। वहीं, लग घाटी के तिऊण के ग्रामीणों ने भी पुल बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

> गांव के स्वास्थ्य केंद्र में भी दवाएं समाप्त हो गई हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका उपचार करना मुश्किल होगा। 50,000 रुपये खर्च कर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए झूला पुल का निर्माण करवाया है। तीन गांवों के लोगों ने पुल निर्माण के लिए श्रमदान किया। प्रशासन ने आग्रह किया है कि सरकार द्वारा स्थायी पुल बनवाया जाए। - नीरज शर्मा, प्रधान जां पंचायत

गत दिनों भारी वर्षा से बाढ़ आने से बलाथी, फागटा तथा पौहल को जोड़ने वाला पुल बह था। इससे तीन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया था। पांच दिन तक न सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा और न ही जिला प्रशासन की ओर से किसी अधिकारी ने ग्रामीणों को पूछा। पांच दिन तक गांव के लोग बाजार तक नहीं पहुंच पाए।

यूट्यूब देख माचिस की तीली के मसाले को टार्च में भर बना रहे थे 'बम', हुआ विस्फोट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : कुछ दिन पहले बिहार के सुपौल में पांच साल का बच्चा स्कूल बैग में पिस्तौल लेकर पहुंच गया था। उससे गोली चलने से कक्षा तीन का छात्र जख्मी हो गया था। मुजफ्फरपुर में मंगलवार की शाम हुई घटना इससे थोड़ी अलग है, लेकिन इसमें बच्चे ही शामिल हैं। यहां पांच से लेकर आठ साल के छह बच्चे यूट्यूब देख माचिस की तीली के मसाले को टार्च में भरकर पटाखा बम बना रहे थे। इस दौरान उसमें विस्फोट होने से पांच बच्चे झुलस गए। किसी का मुंह झुलसा तो किसी का हाथ। गायघाट थाना क्षेत्र की बोआरीडीह पंचायत के मुन्नी कल्याण गांव में हुए इस धमाके के बाद गांव और स्वजन में अफरातफरी मच गई। स्वजन मामले को रातभर दबाए रहे। घर में ही उपचार कराया। बुधवार दोपहर सभी को भर्ती करवाने पर मामला सामने आया।

बिहार में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में 10 अभ्यर्थी व साल्वर गैंग के 10 लोग गिरफ्तार

जागरण टीम, पटना

- आरा में चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगा परीक्षा देने पहुंचे थे अभ्यर्थी
- सारण में कोचिंग सेंटर पर छापा, साल्वर गैंग का सरगना फरार

बिहार पुलिस में सिपाही के 21391 पदों पर नियुक्ति के लिए बुधवार को पहले चरण की लिखित परीक्षा में कदाचार करते 10 अभ्यर्थियों और साल्वर गैंग के भी 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि कदाचार व अन्य वजहों से पटना से चार, बक्सर, आरा व जमुई से दो-दो अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आरा में पटना के अभ्यर्थी चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा देने आए थे। बक्सर के डुमरांव अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र के फोटो से मिलान नहीं हुआ तो उनके सामान की जांच की गई। उनके पास से सात और 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा के 145 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, दो पन्ने पर पटना और बक्सर के परीक्षा केंद्रों के नाम तथा उन केंद्रों के कुछ परीक्षार्थियों के रोल नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड आदि बरामद किए गए। अधिकारी के मुताबिक सारण पुलिस ने मंगलवार की रात एक कोचिंग सेंटर पर छापेमारी कर साल्वर गैंग के तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि सरगना फरार हो गया। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के निकट सरगना के किराये के फ्लैट से लैपटाप, 22 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बैंक के 22 ब्लैंक चेक, दो पासबुक, एक इयर पीस और तीन मोबाइल जब्त किए हैं। दरभंगा पुलिस के इनपुट पर जहानाबाद के कोठिया गांव से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके खाते में कई अभ्यर्थियों द्वारा रकम जमा करने की सूचना है।

****

20 हजार रेल इंजन हैं देश में अभी। सरकार की योजना प्रत्येक वर्ष पांच हजार इंजनों में कवच प्रणाली लगाने की है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना खत्म हो जाए।

न्यूज गैलरी

कंटेनर ने बाइक सवार परिवार के पांच लोगों को कुचला

उदयपुर : राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर मंगलवार रात करीब नौ बजे कंटेनर ने बाइक सवार एक ही परिवार के पांच लोगों को कुचल दिया। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। एक बाइक पर छह लोग सवार थे। हादसे में एक साल की बालिका बच गई, जो टक्कर के बाद छिटक कर दूर जा गिरी थी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में पति-पत्नी, बच्चे और उनके रिश्तेदार थे। पति-पत्नी बच्चों के साथ रिश्तेदार की ससुराल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सतराना गांव जा रहे थे। (संसू)

पीएमएलए फैसले पर पुनर्विचार अर्जियों पर 28 को सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस सवाल पर सुनवाई 28 अगस्त तक स्थगित कर दी कि क्या प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी की गिरफ्तारी एवं संपत्ति जब्त करने की शक्तियों को बरकरार रखने के उसके 2022 के फैसले पर किसी तरह के पुनर्विचार की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार एवं जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने बुधवार को जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू की तो ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'यह मामला अचानक आ गया है। हमें तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। हमें गत देर रात्रि ही पता चला कि मामला सुनवाई के सूचीबद्ध हुआ है। कृपया मामले पर बाद की किसी तिथि पर सुनवाई की जाए।' याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि 2022 का फैसला गलत है और इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई 28 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। (प्रेट्र)

मातृत्व अवकाश में रहते विमान उड़ाने पर प्रशिक्षक को नोटिस

पटना : बिहार के उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में उड्डयन प्रशिक्षण के पद पर तैनात कैप्टन पूजा संदवार को सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की है। महिला अधिकारी पूजा संदवार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गर्भावस्था का हवाला देते हुए मातृत्व अवकाश लिया और इसी दौरान प्रशिक्षण विमान भी उड़ाया। सरकार का कहना है कि कैप्टन संदवार का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रविधान का सरासर उल्लंघन है। इस मामले की जांच की जरूरत है। सरकार की ओर से जारी नोटिस में संदवार को निर्देश दिया गया है कि वह अपने बचाव के संबंध में पक्ष रखने के लिए जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित रहें। (राब्यू)

सूरत की एसीजेएम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की दोषी

अग्रिम जमानत के बावजूद आरोपित को पुलिस हिरासत में भेजने का मामला

एसीजेएम दीपाबेन संजय कुमार ठाकर के साथ इंस्पेक्टर आरवाई रावल को भी माना दोषी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करने वाली टिप्पणी करने के लिए भले ही चेतावनी के बाद बच गए हों, लेकिन गुजरात की एक जज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर उसके कोपभाजन से नहीं बच पाई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभूतपूर्व आदेश में गुजरात के सूरत में एडिशनल चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) दीपाबेन संजयकुमार ठाकर को अपने आदेश की अवमानना का दोषी ठहराया। इतना ही नहीं कोर्ट ने सूरत के वेसु थाने में तैनात इंस्पेक्टर आरवाई रावल को भी अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम जमानत आदेश होने के बावजूद उसकी अनदेखी कर व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भेजने को शीर्ष अदालत ने गंभीर और अदालत की अवमानना करने वाला मानते हुए दोनों अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी माना। कोर्ट ने दोनों (जज और इंस्पेक्टर) को दो सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सजा की मात्रा पर पक्ष रखने का आदेश दिया है। यानी कोर्ट ने दोनों को अवमानना का दोषी तो ठहरा दिया है, अब बस यह तय होना है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों को अवमानना के लिए कितनी और क्या सजा देता है।

ये आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने तुषार भाई रजनीकांतभाई शाह की याचिका पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को दिए। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र कहता है कि अगर वास्तव में किसी को पुलिस हिरासत में भेजने की आवश्यकता है तो कोर्ट ऐसा करने से पहले मामले के तथ्यों को देखता है और अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करता है। अदालत से जांच एजेंसियों के दूत के रूप में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाती। अदालतों को रिमांड अर्जियां रुटीन तरीके से नहीं स्वीकार करनी चाहिए। कोर्ट ने सूरत की एसीजेएम दीपाबेन संजयकुमार ठाकर को पक्षपाती और मनमाने तरीके से काम करने के लिए अवमानना का दोषी माना। पीठ इस बात से हैरान थी कि जब तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह को अग्रिम जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का आठ दिसंबर, 2023 का आदेश था तो फिर न्यायिक अधिकारी ने कैसे जांच अधिकारी की अभियुक्त को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजने की मांग की अर्जी पर ध्यान दिया और उसे हिरासत में भेज दिया।

पीठ ने आदेश में जज को अवमनानना का दोषी मानते हुए कहा कि उनके कारण अभियुक्त को पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद भी 48 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रहना पड़ा। हालांकि कोर्ट ने सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर विजय सिंह गुर्जर और मामले में अभियुक्त तुषारभाई के विरुद्ध शिकायत दाखिल करने वाले मूल शिकायतकर्ता अभिषेक विनोदकुमार गोस्वामी को अवमानना के आरोपों से मुक्त कर दिया है, उनके विरुद्ध जारी अवमानना नोटिस समाप्त कर दिए हैं।

असमानता रोकने का शक्तिशाली साधन है संविधान : सीजेआइ

डीवाई चंद्रचूड़। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि संविधान असमानता रोकने के लिए एक शक्तिशाली साधन है और यह ऐसी संस्थाओं का निर्माण करता है, जो असमानता से रक्षा करती हैं।

उन्होंने कहा कि संविधान इन संस्थाओं के भीतर नियंत्रण और संतुलन प्रदान करता है और देश के नागरिकों के लिए दायित्वों को भी निर्धारित करता है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 13वें दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआइ ने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपने आसपास की दुनिया में अन्याय को उसके सभी पहलुओं में पहचानें। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अंतर-संस्थागत संबंधों को विनियमित करता है तथा राज्य और उसके लोगों के बीच संबंधों का नियमन करता है। आज हमारे समाज के लिए शोरगुल एक खतरा है। हमें बेलगाम आवाजों के बीच तर्क की आवाज की जरूरत है। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनके पास अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता है।

सुप्रीम कोर्ट ने की जजों से भविष्य में अधिक संयम बरतने की अपेक्षा

प्रथम पृष्ठ से आगे

कोर्ट ने अपेक्षा की कि शीर्ष अदालत के आदेशों और खंडपीठों द्वारा पारित आदेशों पर विचार करते समय न्यायाधीश अधिक सावधानी बरतें। आशा है कि भविष्य में उन्हें इन न्यायाधीश या देश के किसी भी अन्य न्यायाधीश के संबंध में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। मामले की सुनवाई में अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट की मदद की।

मेहता ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा,हाई कोर्ट की सुनवाई का प्रसारित वीडियो देखने से पता चलता है कि न्यायाधीश की टिप्पणियां निंदनीय व अवमाननापूर्ण हैं। यह न्यायिक अनुशासन का ही नहीं घोर अवमानना का मामला है। वीडियो में न्यायाधीश यह कहते दिख रहे हैं कि जजों को न्यायिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। मेहता ने कहा, कई बार भाव बहुत कुछ कह देते हैं। आजकल कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है, हर व्यक्ति वीडियो देख रहा है। अटार्नी जनरल ने भी कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।

सभी को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, उन्हें सूचित किया गया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस सहरावत के आदेश पर रोक लगा दी है। वह किसी विशेष न्यायाधीश के बारे में नहीं कह रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट पर अनावश्यक टिप्पणी करने की प्रवृत्ति पर कह रहे हैं कि न्यायपालिका में पदानुक्रम अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस सहरावत के 17 जुलाई के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेगा जिससे हाई कोर्ट की गरिमा प्रभावित हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अदालतों के सीधे प्रसारण की शुरुआत लोगों तक न्याय की पहुंच आसान करने के लिए की गई है। अतः न्यायाधीशों को अधिक संयम बरतना चाहिए। ''सभी हाई कोर्ट व जिला अदालतें एक पदानुक्रमित न्यायिक प्रणाली में काम करते हैं। उस अनुशासन को बनाए रखना होगा।'' जस्टिस हृषिकेश राय ने कहा, 'कोई भी अदालत सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्चता संविधान की है। हम सभी संविधान से नीचे हैं। हमारा काम संविधान की व्याख्या करना है।''

मुआवजा में देरी पर ब्याज से जुड़ा था मामला

हाई कोर्ट की एकल पीठ के जज नार्ती राम बनाम देवेंद्र सिंह के भू-अधिग्रहण से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। मुआवजे में देरी के लिए ब्याज को लेकर विवाद था। इस मामले में एकल पीठ व खंडपीठ से फैसला होने के बाद जस्टिस राजबीर सहरावत की पीठ अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस पर सहरावत ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी।

अशोक गहलोत के पुत्र के कार्यकाल में आरसीए में घोटाला, दर्ज होगा केस

जागरण संवाददाता, जयपुर

- जांच के लिए गठित एडहाक कमेटी ने तैयार की विस्तृत रिपोर्ट
- ठेकों से लेकर स्टेडियम के निर्माण तक में मिली अनियमितता

वैभव गहलोत। फाइल

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की पूर्व कार्यकारिणी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। भाजपा सरकार की ओर से जांच के लिए गठित एडहाक कमेटी ने वैभव के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच कराई है। इसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) और राजस्थान प्रीमियर लीग (आरपीएल) से जुड़े ठेकों से लेकर स्टेडियम निर्माण तक के काम में अनियमितता मिली है। एडहाक कमेटी के अध्यक्ष भाजपा विधायक जयदीप बिहानी ने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सौंप पुलिस में जल्द शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

बिहानी ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जयपुर में चौंप स्टेडियम के निर्माण के लिए जमीन आवंटित हुई थी। निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था, लेकिन बाद में बंद हो गया। जांच में सामने आया कि आरसीए कार्यकारिणी ने करोड़ों रुपये का गबन किया है। छत्तीसगढ़ की जिस कंपनी को स्टेडियम बनाने का काम दिया गया, उसे इसका अनुभव ही नहीं था। कंपनी सड़क बनाने का काम करती है। स्टेडियम निर्माण की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये थी, लेकिन चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लागत बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया। कई तरह के भुगतान में भी गड़बड़ी मिली है। घोटालों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। अब जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

हाईकोर्ट में दी जा सकेगी वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती

केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 में बदलाव के लिए गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा 1923 के वक्फ अधिनियम को खत्म के लिए एक और विधेयक भी लाया जा सकता है। आइये जानते हैं कि प्रस्तावित विधेयक के जरिये वक्फ बोर्ड अधिनियम में कौन से बड़े बदलाव किए जाएंगे।

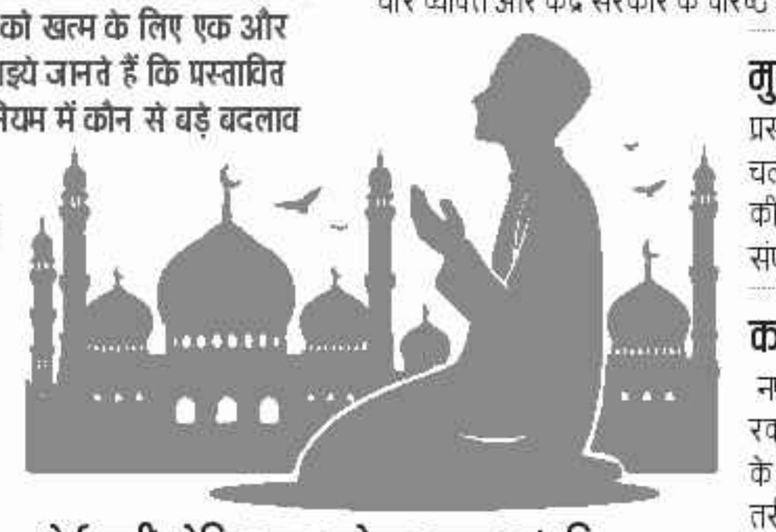

वक्फ बोर्ड में होंगी दो महिला सदस्य

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिला सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होगी। परिषद में अब एक केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, मुस्लिम संगठनों के तीन प्रतिनिधि और तीन मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा परिषद में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के दो पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा रखने वाले चार व्यक्ति और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

हाईकोर्ट में कर सकेंगे बोर्ड के खिलाफ अपील

नए कानून के तहत किसी संपत्ति को वक्फ के तौर पर पंजीकृत करने से पहले नोटिस जारी करना होगा। इसके अलावा पंजीकरण एक वेबसाइट पर होगा। वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार अब जिला अधिकारी को दिया जाएगा। इसके अलावा नए कानून में वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में अपील करने का प्रविधान भी होगा।

बोर्ड नहीं घोषित कर सकेगा वक्फ संपत्ति

प्रस्तावित विधेयक के तहत एक प्रमुख बदलाव मौजूदा कानून की धारा 40 को खत्म करना है। धारा 40 ही वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार देती है। इसके बजाए अब वक्फ की संपत्ति घोषित करने फैसला जिला अधिकारी या नौकरशाह करेंगे।

मुसलमान ही दान कर सकेंगे संपत्ति

प्रस्तावित बदलाव के तहत सिर्फ मुसलमानों को ही चल, अचल संपत्ति वक्फ परिषद या बोर्ड को दान करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, सिर्फ कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक ही दान का फैसला ले सकेगा।

कल्याण पर खर्च होगी रकम

नए कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड को मिलने वाली रकम विधवा और तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। रकम खर्च करने के तरीकों पर सरकार सुझाव देगी।

बोहरा- आगाखानी के लिए अलग बोर्ड

विधेयक में बोहरा और आगाखानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बोर्ड में शिया, सुन्नी और मुस्लिमों में दूसरे पिछड़े वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

जागरण रिसर्च

सौ फीट गहरा था स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग का अरघा

विधि संवाददाता • जागरण

- वादमित्र ने कोर्ट को इतिहास की मदद से बताया ज्ञानवापी का भूगोल

वाराणसी: ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई के दौरान बुधवार को वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने इतिहास के हवाले से कोर्ट को ज्ञानवापी का भूगोल समझाया। उन्होंने बताया कि कई पुस्तकों में ज्ञानवापी का उल्लेख है। वादमित्र का कहना था कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के 100 फीट लंबे शिवलिंग का अरघा भी सौ फीट गहरा था। इस पर गंगाजी के स्रोत से जल निरंतर गिरता रहता था।

वर्ष 1991 में स्व. पं. सोमनाथ व्यास, डा. रामरंग शर्मा व पं. हरिहर नाथ पांडेय द्वारा दाखिल मुकदमे की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में हुई। वादमित्र ने एक और एएसआइ सर्वे कराने की अपील पर बहस करते हुए धार्मिक व ऐतिहासिक पुस्तकों में ज्ञानवापी के उल्लेख की दलील दी। इसे जारी रखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तारीख तय की है।

वादमित्र ने स्कंद महापुराण के काशी खंड, ब्रह्म वैवर्त पुराण, डा. मोती चंद की पुस्तक काशी का इतिहास, चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत यात्रा वृतांत आदि पुस्तकों की प्रतियां अदालत को सौंपी। इन ग्रंथों व पुस्तकों के हवाले से श्रीकाशी विश्वनाथ के मुख्य मंदिर के स्वरूप के बारे में जानकारी दी गई। बताया कि अरघे पर गिरने वाला जल ब्रह्मनाल से होते हुए वर्तमान में ललिता घाट पर गंगा में मिलता था। औरंगजेब की सेना ने उस शिवलिंग के स्थान पर पत्थर, मलबा डालकर उसे पाटकर ढक दिया और उसके ऊपर का हिस्सा दालान के रूप में परिवर्तित कर दिया। नीचे के तहखाने में मंदिर के पुराने अवशेष मौजूद हैं। एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान उसके दक्षिण-पूर्वी कोण पर नवनिर्मित तालाब में शिवलिंग मिला था। तालाब को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील कर दिया गया है, इसलिए एएसआइ ने तालाब और शिवलिंग मिलने वाले स्थान का सर्वे नहीं किया है। इस क्षेत्र का सर्वे किया जाना जरूरी है।

बेहिसाब संपत्ति मामले में तमिलनाडु के दो मंत्रियों के खिलाफ होगी सुनवाई

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाई कोर्ट ने बेहिसाब संपत्ति के मामले में सुनवाई अदालत के आरोपमुक्त करने के फैसले को दरकिनार करते हुए तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री तंगम तेनारासु के खिलाफ बुधवार को आरोप तय करने का निर्देश दिया।

जस्टिस एन.आनंद वेंकटेश ने आपराधिक समीक्षा याचिका पर आदेश पारित करते हुए बेहिसाब संपत्ति के दो अलग मामलों में रामचंद्रन व तंगम तेनारासु को सुनवाई का सामना करने को कहा। दोनों मंत्री और द्रमुक नेताओं को उनके खिलाफ सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के जरिये दर्ज केसों में सुनवाई का सामना करना होगा। जज ने रामचंद्रन को विशेष अदालत के समक्ष 9 सितंबर को पेश होने को कहा है। साथ ही तेनारासु को 11 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। जज ने कहा कि दोनों मामले क्रमशः 2011 और 2012 के हैं। जज ने कहा कि अगर यह अवैध प्रक्रियाएं अदालत के सामने आई हैं तो यह न्यायिक दायित्व है कि न्याय में हुई गफलत को दूर किया जाए। कानून की नजर में राज्य के राजनेता और आम आदमी बराबर हैं।

ईसाई मिशनरी में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न, मतांतरण कराने का भी अंदेशा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

- संस्था में काम करने वाली महिला समेत तीन के विरुद्ध मामला दर्ज
- फादर को भेजा जाता था बच्चियों के सोते समय का अश्लील फोटो

गांव चांदपुर स्थित ईसाई मिशनरी। जागरण

फरीदाबाद के चांदपुर गांव में ईसाई मिशनरी की संस्था (सेंट मैरी चिल्ड्रेन्स होम) में रहने वाली बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। संस्था में बच्चियों को डरा धमकाकर रखा जाता था। सोते समय उनके अश्लील फोटो खींचकर कर्मचारी मिशनरी के फादर को भेजते थे। मतांतरण कराने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। छांयसा थाना पुलिस ने महिलाकर्मी समेत तीन के विरुद्ध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पाक्सो के तहत मामला दर्ज किया है।

फरीदाबाद की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीपाल करहाना को दिल्ली निवासी युवती ने बताया था कि उसके माता-पिता नहीं हैं। उसकी छोटी बहन कई साल से चांदपुर स्थित ईसाई मिशनरी में रह रही है। बहन ने फोन कर कुछ संदिग्ध बातें बताई थीं। वह बहन को अपने साथ रखना चाहती है, पर मशीनरी के फादर ने उसे केरल स्थित दूसरी मिशनरी में भेज दिया। सच जानने के लिए जिला बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी गरीमा सिंह तोमर, बाल कल्याण समिति के सदस्य सुनील यादव व कौराली अस्पताल के मेडिकल आफिसर डा. प्रदीप कुमार मिशनरी में जांच के लिए चांदपुर पहुंचे। वहां 33 बच्चियां मिलीं। मिशनरी करीब 24 साल से चल रही है। बच्चियों ने अधिकारियों को बताया कि चाइल्ड केयर टेकर के रूप में काम करने वाली मैसी लूसी उनकी पिटाई करती है। सोते समय उनकी अश्लील फोटो खींच कर फादर जोमेन और फादर अरुण के पास भेजे जाते थे। विरोध करने पर मारा-पीटा जाता है। मानसिक उत्पीड़न भी किया जाता है। डरा धमकाकर घंटों कार्य कराया जाता है। बच्चियों की पीड़ा जानने के बाद अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लूसी के मोबाइल को कब्जे में ले लिया, जिसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। पुलिस ने बताया कि डाटा रिकवर होने के बाद पता लगेगा कि कितने वीडियो बनाए गए हैं। जांच में जो भी तथ्य आएगा, पुलिस उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगी। जांच पूरी होने तक यहां रह रही बच्चियों को किसी और संस्था में स्थानांतरित किए जाने पर सहमति बनी। मतांतरण कराए जाने की भी आशंका है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन श्रीपाल कराहना ने बताया कि पता लगाया जाएगा कि मिशनरी को जमीन आवंटित और पंजीकृत है अथवा नहीं।

सीजीपीएससी फर्जीवाड़े में छग के छह जिलों में 15 ठिकानों पर सीबीआइ छापे

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : सीबीआइ ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) फर्जीवाड़े मामले में बुधवार को प्रदेश के छह जिलों में 15 ठिकानों पर छापा मारा। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर और धमतरी जिले में चयनित अभ्यर्थियों और उनके रिश्तेदारों के घर तलाशी ली गई। टीम ने चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ के साथ दस्तावेजों की भी जांच की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जिनके ठिकानों पर छापा मारा, उनमें पूर्व राज्यपाल के सचिव अमृत खलको, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी, श्रम पदाधिकारी सुनीता जोशी, बीएसपी कर्मचारी एल. कौशिक शामिल हैं। इनके पुत्र-पुत्रियों के नाम चयन सूची के टापरों में आने से चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 170 पदों की चयन सूची 11 मई 2023 को जारी की गई थी। राज्य सरकार ने छह मार्च 2024 को सीजीपीएससी भर्ती की जांच सीबीआइ से कराने की अधिसूचना जारी की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी 18 अभ्यर्थियों के चयन की जांच कर रही है।

व्यवस्था

चार वर्षों में सभी लोकोमोटिव में लगा दी जाएगी कवच प्रणाली, यह सभी तरह की भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम

पायलट की गलतियों से नहीं होंगे ट्रेन हादसे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अश्विनी वैष्णव फाइल

पायलट की गलतियों से एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के बीच होने वाली टक्कर पर जल्द नियंत्रण लग जाएगा। अगले चार वर्षों में ही देश के सारी ट्रेनों में 'कवच' प्रणाली लगा दी जाएगी। रेलवे ने अभी दस हजार किमी रेल रूट पर कवच लगाने का काम तीन कंपनियों को दिया है। बाकी रेल रूट, लोकोमोटिव एवं आठ हजार स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडिया को बताया कि रेलवे ने स्वदेशी तकनीक एवं संसाधनों से कवच का विकास किया है। इसके 4.0 वर्जन को इसी साल 17 जुलाई को पूरा किया गया है। यह जंगल, पहाड़ और पानी सभी तरह की भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम है।

रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेन हादसों के तीन बड़े कारण होते हैं। ट्रैक की खराबी, ड्राइवर की गलती एवं कभी-कभी ट्रैक पर कुछ आ जाने पर दुर्घटना का खतरा रहता है। कवच प्रणाली से ड्राइवर की गलतियों से होने वाले हादसों का खतरा टल जाएगा। देश में अभी लगभग 20 हजार रेल इंजन हैं। प्रत्येक वर्ष करीब पांच हजार इंजनों पर कवच लगाया जाएगा। इस तरह चार वर्ष में ही सभी लोकोमोटिव में कवच प्रणाली लगा दी जाएगी। साथ ही रेल ट्रैक एवं स्टेशनों पर भी नए वर्जन का कवच लगाना है।

रेलवे ने तीन कंपनियों को काम दिया है। दो अन्य कंपनियों को काम दिया जाना है। जिन रेल रूटों पर पहले से पुराने वर्जन की कवच प्रणाली लगी है, उसे भी अपग्रेड किया जाएगा। नया साफ्टवेयर इंस्टाल करना है। सौ प्रतिशत स्वदेशी तकनीक एवं संसाधनों से निर्मित कवच के 4.0 वर्जन को 17 जुलाई को पूरा किया गया है। यह जंगल, पहाड़ और पानी सभी तरह की भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम है। रेल मंत्री ने बताया कि कवच का नया वर्जन अभी तक सभी परीक्षणों में सौ प्रतिशत खरा उतरा है। इससे ट्रेन की गति पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रूट पर कवच लगाने का काम जारी : दिल्ली-मुंबई एवं दिल्ली-हावड़ा रूट पर लगभग तीन हजार किमी में कवच लगाने का काम जारी है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई के लगभग 3,300 किमी रूट समेत सभी स्वचालित सिग्नलों के लिए भी निविदाएं निकाली गई हैं। इसमें भी अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा। इसके तुरंत बाद अन्य रूटों पर भी काम शुरू होगा।

****

राहुल ने लोकोपायलटों को रेल मंत्री से मिलवाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में लोको पायलटों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलाने ले गए। उन्होंने लोको पायलटों के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वे अपनी समस्याएं बताते नजर आ रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोको पायलटों ने कहा कि राहुल ने उनसे संसद भवन में मुलाकात की और फिर उन्हें रेल मंत्री से मिलवाने ले गए। एक्स पर पोस्ट में राहुल ने कहा कि संसद भवन में लोको पायलटों से फिर मुलाकात हुई। लोको पायलटों ने केबिन में पर्याप्त आराम और बुनियादी सुविधाओं की अपनी मांग दोहराई।

डीएनए जांच को लिया आरोपितों का सैंपल, पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार

जागरण टीम, लखनऊ

अयोध्या दुष्कर्म कांड

- पीड़िता को जल्द अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी

अयोध्या में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित सपा नेता मोईद खान व उसके नौकर राजू खान का सैंपल डीएनए जांच के लिए बुधवार को अयोध्या जेल में लिया गया। उधर, लखनऊ में पीड़िता के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। मंगलवार को डाक्टरों ने उसके 12 सप्ताह के गर्भ का समापन किया था।

पीड़िता और भ्रूण का सैंपल मंगलवार को गर्भपात के समय लेकर पुलिस को दे दिया गया था। पुलिस विवेचना में डीएनए टेस्ट का मिलान करेगी। बुधवार को किशोरी की सभी जांच रिपोर्ट सामान्य आई है। ऐसे में उसे एक-दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए सोमवार को अयोध्या से लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। मोईद खान व राजू खान ने बेकरी में नौकरी दिलाने के बहाने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसका वीडियो भी बना लिया था। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती होने पर मामला खुला और दोनों को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेकर पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के साथ ही कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया था। यह बेकरी सरकारी और एक किसान की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी।

50 हजार से ज्यादा मामले उपभोक्ता अदालतों में लंबित हैं रियल एस्टेट के। राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता अदालतों में 2,44,813 मामले दायर किए गए हैं। 31 जुलाई 1,94,555 का निपटारा किया जा चुका है।

हिमाचल में एक और शव मिला, 36 की तलाश जारी

31 जुलाई की रात को सात स्थानों पर बादल फटने से आई बाढ़ में बह गए थे 55 लोग

जागरण टीम, नई दिल्ली

हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों शिमला, कुल्लू व मंडी में 31 जुलाई की रात को सात स्थानों पर बादल फटने से आई बाढ़ में बहे लोगों की तलाश अब भी जारी है। शिमला जिले के समेज में लापता एक और महिला का शव बुधवार को मिला है। समेज से 26, मंडी जिले के राजबन से एक और कुल्लू के बागीपुल से नौ लापता लोगों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तलाशी अभियान के दौरान मिले शवों में से दो की पहचान स्वजन ने कर दी है। उधर, आपदा विभाग ने कहा है कि तलाश अभियान स्वजन की सहमति से ही बंद होगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डा. डीसी राणा का कहना है कि अभियान कब तक जारी रहेगा, यह स्थानीय लोगों और प्रशासन की सहमति पर निर्भर करेगा। कुल 55 लोग लापता हुए थे, जिनमें से अब तक 19 के ही शव मिले हैं। पिछले वर्ष आपदा के बाद 25 दिन तक 39 लोगों की तलाश चली थी, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित किया गया था।

हिमाचल के आठ जिलों में 13 तक भारी बारिश का अलर्ट : मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के आठ जिलों में 13 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को इस दौरान नदी-नालों व भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रदेश में कई स्थानों पर मंगलवार रात से रुक-रुक वर्षा हो रही थी।

बिहार में वज्रपात से नौ लोगों की मौत : बिहार में वज्रपात से बुधवार को तीन जिलों में नौ लोगों की मौत हो गई। इनमें नवादा में सर्वाधिक छह लोगों की मृत्यु हुई है। सभी अलग-अलग गांवों में धान की रोपाई कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है।

प्रयागराज में बड़े हनुमानजी ने किया महास्नान, वाराणसी में छत पर गंगा आरती

संगमनगरी प्रयागराज और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में गंगा का जल स्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी से बुधवार सुबह प्रयागराज में बड़े हनुमानजी का महास्नान हो गया। श्रावण शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि पर बुधवार की सुबह 6.40 बजे गंगा का जल हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया। प्रयागराज में गंगा पांच तो यमुना में दो सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। उधर, वाराणसी में भी छह सेमी प्रति घंटे की गति से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पर गलियों में चिताएं जलाई जा रही हैं तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती स्थल छत पर बना दिया गया है।

प्रयागराज में बुधवार को लेटे हनुमानजी के मंदिर में गंगा का जल पहुंचने पर पूजन करते महंत बलवीर गिरी। जागरण

मौसम ने डाला खलल, केदारनाथ यात्रा शुरू नहीं हो पाई

मौसम अनुकूल न होने के कारण बुधवार को हेलीकाप्टर सेवा से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई। पूरे दिन हेलीकाप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान नहीं भर सके। उधर, केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा भी स्थगित है। क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है, फिर भी पैदल यात्रा शुरू होने में अभी एक हफ्ते का समय लग सकता है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सेना की ओर से यात्रियों को निकालने के लिए बनाया गया अस्थायी पैदल पुल मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बह गया है। उधर, बुधवार को भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने केदारघाटी से 150 स्थानीय लोगों और व्यापारी को सुरक्षित निकाला। 31 जुलाई को बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी।

उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने से क्षतिग्रस्त मार्ग को सही किए जाने का काम जारी है। प्रेट्र

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में बुधवार को ढहा हुआ काली नदी पर बना पुल। प्रेट्र

वायनाड में अभी भी 152 लोग लापता, मोदी 10 को जाएंगे

- विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 413 हो गई
- राहुल ने लोकसभा में कहा- वायनाड भूस्खलन राष्ट्रीय आपदा घोषित हो

नई दिल्ली, आइएएनएस : केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 413 हो गई है। अभी भी 152 लोग लापता हैं। बुधवार को नौवें दिन भी राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे और आपदा प्रभावितों से मिलेंगे।

एक सूत्र ने बताया कि पीएम विशेष विमान से कन्नूर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकाप्टर से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद कुछ राहत शिविरों का दौरा करेंगे, जहां फिलहाल 10,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। उधर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा- ''मैं केंद्र सरकार से वायनाड के लिए व्यापक पुनर्वास पैकेज देने अनुरोध करता हूं। केंद्र सरकार को लोगों को मिलने वाले मुआवजे में भी वृद्धि करनी चाहिए। केंद्र को वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए।'' इस बीच, तेलुगू सुपरस्टार प्रभास ने बुधवार को केरल के भूस्खलन प्रभावित जिले में पुनर्वास प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दो करोड़ रुपये का दान दिया।

छात्र के पत्र ने सेना का दिल जीता, रक्षाबल ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब : वायनाड में राहत कार्यों में जुटे सैनिकों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए तीसरी कक्षा के एक छात्र रेयान द्वारा लिखे पत्र ने भारतीय सेना का दिल जीत लिया है सेना की दक्षिणी कमान ने बच्चे का पत्र और अपना जवाब पोस्ट किया है। स्कूल डायरी में लिखे पत्र में छात्र ने कहा- 'मैं रयान हूं। मेरा प्रिय वायनाड बड़े भूस्खलन की चपेट में आ गया, इससे भारी तबाही हुई। मुझे आपको मलबे में फंसे लोगों को बचाते देखकर गर्व और खुशी हुई।' बच्चे ने एक वीडियो का जिक्र किया है जिसमें सैनिकों को भूस्खलन से तबाह क्षेत्र में पुल बनाने के दौरान भूख मिटाने के लिए बिस्कुट खाते देखा गया। छात्र ने लिखा कि इस दृश्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं एक दिन सेना में भर्ती होना और देश की रक्षा करना चाहता हूं। जवाब में सेना ने कहा- 'प्रिय मास्टर रयान, आपके मार्मिक शब्दों ने हमारा दिल छू लिया है। विपत्ति के समय में हमारा मकसद आशा की किरण बनना है। आप जैसे नायक हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें उस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा है जब आप वर्दी पहनेंगे और हमारे साथ खड़े होंगे। हम एक साथ मिलकर अपने देश को गौरवान्वित करेंगे। आपके साहस और प्रेरणा के लिए आभार युवा योद्धा।

पिता की जान बचाने को बदमाशों से भिड़ गई बेटी

नईदुनिया न्यूज जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में बस्तर के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के झारागांव में सोमवार को 17 वर्षीय सुशीला कोर्राम अपने पिता की जान बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ गई। पिता पर आठ अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से हमला किया था। सुशीला ने हमलावर के हाथ से न सिर्फ कुल्हाड़ी छीन ली, बल्कि घायल पिता को कमरे में बंदकर शोर मचाया, जिसके बाद हमलावर भागे। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को जगदलपुर मेडिकल कालेज में भर्ती किया है। एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पारिवारिक विवाद लग रहा है। उधर, राज्यपाल रमेन डेका ने सुशीला को राजभवन बुलाकर सम्मानित करने का निर्देश दिया है। सुशीला आठवीं तक पढ़ी है और शिक्षक पिता की इकलौती संतान है। उसने बताया कि वह मां के साथ वनोपज संग्रह करने जंगल भी जाती है।

अस्पताल में पिता के साथ बहादुर बेटी सुशीला।

बिहार में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दो लावारिस शव नदी में फेंके

जागरण संवाददाता, सासाराम

- एक शव पोस्टमार्टम हाउस में 72 घंटे सुरक्षित रखने के बाद फेंका गया
- दूसरे शव के बारे में यह पता नहीं कि उसकी बरामदगी कहां से हुई थी

बिहार के डेहरी में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कराने के बजाय लावारिस शवों को सोन नदी में फेंक दिया। एक दिन पहले सोन नदी पर बने रेल पुल के नीचे मिले दो लावारिस शवों की जांच के बाद पुष्टि हो गई है कि उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। एक वृद्ध के शव को गत दो अगस्त को प्लेटफार्म से बरामद कर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) सासाराम ने पोस्टमार्टम कराया था। इसके बाद 72 घंटे तक शव सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखा गया था। इस बीच कोई दावेदार नहीं आया तो पुलिस ने उनके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार के बजाय नदी में फेंकवा दिया। दूसरे शव का भी पोस्टमार्टम हो चुका है, हालांकि उसके बारे में यह पता नहीं चल सका है कि उसकी बरामदगी कहां से हुई थी।

उल्लेखनीय है कि लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का सरकारी स्तर पर प्रविधान है। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है। अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस व अस्पताल प्रशासन की संयुक्त जिम्मेवारी होती है। फिर भी शवों के साथ ऐसे व्यवहार ने पूरे तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

डेहरी के अपर पुलिस अधीक्षक शुभांकर मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने दोनों शवों की जांच के बाद उनके पोस्टमार्टम की पुष्टि की है। उधर, सासाराम जीआरपी का कहना है कि पहचान नहीं होने के बाद पांच अगस्त की रात शव को अंतिम संस्कार के लिए डेहरी में सोन किनारे भेजा गया था। दूसरा शव कहां से लाया गया था, अभी पता नहीं चल सका है। ज्ञात हो देश के अन्य राज्यों में भी पुलिसकर्मियों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की खबरें आती रहती हैं।

यूट्यूब शाट्स ने एक लाख करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार किया : नील मोहन

नई दिल्ली, प्रेट्र : यूट्यूब शाट्र्स ने एक लाख करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने बुधवार को यह घोषणा करते हुए भारतीय कंटेंट (सामग्री) निर्माताओं को इसका श्रेय दिया है। यूट्यूब शाट्र्स 60 सेकंड का वीडियो प्रारूप है। साल, 2020 में भारत में ही इसकी वैश्विक शुरुआत की गई थी। यहां यूट्यूब ब्राडकास्ट-2024 कार्यक्रम में नील मोहन ने कहा कि यूट्यूब ऐसा मंच बन गया है, जहां लोग अपनी कहानी बता सकते हैं।

उन्होंने कहा, भारतीय क्रिएटर स्थानीय रुझानों से प्रेरित होकर वीडियो बना रहे हैं, जो वैश्विक संस्कृति को परिभाषित करते हैं। यूट्यूब भारत में पहुंच और देखने के समय के मामले में नंबर एक है और हमने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार किया है। सबसे पहले भारत में पेश किए शाट्र्स के एक लाख करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब भारत में कनेक्टेड टीवी (सीटीवी) पर सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली श्रृंखला है तथा पिछले तीन वर्षों में इसके दर्शकों की संख्या में चार गुना बढ़ी है।

पंजाब के खरड़ थाने में हुआ था लारेंस बिश्नोई का पहला साक्षात्कार

दयानंद शर्मा • जागरण

- हाई कोर्ट में पेश एसआइटी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा पर्दाफाश
- दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की जेल में, राज्य सरकार पक्ष बनेगी

चंडीगढ़: गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के साक्षात्कार मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक, लारेंस का हिरासत में पहला साक्षात्कार पंजाब पुलिस की क्राइम इंवेस्टिगटिंग एजेंसी (सीआइए) के खरड़ स्थित परिसर में हुआ था। रिपोर्ट से पंजाब सरकार के उस दावे की पोल खुल गई है जिसमें कहा गया था कि साक्षात्कार पंजाब की सीमा में नहीं हुआ था।

हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच स्पेशल डीजीपी ह्यूमन राइट्स प्रबोध कुमार की अध्यक्षता वाली एसआइटी को सौंपी थी। एसआइटी ने सीलबंद रिपोर्ट बुधवार को हाई कोर्ट में पेश की। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पढ़ा जिससे सामने आया कि पहला साक्षात्कार सीआइए खरड़ में हुआ था। विशेष बात यह है कि सितंबर 2022 में रिकार्ड किए गए इस साक्षात्कार को सात माह बाद मार्च, 2023 में जारी किया गया था। इस जानकारी पर हाई कोर्ट ने उन कर्मियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिन्होंने इस इंटरव्यू के लिए व्यवस्था करने में भूमिका निभाई थी।

लारेंस बिश्नोई। फाइल

हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एसआइटी का सहयोग करने का आदेश दिया।

लारेंस के दूसरे साक्षात्कार के संबंध में बताया गया कि यह राजस्थान की जेल में हुआ था। इस पर हाई कोर्ट ने 'न्यायालय मित्र' को आदेश दिया कि वह राजस्थान सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से पक्ष बनाएं। हाई कोर्ट ने राजस्थान के एडवोकेट जनरल को अगली सुनवाई पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पंजाब पुलिस देश की बेहतरीन पुलिस है परंतु इसमें कुछ काली भेड़ें हैं जो इसकी छवि धूमिल करती हैं। ऐसी काली भेड़ों को ढूंढकर अलग करना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि जेल से उगाही व धमकी के सर्वाधिक मामले पंजाब से ही सामने आते हैं, ऐसे में अगली सुनवाई पर बताया जाए कि पंजाब की जेलों से ऐसे फोन करने के कितने मामले सामने आए हैं और उन मामला में क्या कार्रवाई की गई है।

ममता कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग्स मामले में हाई कोर्ट ने रद की एफआइआर

मुंबई, प्रेट्र : पूर्व बालीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में बांबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज 2016 के ड्रग्स मामले को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा, कुलकर्णी के खिलाफ कार्यवाही तुच्छ व अफसोसजनक है और इसे जारी रखने से अदालत का दुरुपयोग होगा।

जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 22 जुलाई को पारित एक आदेश में, जिसकी एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई थी, कहा कि उसकी स्पष्ट राय है कि कुलकर्णी के खिलाफ एकत्र सामग्री प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता। पीठ ने आदेश में कहा, 'हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) के खिलाफ अभियोजन जारी रखना अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग से कम नहीं होगा। वह इस बात से संतुष्ट हैं कि एफआइआर रद करने की अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह उपयुक्त मामला है क्योंकि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और अफसोसजनक है।'' बता दें कि कुलकर्णी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के विभिन्न प्रविधानों के तहत ठाणे पुलिस द्वारा 2016 में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर रद करने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है। वह केवल विक्की गोस्वामी से परिचित थी, जो मामले के सह-अभियुक्तों में से एक है। पुलिस ने अप्रैल 2016 में एक किलोग्राम इफेड्रिन (मादक पदार्थ) रखने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच के बाद कुलकर्णी समेत 10 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कुलकर्णी ने विक्की व अन्य सह-अभियुक्तों संग जनवरी 2016 में केन्या के होटल में मादक पदार्थों की बिक्री व खरीद के लिए बैठक की थी।

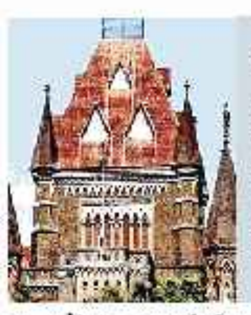

कहा-पूर्व अभिनेत्री के खिलाफ कार्यवाही तुच्छ और अफसोसजनक

सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का में प्राइवेट वाहनों के आवाजाही पर राजस्थान से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान मंदिर तक प्राइवेट वाहनों की आवाजाही के कारण वन्यजीवों को होने वाली क्षति पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है।

जस्टिस बीआर गवई, केवी विश्वनाथन व संदीप मेहता की पीठ ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और 11 सितंबर तक जवाब मांगा है, जबकि अदालत द्वारा आदेशित सीईसी के अधिकांश सुझावों से राज्य सहमत है। मामले में न्याय मित्र के रूप में कोर्ट की मदद कर रहे वकील के परमेश्वर ने कहा, सीईसी ने टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मंदिर तक जाने वाले वाहनों पर पाबंदी की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक शटल बसें भक्तों को ले जाने का विकल्प हो सकती हैं। सीईसी ने रिपोर्ट में कहा है कि रिजर्व के अंदर बड़े पैमाने पर वाहनों का आवागमन बाघों के प्रजनन और अन्य वन्यजीवों पर प्रभाव डाल रहा है।

अभियोजन एवं साक्ष्यों की गुणवत्ता पर फोकस करे ईडी : सुप्रीम कोर्ट

- मनी लांड्रिंग मामलों में दोषसिद्धि की कम दर का दिया हवाला
- कहा, इसके लिए ईडी को करनी चाहिए कुछ वैज्ञानिक जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : मनी लांड्रिंग के मामलों में दोषसिद्धि की कम दर का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ईडी को अभियोजन एवं साक्ष्यों की गुणवत्ता पर फोकस करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता व उज्जल भुइयां की पीठ ने संसद में दिए गए हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा, दोषसिद्धि की दर में वृद्धि के लिए ईडी को कुछ वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए।

अदालत छत्तीसगढ़ के कारोबारी सुनील कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्हें कोयले के परिवहन पर अवैध लेवी वाले मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से कहा, 'इस मामले में आप कुछ गवाहों के बयानों, हलफनामों पर जोर दे रहे हैं। इस तरह के मौखिक साक्ष्य... भगवान जाने कल वह व्यक्ति इस पर कायम रहेगा या नहीं। आपको कुछ वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए।' राजू ने कहा कि सीआरपीसी की धारा-161 के बयानों के विपरीत पीएमएलए की धारा-50 के तहत बयानों को साक्ष्य माना जाता है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि पीएमएलए की धारा-19 की तहत गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को भरोसे के कारण बताने होते हैं, उन्होंने एएसजी से पूछा कि कि क्या वर्तमान मामले में गिरफ्तारी आदेश बरकरार रखने योग्य है। याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि आरोपित को गिरफ्तारी के आधार के अलावा भरोसे के कारण भी बताए जाने चाहिए। साथ ही गिरफ्तारी आवश्यक होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने सुनील कुमार की अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सिलिकोसिस के खतरे वाले उद्योगों की निगरानी करे एनजीटी

- कहा, प्रभावित श्रमिकों को उचित मुआवजा प्रक्रिया की निगरानी करे एनएचआरसी
- लंबे समय तक सिलिका कणों के शरीर में जाने से होती है यह लाइलाज बीमारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को देशभर में सिलिकोसिस के खतरे वाले उद्योगों एवं कारखानों के असर की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केंद्रीय और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मुद्दे पर उसके पूर्व के निर्देशों का अनुपालन करें। सिलिकोसिस फेफड़ों की ऐसी लाइलाज बीमारी है, जो सिलिका के कणों के लंबे समय तक शरीर के अंदर जाने से होती है।

जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना भालचंद्र वराले की पीठ ने कहा, गठित किए गए वैधानिक निकाय कानून के अनुपालन की बेहतर निगरानी व देखरेख करने की स्थिति में होंगे। पीठ ने एनजीटी को भी निर्देश दिया कि ऐसे उद्योगों एवं कारखानों द्वारा सिलिकोसिस के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए। पीठ ने कहा, 'चिंता का दूसरा पहलू यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित श्रमिकों या उनके स्वजन को जल्द से जल्द उचित मुआवजा प्राप्त हो। इस संबंध में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को संबंधित राज्यों की मुआवजा प्रक्रिया की निगरानी का निर्देश देते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम व संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि मुआवजा वितरण प्रक्रिया कुशलतापूर्वक व अविलंब पूरी हो।' कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़ी सभी रिपोर्टें एवं हलफनामे एनजीटी एवं एनएचआरसी को भेजे जाएं ताकि वे अपनी जिम्मेदारी तेजी से निभा सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने पीपुल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर की 2006 की याचिका निपटा दी।

जागरण विशेष

कैंसर की पहचान व निदान करेगा आइआइटी का शोध

कैंसर कोशिकाएं कहां तक फैलीं इस बारे में पता लगा सकेंगे, शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित, पेटेंट की प्रक्रिया भी पूरी

उदय जगताप • जागरण

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली ने एक ऐसा शोध किया है, जोकि न केवल कैंसर की पहचान करेगा बल्कि उसके निदान की राह भी खोलेगा। आइआइटी दिल्ली में रसायन विभाग के विज्ञानियों ने जैविक अमीनो फुल्विन मालिक्यूल खोजा है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कैंसर कोशिकाएं किसी व्यक्ति के शरीर के किस हिस्से में किस स्तर तक फैलीं हैं। यह शोध नेचर जर्नल में प्रकाशन हो चुका है और इसके पेटेंट की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

आइआइटी दिल्ली के रसायन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख शोधकर्ता प्रो. रवि पी सिंह के अनुसार जैविक अमीनो फुल्विन छोटे अणुओं का समूह होता है। इसे खोजने के लिए सामान्य तौर पर मिलने वाले अमीनो एसिड की प्रकृति में बदलाव किए गए हैं। इसमें किसी तरह के विषैले पदार्थ, अपाकृतिक धातु या उत्प्रेरकों का उपयोग नहीं किया गया है। इसे एक स्टेप में ही तैयार किया गया है। आमतौर पर इसको बनाने में विषैली धातुओं का उपयोग होता है, लेकिन यह पूरी तरह से आर्गेनिक है। आइआइटी दिल्ली की ही लैब में किए गए इस शोध को एक वर्ष लगा है। हालांकि, क्लीनिकल ट्रायल अभी शेष है।

चुनौतीपूर्ण थी आर्गेनिक तरीके से खोज: अमीनो फुल्विन खोजने के बाद वायरल और कई तरह की एंटीबाडी के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन कैंसर की कोशिकाओं को ढूंढने के मामले में यह काफी असरदार साबित हुआ है। देश में यह अपनी तरह की पहली खोज है। आइआइटी दिल्ली के दो छात्र संजय सिंह, रवि सैनी के साथ में शोध करने वाले प्रो रवि बताते हैं कि हम एंजाइमों, डाइपेप्टाइड्स से अधिक प्रेरित थे। ये दोनों धातु आयनों की अनुपस्थिति में आसानी से रासायनिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जानी जाती हैं, पर ऐसे उत्प्रेरक संक्रमित धातुओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में आर्गेनिक तरीके से खोज एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। बायो-टेक्नोलाजी के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी सफलता है।

आइआइटी दिल्ली की रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में शोध कार्य को लेकर छात्र रवि सैनी (बाएं) से चर्चा करते रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रवि पी सिंह • सौजन्य प्रोफेसर रवि पी सिंह

नए शोध का खुलेगा रास्ता

शोध की विशेषता पर प्रो. रवि बताते हैं कि टी-ल्यूसिन पदार्थ के साथ अभिक्रियाएं करने के बाद अमीनो फुल्विन बनाया गया है। इसे इंजेक्शन के जरिये कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है, जोकि विश्लेषण करके यह बता देगा कि कैंसर कोशिकाएं शरीर में कहां तक फैली हैं और कौन-कौन से हिस्से तक आगे बढ़ेंगी। इससे उसका उपचार करने में सुविधा होगी। यह निश्चित रूप से नए ड्रग की खोज, कृषि रसायन और कई अन्य उत्तम केमिकल्स बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। बायोलाजिकल साइंस के क्षेत्र में नए शोध का रास्ता भी इससे खुलेगा।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

धार कलेक्टर का वाट्सएप खाता बनाकर ठगी का प्रयास

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : शातिर बदमाश ठगी के नित नए तरीके अपनाने लगे हैं। मंगलवार को सिवनी कलेक्टर के नाम से फर्जी अकाउंट का मामला सामने आया था। बुधवार को उसी शातिर बदमाश ने धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का फर्जी वाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास किया। बदमाश किसी के साथ ठगी करता, उसके पहले ही जानकारी मिल गई। कलेक्टर ने इंटरनेट मीडिया पर फर्जी अकाउंट की जानकारी साझा की और लोगों को सतर्क रहने को कहा। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। बदमाश इतना शातिर है कि इसने कई कलेक्टरों को निशाना बना रखा है। 24 घंटे में एक ही नंबर से दो अलग-अलग कलेक्टर के फर्जी अकाउंट सामने आए हैं। मंगलवार को सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से गिफ्ट और पैसे की मांग की गई थी। ठग अंग्रेजी में मैसेज कर रहा था ताकि संदेह नहीं हो।

कन्नौज में थूक लगा चेहरे की मसाज करने वाला सैलून संचालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कन्नौज : सैलून पर आने वालों के चेहरे की मसाज थूक लगाकर करने का एक और वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। वीडियो उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के तालग्राम कस्बे का है। इसे सैलून संचालक मूक-बधिर मोहम्मद यूनुस सलमानी उर्फ बौरा द्वारा बनाया गया था। तालग्राम पुलिस ने एसपी के निर्देश पर शाम को मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।

तालग्राम के छिबरामऊ बस स्टाप पर जेरकिला निवासी यूनुस का सैलून है। बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर उसके सैलून का एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें दिख रहा है कि एक ग्राहक आंखें बंद किए है और यूनुस थूक लगाकर उसके चेहरे की मसाज कर रहा है। वीडियो प्रसारित होने पर स्थानीय लोग भड़क गए। उसके सैलून पर पहुंचे तो देखा वह ताला बंद करके फरार है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग सहमंत्री पंकज मिश्रा ने पदाधिकारियों के साथ एसपी अमित कुमार आनंद से भेंट कर कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आशू तिवारी ने भी आक्रोश जताया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने जन भावनाएं आहत करने की रिपोर्ट दर्ज करके यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है। इससे पूर्व पश्चिमी उप्र में भी ऐसे मामले सामने आए थे।

मसाज के दौरान मुंह से थूक निकालता यूसुफ। वीडियो ग्रैब

****

दैनिक जागरण

पराजय में भी अगली विजय के लिए सबक छिपा होता है

ओलिंपिक में अनहोनी

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेरिस ओलिंपिक में पदक की सुनिश्चित दावेदार विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य करार दी गईं। उनसे स्वर्ण पदक की आशा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले के सभी मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कई नामी पहलवानों को हराया था, लेकिन अंतिम मुकाबले के कुछ घंटे पहले उनका वजन सौ ग्राम अधिक पाया गया। इसके साथ ही उनका सपना तो टूटा ही, देशवासियों की आशाओं पर भी तुषारापात हो गया। चूंकि एक तरह से हाथ आया पदक फिसल गया, इसलिए अफसोस अधिक है। यह होना भी चाहिए, लेकिन इस प्रसंग से सबक भी लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो। इस ओलिंपिक में विनेश ने 53 किलोग्राम के अपने स्वाभाविक भार वर्ग को छोड़कर 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ना तय किया था। इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद वह अपने वजन को नियंत्रित रखने का उतना अभ्यास नहीं कर पाईं, जितना आवश्यक था। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के मानकों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी जितनी किसी खिलाड़ी की होती है, उतनी ही उसके कोच और सपोर्ट स्टाफ की भी। विनेश के मामले में कहां क्या चूक हुई, इसकी जवाबदेही उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ की है। उन्होंने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा है और यह स्पष्ट किया है कि विनेश का वजन नियंत्रित रखने के लिए वह सब कुछ किया गया, जो संभव था, लेकिन आखिर कहीं तो कुछ भूल-चूक हुई ही। यह किन कारणों से हुई, यह सामने आना चाहिए।

विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने और इस तरह भारत के पदक से वंचित होने पर देशवासियों की ओर से अपनी निराशा व्यक्त किए जाने के बीच कुछ नेताओं की ओर से जैसे अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं, वे उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शा रहे हैं। यह समझ आता है कि उन्हें न खेल की जानकारी है और न ही खेल के नियमों की, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे जो मन में आए, वह बोल दें। कोई विनेश के साथ साजिश की कहानी गढ़ रहा है तो कोई उन्हें अयोग्य करार देने में किसी नेता का हाथ देख रहा है। यह सब इसीलिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ धरना-प्रदर्शन में भाग लिया था। निःसंदेह विनेश का मुकाबले से बाहर हो जाना और उन्हें कोई पदक न मिलना आहत करने वाला है, लेकिन खेलों के अपने नियम होते हैं। वे हमारे या किसी अन्य के हिसाब से नहीं बन सकते। विनेश के मामले में साजिश की कहानियां गढ़ रहे लोग इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी पसंद का सपोर्ट स्टाफ था। इस मामले में कम से कम नेताओं की प्रतिक्रियाएं जगहंसाई कराने वाली नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है।

बच सकेंगी जानें

बिहार में दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से वे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस आशय का निर्देश राज्य के सभी सिविल सर्जन, निजी और सरकारी अस्पतालों को भेजा गया है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है और निश्चित तौर पर इससे सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम किए जाने में मदद मिलेगी। अभी बिहार में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। यहां सड़क हादसों के 78 प्रतिशत मामलों में घायलों की जान चली जाती है। मिजोरम के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य है, जहां इतनी ज्यादा जनहानि होती है। इन मौतों में तभी कमी लाई जा सकती है जब घायलों को समय पर उपचार मिल जाए। अभी अस्पताल ले जाने के बाद तमाम औपचारिकताओं में वक्त जाया होता है। ज्यादातर अस्पताल मरीज की तीमारदारी शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि इलाज का पैसा कौन देगा। उम्मीद है कि इस आदेश के बाद अस्पताल बिना वक्त बर्बाद किए घायलों का उपचार करेंगे और कई परिवारों को जिंदगी भर मिलने वाले दर्द से दूर रखने में कामयाब होंगे। इस आदेश का ज्यादा से ज्यादा प्रचार भी किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि घायलों की मदद कर अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ना होगा। पैसे के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। लोगों को तो यह भी नहीं पता कि घायलों को मदद पहुंचाने वालों को सम्मानित तक किया जाता है। जाहिर तौर पर इसका प्रचार प्रसार होगा तो घायलों को मदद पहुंचाने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही राज्य में ट्रामा सेंटर व एंबुलेंस की व्यवस्था को भी और सघन किए जाने की जरूरत है। एनएच किनारे एंबुलेंस की संख्या बढ़ेगी तो शीघ्र से शीघ्र घायलों को डाक्टर के पास ले जाया जा सकेगा। गोल्डन आवर में समय पर इलाज शुरू हो जाए तो कई घायलों का जीवन बचाया जा सकता है।

अस्थिर पड़ोसियों से घिरता भारत

ऋषि गुप्ता

बांग्लादेश में तख्तापलट और अराजकता के साथ ही दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है। यह स्थिति भारत के हित में नहीं

बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के मुद्दे पर भारतीय संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि पांच अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ बैठक के बाद स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया और 'कुछ समय के लिए' उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत में हैं और माना जा रहा है कि वह किसी तीसरे देश में शरण मिलने तक यहीं रहेंगी। यदि इस हालात को भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक असाधारण स्थिति है, जहां भारत को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जिसमें पड़ोसी प्रथम नीति के तहत मदद भी करनी है। बांग्लादेश में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कोई अनधिकृत रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम से देश के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा स्थिति पैदा हो गई है। भारत के समक्ष 1971 वाली स्थिति फिर एक बार बन पड़ी है। बांग्लादेश में रह रहे तमाम अल्पसंख्यक समूह खासकर बड़ी संख्या में हिंदू भारत में शरणार्थी के तौर पर आने की गुहार लगा सकते हैं। इससे बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं।

अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता है, जिसकी भरी-पूरी आशंका है तो भारत की चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ गुटों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। इसके चलते ये लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे हैं। पाकिस्तान आज तक भारत को अपने विभाजन यानी बांग्लादेश के निर्माण का कारण मानता रहा है और वह कोशिश करेगा कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी और असामाजिक तत्वों को सक्रिय किया जाए। बांग्लादेश में अराजकता के बीच दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है, जो भारत के हित में बिल्कुल नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए चौतरफा चुनौतियां बढ़ रही हैं। बीते दिनों ही नेपाल में चीन समर्थक सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे हैं। ओली को 'इंडिया आउट' अभियान का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है और हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी राजनीतिक साख मजबूत करने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा शांत नहीं होने दिया है। चूंकि ओली की 'राष्ट्रवादी छवि' भारत विरोध से बनी है, लिहाजा भारत के लिए जरूरी है कि वह स्थिति पर नजर रखे। यदि नेपाली जनता पुरानी पार्टियों और पुराने नेताओं की कार्यशैली से ऊबती है तो 2006 जैसा जन आंदोलन छिड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका सीधा असर खुली सीमा के चलते भारत पर होगा। नेपाल के बगल में ही भूटान है, जो पूरी तरह से भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर फिक्रमंद है और एक मित्रतापूर्ण सहयोगी रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन ने वहां भी अपनी पैठ बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद भारत के लिहाज से भूटान में स्थिति नियंत्रण में है।

अवधेश राजपूत

पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार में भी दबावपूर्ण और अनिश्चित राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। यहां विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन को कमजोर करने में सफल हो गए हैं। यहां अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का सिलसिला कायम है, जिसके चलते भारत की सुरक्षा एजेंसिया भारत-म्यांमार सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। यदि बांग्लादेश और म्यांमार की तानाशाही ताकतें चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव में आकर भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश में साथ आती हैं तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। नई दिल्ली के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी लुक-ईस्ट और एक्ट-ईस्ट नीति में सुरक्षा पहलुओं को भी शामिल करे। म्यांमार में आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। यह सही है कि श्रीलंका धीरे-धीरे भारत और आइएमएफ की मदद से आर्थिक मुसीबतों से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी भी वहां भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। मालदीव भी इस मामले में अलग नहीं, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोध में लगे हुए हैं। उन्होंने भी ओली की तरह 'इंडिया आउट' अभियान चलाया, फिर वह चाहे भारतीय सैन्य अधिकारियों का मालदीव से भारत वापस भेजने का मुद्दा रहा हो या फिर उनकी सरकार के मंत्रियों का भारत और भारत के प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ टीका-टिप्पणी का मामला।

पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पहले से ही भारत के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हाल में जम्मू में हुए आतंकी हमलों ने भारत की चिंता बढ़ाने का काम किया है। यदि पड़ोसी देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत इन सभी देशों की सीमाओं के जुड़े होने के कारण एक प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है, जो आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। दक्षिण एशिया में बड़े लंबे समय से भारत की केंद्रीयता को सभी समस्याओं की जड़ माना जाता रहा है और भारत पर लगभग सभी पड़ोसी देश हस्तक्षेप का आरोप भी लगाते आए हैं, लेकिन क्या अब यही देश अपनी आंतरिक हलचल के चलते भारत के सामने मौजूद सुरक्षा संकट पर नई दिल्ली के साथ खड़े होंगे? इसका जवाब संभवतः नकारात्मक ही मिले। दक्षिण एशिया में जैसी असामान्य परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनका सामना करने के लिए भारत को असाधारण प्रयास करने की आवश्यकता है।

भारत को हर कीमत पर अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है और पड़ोसी देशों में सिविल सोसायटी समूहों के साथ मिलकर शांति बहाली के प्रयासों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों और क्षेत्र में मौजूद समान विचारधारा वाली शक्तियों जैसे अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के लिए भी जरूरी है कि वे भारत की चिंताओं को समझें और अपने स्तर पर पाकिस्तान और चीन पर दबाव डालें, ताकि ये दोनों देश दक्षिण एशिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत को परेशान करने के लिए नई तिकड़में न कर सकें।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

युवाओं में कौशल विकास की चुनौती

डा. सुरजीत सिंह

यह समझा जाना बहुत आवश्यक कि अपने देश में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है

बढ़ाने होंगे रोजगार के अवसर। फाइल

बजट पेश होने के बाद उसके प्रस्तावों पर अमल की दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में सभी की निगाहें रोजगार सृजन की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर टिकी हैं, जिन्हें हालिया बजट का सबसे विशिष्ट पहलू माना जा रहा है। कौशल, नवाचार और रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विशेष प्रविधान किए हैं। इसमें इंटर्नशिप योजना को खासी चर्चा भी मिली है। इससे न केवल रोजगार के आकांक्षियों के हितों की पूर्ति होगी, बल्कि उद्योगों को भी अपने अनुकूल कौशल से लैस लोग मिलेंगे। इससे न सिर्फ भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, बल्कि निवेश संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे सरकार की यह मंशा भी प्रकट हुई है कि अगले पांच वर्षों में वह रोजगार, कौशल और एमएसएमई पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को भुनाने की राह में कार्यशील आबादी में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी न होने का संज्ञान भी सरकार ने लिया है। इसके लिए कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थल के निकट महिला हास्टलों और शिशु देखभाल गृहों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही महिला श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी फोकस किया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में भी उल्लेख है कि देश में बढ़ते कार्यबल के समायोजन के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करनी होंगी। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई। बजट में युवाओं और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। कुल मिलाकर, पांच साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं को शिक्षित, कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। विनिर्माण क्षेत्र में भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए बजट में प्रविधान है कि पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को शुरुआती चार वर्षों में ईपीएफओ में योगदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है। नियोक्ताओं को सहायता देते हुए यह उपाय भी किया गया है कि सभी क्षेत्रों में प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के संबंध में नियोक्ता के ईपीएफओ में अंशदान के लिए उन्हें दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्री की यह पहल औपचारिक रोजगार सृजन की दिशा में स्वागतयोग्य कदम है, जिससे सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिकता के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी। इससे अधिक स्नातकों को नौकरी के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।

भारत में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है। बढ़ती श्रमशक्ति और कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन की दृष्टि से पांच वर्षों में देश की 500 दिग्गज कंपनियों द्वारा एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना एक बाजी पलटने वाली योजना सिद्ध हो सकती है, लेकिन तभी जब कंपनियां इस योजना में रुचि दिखाएं। इस योजना में 5,000 रुपये के मासिक भत्ते और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता आकर्षक पहलू हैं। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य पांच वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल प्रदान करना है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्रदान करने के साथ ही हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के तीन प्रतिशत ब्याज में छूट भी मिलेगी। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 1000 आइटीआइ को और अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाया जाएगा। उद्योगों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ही विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे नई उभरती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक भी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर जोर देने से इस क्षेत्र को संजीवनी मिलने के आसार हैं। प्रत्येक वर्ष 25,000 कुशल व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपये तक का गारंटीकृत ऋण प्रदान करना निश्चित रूप से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा। मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने से इस क्षेत्र की तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी सराहनीय है। पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से ई-कामर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार की गंभीरता इससे भी स्पष्ट होती है कि रोजगार और कौशल विभाग का नाम भी बदलकर कौशल, रोजगार और आजीविका कर दिया है। बजट में एक लाख करोड़ रुपये से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन से आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, केंद्र के स्तर पर तमाम पहल तभी सफल हो पाएंगी, जब राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस दिशा में अपेक्षित प्रयास करेंगी। इन कार्यक्रमों को यदि गंभीरता से लागू किया जाता है तो भारत को एक अग्रणी स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संबंधों की सजीवता

किसी की संगति में ही उस व्यक्ति के प्रति गहरी समझ और संवेदना विकसित होती है। यह मेलजोल प्रायः लोगों की समान रुचियों, सोच और जीवन की दिशा पर आधारित होता है। एक दूसरे के सान्निध्य और संगति में दोनों एक-दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और एक मजबूत संबंध की नींव रखते हैं। यह संबंध तब फलता-फूलता है, जब दोनों पक्ष एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे के महत्व को समझते हैं। स्मरण रहे कि कोई भी संबंध सब कुछ सह लेता है, लेकिन उपेक्षा नहीं सह सकता है। समय के साथ व्यक्ति का सोच और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। कभी-कभी ये बदलाव धीरे-धीरे व्यक्ति को अपने पूर्व संबंधों से दूर भी कर देते हैं। किसी नई जिम्मेदारी या नई रुचियों के कारण व्यक्ति पुरानी मित्रता को उतना समय और महत्व नहीं दे पाता है,जितना पहले देता था। इस प्रक्रिया में वह दूसरे व्यक्ति को उपेक्षित महसूस करा सकता है। प्रायः व्यक्ति को उस संबंध में वह अनुभूति नहीं मिलती, जो पहले अनुभव होती थी। जब किसी संबंध में नवीनता समाप्त हो जाती है, तो उदासीनता का भाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति उस संबंध को महत्व देना बंद कर देता है।

इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने संबंधों के प्रति संवेदनशील रहे। अगर किसी संबंध में कोई परिवर्तन आता भी है तो इसे ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद के माध्यम से व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है और उनके महत्व को पुनः स्वीकार कर सकता है। संबंधों में उतार-चढ़ाव और परिवर्तन सामान्य हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को महत्व देना और उसकी उपेक्षा न करना हमारे संबंधों की मजबूती के लिए एक आवश्यक अवयव है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

भुखमरी खत्म करने की जरूरत

रवि शंकर

यह कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है

दुनिया में आज हर 11वां इंसान खाली पेट सोने को मजबूर है। दुनिया में 73.3 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। यदि 2019 की तुलना में देखें तो इन लोगों की संख्या में 15.2 करोड़ का इजाफा हुआ है। यह जानकारी 'द स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024' नामक रिपोर्ट में सामने आई है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से प्रकाशित की है।

साफ है भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी दुनिया को एक लंबा रास्ता तय करना है। यह कैसी विडंबना है कि एक ओर हमारे और आपके घरों में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है और वे भूख से जूझ और मर रहे हैं। दुनिया भर में हर साल जितना भोजन तैयार होता है, उसका लगभग एक-तिहाई बर्बाद हो जाता है। बर्बाद किया जाने वाला खाना इतना होता है कि उससे दो अरब लोगों के भोजन की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। दुनिया में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही लोगों में खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। खाद्यान्न की क्षति और बर्बादी न केवल संसाधनों के कुप्रबंधन का मुद्दा है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान देती है। खाद्य एवं कृषि संगठन का अनुमान है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आठ प्रतिशत के लिए खाद्य अपशिष्ट भी जिम्मेदार होते हैं।

ऐसा नहीं है कि दुनिया में इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी धन और संसाधनों की कोई कमी है, दरअसल समस्या आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की है। वर्तमान समय में हर देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्पविकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं तो वहीं विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए देशों की सरकारें प्रयास भी करती हैं और विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धियों को गिनाती हैं। यहां तक कि विकास दर के आंकड़े से यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है कैसे आगे बढ़ रहा है? ऐसे में जब कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए जो आपको यह बताए कि अभी तो देश 'भूख' जैसी 'समस्या को भी हल नहीं कर पाया है, तब विकास के आंकड़े झूठे लगने लगते हैं। यह कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भारत को रहना होगा सतर्क

'अराजकता में डूबा बांग्लादेश' शीर्षक से लिखे आलेख में दिव्य कुमार सोती ने आशंका जाहिर की है कि चीन और अमेरिका जैसे देश बांग्लादेश को अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। वहां उन्हें कठपुतली सरकार मंजूर थी। चूंकि चीन अधिनायकवादी देश है तो यह बात समझ में आती है, मगर अमेरिका जो पुराने लोकतंत्रों में से एक है। उसे तो बांग्लादेश में लोकतंत्र प्रेमी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए था। उसे भारत का भी ध्यान रखना चाहिए था, जिससे उसके मित्रतापूर्ण संबंधों के कई फायदे हैं। बहरहाल यह देखने वाली बात है कि उन राष्ट्रों में लोकतंत्र कभी सफल नहीं रहा, जहां मजहबी कट्टरपंथी ताकतें मजबूत रही हैं। लिहाजा लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी भी तरह के कट्टरपंथ को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। जहां कट्टरपंथ अपना सिर उठाता है या उठाने की आशंका रहती है, वहीं विदेशी महाशक्तियों के दखल संभव होते हैं। भारत को नई परिस्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित हो

बांग्लादेश में रह रहे डेढ़ करोड़ हिंदुओं और 19,000 भारतीयों की सुरक्षा चिंतनीय विषय है। सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि हिंसा और आगजनी पर आमादा कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी के समर्थक और तख्तापलट करने वाले तत्वों के साथ भारत सरकार का कोई संपर्क भी नहीं है। यही स्थिति पाकिस्तान में दशकों से है और इसी कारण हिंदुओं के साथ बड़े स्तर पर हिंसा हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या नगण्य होती जा रही है। यह तब की स्थिति है, जब बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा 95 प्रतिशत भारत से घिरी हुई है। ऐसी भौगोलिक स्थिति चीन के साथ होती तो चीन बांग्लादेश को निगल गया होता। वैश्विक मुस्लिम कट्टरपंथी राजनीति अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा पर केंद्रित है। इसलिए जहां भी इस्लामिक राष्ट्रों में कट्टरपंथी सरकारें हैं वहां हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हिंसा लगातार होती है। उनके मंदिर और चर्च नष्ट किए जाते हैं। भारत को इस विषय में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा और भारत के विपक्षी दलों को भी वोटबैंक की राजनीति को छोड़कर विश्वभर में हिंदुओं की सुरक्षा के हित सुरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। इस्लामिक व्यवस्था में उनका भी कोई वजूद नहीं है। जब तक हिंदू हैं तभी तक उनका भी अस्तित्व है। किसी वामपंथी, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी पार्टी का किसी इस्लामिक देश में कोई वजूद ही नहीं है। भारत में सबसे अधिक मुस्लिम हैं और सौभाग्यवश चैन से हैं अन्यथा शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोहरा के कुचक्र के दमनचक्र के शिकार हो रहे होते। भारत को सभी इस्लामिक देशों में हिंदुओं को भारतीय नागरिकता दे देनी चाहिए, जिससे वह आपत्ति के समय भारत वापस आ सकें। बांग्लादेश का जो भी भविष्य हो लेकिन दीर्घ समय तक वहां अस्थिरता रहेगी। उसको चीन और अमेरिका के लिए अपने धरती पर युद्ध भूमि तैयार करने की चुनौती है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

अराजकता में डूबा बांग्लादेश

चीन, अमेरिका और पाकिस्तान को पता है कि बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार की दोस्ती नई दिल्ली से गहरी थी। शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंध बाधित हो सकते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अहम सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच अच्छा-खासा व्यापार होता रहा है। शेख हसीना के जाने से दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती मिल सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। मसलन तीस्ता सिंचाई परियोजना पर चीन अपनी नजर जमाए हुआ था, लेकिन भारत के इसमें सहयोग के आफर से शेख हसीना ने अपनी नीतियां भी बदलीं। युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

1931 में देश में पहली बार हुई थी जातीय जनगणना, लेकिन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और एक किस्म के विभाजनकारी नजरिये से बचने के उद्देश्य से जातियों से जुड़ी गणना को वर्ष 1951 से बंद कर दिया गया।

आजकल

सवालों के घेरे में टलती जनगणना

विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा तो यह है कि आखिर हमारे देश में सामान्य जनगणना कब होगी जिसमें काफी विलंब हो चुका है। वर्ष 2011 के बाद हमारे देश में जनगणना कराई ही नहीं गई है। जनगणना केवल जनसंख्या वृद्धि ट्रैकर नहीं है, बल्कि यह देश की नीतियां तय करने के लिए व्यापक सामाजिक-आर्थिक डाटा प्रदान करती है। इस डाटा का उपयोग नीति-निर्माण के अलावा आर्थिक नियोजन और विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर,
बेनेट यूनिवर्सिटी

जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं-लिंग, आयु, आय, व्यवसाय, प्रवासन पैटर्न आदि जानकारियों का सबसे बड़ा भंडार है जनगणना। फाइल

इन दिनों जातीय जनगणना की मांग को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। इस बीच कुछ सवाल जनगणना में हो रहे विलंब को लेकर उठ रहे हैं। आखिर देश में सामान्य जनगणना कब होगी? पिछले वर्ष अप्रैल में जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत को चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला मुल्क घोषित किया था, तो सबके मन में यह सवाल उठा था कि आखिर इस जनसंख्या का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने कैसे लगाया है? वजह यह है कि वर्ष 2011 के बाद हमारे देश में जनगणना कराई ही नहीं गई है। यानी पिछली जनगणना को अब करीब डेढ़ दशक होने को है। हालांकि 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष तिथि पर जनगणना करने या निश्चित अवधि में संबंधित डाटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता, लेकिन सामान्यतः दस वर्षों के अंतराल के कायदे के तहत यह जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी। कोविड महामारी के प्रकोप के कारण यह दशकीय जनगणना समय पर नहीं कराई जा सकी। उल्लेखनीय है कि जनगणना केवल जनसंख्या वृद्धि ट्रैकर नहीं है, बल्कि यह देश की नीतियां तय करने के लिए व्यापक सामाजिक-आर्थिक डाटा प्रदान करती है। इस डाटा का उपयोग नीति-निर्माण के अलावा आर्थिक नियोजन और विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह भारतीय जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं-लिंग, आयु, आय, व्यवसाय, प्रवासन पैटर्न आदि पर सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा भंडार है। जनगणना का महत्व इससे समझा जा सकता है कि हमारे देश के प्रत्येक गांव, कस्बे और वार्ड के लिए प्राथमिक डाटा का यह जनगणना एकमात्र स्रोत है, लेकिन जनगणना करने में हुए इस विलंब की वजह से एक बड़ा डाटा-अंतर पैदा हो गया है।

नई तारीख पर उलझा पेच : जनगणना में हुए विलंब के बारे में सरकार समय-समय पर अपना पक्ष रखती रही है। जैसे 16 सितंबर, 2020 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया था कि कोविड महामारी के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना और इससे संबंधित क्षेत्रीय गतिविधियों को ''अगले आदेश तक'' स्थगित कर दिया गया है। दिसंबर 2023 में संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब में यही कारण सुझाया गया था। उल्लेखनीय है कि जनगणना का काम आमतौर पर प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने के तीन महीने बाद शुरू होता है। इस बारे में 30 दिसंबर, 2023 को भारत के अतिरिक्त महापंजीयक ने राज्यों को सूचित किया कि जिलों, तहसीलों, कस्बों आदि की प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा एक जनवरी, 2024 थी। गौरतलब है कि इस दौरान किया गया यह नौवां ऐसा विस्तार था। इसलिए जनगणना का काम अब अक्टूबर 2024 से पहले शुरू नहीं हो सकता है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र को मिली जानकारी का सवाल है, तो इसकी जनसंख्या कोष इकाई ने वैश्विक जनगणना का जो ट्रैकर बनाया है, उसके अनुसार 150 देशों ने 2020 और 2021 में अपनी जनगणना करने का कार्यक्रम बनाया था। इनमें से चीन, बांग्लादेश, नेपाल सहित 94 देशों ने महामारी के दौरान ही अपनी जनगणना पूरी कर ली थी। 52 देशों ने जनगणना को नई तिथि के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन भारत उन तीन देशों में शामिल है, जिसने बिना नई तिथि के जनगणना को स्थगित कर दिया था। उम्मीद है कि जनगणना का यह काम हमारे देश में अक्टूबर 2024 के बाद शुरू हो सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद अब राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों (समुदायों) को अलग-अलग वर्गों में बांटने का अधिकार हासिल हो गया है। उपवर्गीकरण की इस आवश्यकता का संदर्भ यह है कि पिछड़े समुदायों में सदियों से उत्पीड़न का सामना कर रही कुछ ऐसी श्रेणियां या समूह ऐसे हैं, जिन्हें आज भी अत्यधिक भेदभाव झेलना पड़ रहा है। राज्यों को उपवर्गीकरण का अधिकार मिलने से अब ऐसे समूहों-श्रेणियों से संबंधित लोग आरक्षण में समुचित प्रतिनिधित्व हासिल कर सकेंगे, जिससे उनका विकास हो सकेगा। हालांकि अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उपवर्गीकरण पर राज्य सरकारें अपनी मनमानी नहीं करें, बल्कि यह कार्य राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए भी जनगणना जरूरी है।

जनगणना का एक सामाजिक-राजनीतिक पहलू वह है, जिसकी चर्चा हाल में जातीय जनगणना की मांग और औचित्य के साथ जोरशोर से उठी है। असल में राजनीतिक निहितार्थों से परे देखें तो जातीय जनगणना का एक औचित्यपूर्ण इतिहास रहा है। ऐसी पहली सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना पहली बार वर्ष 1931 में की गई थी। अभाव के संकेतकों की पहचान करने के उद्देश्य से यह जातीय जनगणना देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बसे भारतीय परिवारों की आर्थिक हैसियत का पता लगाने के लिए की गई थी। यही नहीं, इसके तहत विभिन्न जाति समूहों की माली हालत का अंदाजा लेने के लिए विशिष्ट जाति नामों के आधार पर डाटा जमा किया गया था। सामान्य जनगणना से जातीय जनगणना इस मामले में अलग होती है कि इसके आंकड़ों का उपयोग राज्य सरकारें जाति आधारित अपेक्षा और पिछड़ेपन का आकलन कर संबंधित समुदायों को दी जाने वाली मदद के लाभार्थियों की पहचान कर सकें। वैसे तो सामान्य जनगणना के आंकड़े गोपनीय होते हैं, लेकिन जातीय सूचनाओं पर आधारित गणना के आंकड़े राज्यों को देने का प्रविधान था। सरकारें इनसे मिली सूचनाओं के आधार पर वांछित परिवारों को सरकारी विभागों से मदद देने या उन्हें पहले से दी जा रही सहायता या लाभ से वंचित करने के लिए कर सकती थीं। जैसे क्रीमी लेयर में आने वाली जातियों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है। निश्चय ही जातीय जनगणना का एक महत्व रहा है, लेकिन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और एक किस्म के विभाजनकारी नजरिये (समाज को जातियों में बांट कर देखने के दृष्टिकोण) से बचने के उद्देश्य से जातियों से जुड़ी गणना को वर्ष 1951 से बंद करने का फैसला लिया गया, परंतु हाल के दशक में जिस प्रकार सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन आया है, जातियों से जुड़ी सटीक सूचनाओं और आंकड़ों की जरूरत फिर महसूस हुई है। यही वजह है कि खासकर राजनीतिक दल पिछले कुछ वर्षों से लगातर जातीय जनगणना कराने की मांग उठा रहे हैं।

बहुत मुमकिन है कि सामाजिक-राजनीतिक दबावों के तहत केंद्र सरकार आने वाले वक्त में सामान्य जनगणना के साथ जातियों से जुड़े आंकड़ों का संग्रह भी कराए। यदि ऐसा किया जाता है तो ध्यान रखना होगा कि जाति संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए सामाजिक मतभेद गहराने और जातियों के ध्रुवीकरण के संबंध में नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना होगा कि एक बड़े लोकतंत्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के मकसद से की जाने वाली जातीय जनगणना सामाजिक बिखराव का नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने वाली हो।

जातीय जनगणना की मांग का औचित्य

देश की सामान्य जनगणना में यूं तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़े संकलित किए जाते हैं और उनका प्रकाशन भी होता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य समूहों की आबादी का कोई वास्तविक अनुमान नहीं जुटाया जाता है। इससे इन वर्गों के उपेक्षित और वंचित तबकों में आक्रोश की स्थिति है। इसकी वजह यह है कि आर्थिक पिछड़ेपन के अलावा सामाजिक पायदान पर नीचे होने के बावजूद उन्हें मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे तबकों के आक्रोश के मद्देनजर ही कुछ राजनीतिक दल जातीय जनगणना की पुरजोर मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना का समर्थन एक और मसले को लेकर किया जा रहा है। दावा किया जाता है कि हमारे देश में जिस समुदाय के लिए आरक्षण या अन्य योजनाएं बनाकर जरूरतमंदों तक उनका लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है, उनसे संबंधित आबादी के समुचित आंकड़े तक सरकार के पास नहीं हैं। इसके अलावा देश के बहुत से हिस्सों में आज भी जाति-आधारित भेदभाव कायम है। इसे दूर करने के उपाय तभी कारगर हो सकते हैं, जबकि जातिगत जनगणना के जरिये वंचित जातियों, समुदायों और समूहों की सही पहचान की जाए और उनके आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाते हुए उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। जाति समूहों के वितरण और उनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ठोस अनुमान लगाकर सामाजिक असमानता दूर करने के लिए नीतियां लागू की जा सकती हैं और वंचित समुदायों का उत्थान सुनिश्चित किया जा सकता है। ध्यान रखना होगा कि चूंकि देश में कुछ वंचित समुदायों के लिए पहले से आरक्षण व्यवस्था लागू है, इसलिए जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों-समूहों की जातीय जनगणना आधारित सटीक आंकड़े नहीं मिलेंगे, संसाधनों का समान वितरण करना संभव नहीं होगा। इनसे संबंधित आंकड़े मिलने के बाद प्रत्येक जातीय समूह की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करते हुए नीति-निर्माताओं को उनके समावेशी विकास की जरूरत साधने का रास्ता मिल सकता है। अच्छा यही होगा कि इस मुद्दे का राजनीतीकरण करने के बजाय वंचित समुदायों की वास्तविक पहचान की जाए। यदि ऐसा किया गया तो जातीय जनगणना के रास्ते आरक्षण व्यवस्था में होने वाला कोई सुधार अंततः देश और समाज के समुचित विकास का जरिया ही साबित होगा।

-डा. संजय वर्मा

खरी-खरी

बच्चों हम शर्मिंदा हैं...

डा. हरीशकुमार सिंह

गत दिनों मध्य प्रदेश के सागर के एक ग्रामीण इलाके में नौ बाल शिव भक्तों की अकाल मृत्यु हो गई। ये बच्चे एक मकान की जर्जर दीवार के ढहने से मलबे में दबकर मर गए। मर गए या मार डाले गए यह कभी भी तय नहीं हो पाएगा। ऐसे हादसों की जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं। न तो यह घटना-दुर्घटना नई है और न ही हम सबका कोहराम मचाना पहली बार है। माता के पेट में भ्रूण हत्या करने वाले हम विलाप किस बात का कर रहे हैं? सरकारी योजनाएं तो भरपूर हैं, मगर पता नहीं क्यों बच्चों का पेट तो नहीं भरता, बल्कि माननीयों के पेट जरूर वटवृक्ष हुए जा रहे हैं। इसलिए बच्चे चाहे दबकर मरें, किसी अनजान बीमारी से मरें या कुपोषण से क्या फर्क पड़ता है।

और तो और स्कूल के लिए छोटे वाहनों में भेड़-बकरियों की तरह ठूंसे जाने पर भी दुर्घटनाओं में बच्चे मर रहे हैं। हम खुले बोरवेल को भी बंद नहीं कर पा रहे और कोई न कोई प्रिंस खेल खेल में इनमें समा कर जान दे रहा है। बच्चा जिंदा भी रहे तो कौन उसके साथ कुकर्म-दुष्कर्म कर डाले और मार डाले, कोई देखने वाला है क्या। जनसंख्या नियंत्रण का यह अघोषित फार्मूला तो बरसों से चल रहा है। यह जरूर है कि ऐसा कोई हादसा होने पर हम कुछ क्षणों के लिए जागृत हो जाते हैं और व्यवस्था को कोसने की कवायद चालू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। इसी कारण हम जहां थे वहीं तो खड़े हैं।

भविष्य में अब कोई और बच्चा न मरे इसके लिए हम नागरिकों को आगे आना होगा, क्योंकि जिनको इसकी जिम्मेदारी है वे इसे सही से निभा नहीं रहे हैं। अब यह कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं...नहीं, यह काम हमारा नहीं है। आमजन के लिए दो चीजें अधिक जरूरी हैं-एक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा। दुर्भाग्य से दोनों ही भगवान के भरोसे हैं और उत्सवों की तरह हम आपदाओं-विपदाओं का भी त्योहारी रुदन कर रहे हैं। अगर सचमुच में हमें बच्चों की चिंता है तो फालतू का रोना धोना छोड़ें और कैंडल मार्च की जगह 'मशाल' उठाएं। सत्ता जागरण अभियान चलाएं या फिर भविष्य में बच्चों के मरने के समाचार और कहीं से आएं इसकी प्रतीक्षा करें।

X पोस्ट

अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है तो उनके मंदिरों की रक्षा क्यों और किससे करनी पड़ रही है?
हारिस सुल्तान@TheHarrisSultan

फलस्तीन के मसले पर लगातार बोल रहे देश के प्रमुख मुसलमानों से सवाल है कि क्या आपके पास अपने पड़ोस में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए एक शब्द है?
आमना बेगम अंसारी@Amana_Ansari

बांग्लादेश में फैली अराजकता की आड़ में बहुत से एक्स हैंडल बहुत ही धूर्तता से लिख रहे हैं, 'भारत में यह सब कब?' ऐसे सभी लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं। राष्ट्र के होने से हम सबका अस्तित्व है।
इमरान शकील खान@Imran_Shakeel_

विनेश फोगाट का 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण अयोग्य सिद्ध होना बेहद अफसोसनाक है। उनके अपने खून-पसीने के साथ पूरे देश के साधनों और आशाओं पर पानी फिरा है, लेकिन एक-दूसरे को कोसने में लगे नियमतोड़ मानसिकता वालों के लिए सबक है कि थोड़ा-बहुत चलता है का जुगाड़ बाकी दुनिया में नहीं चलता।
शिवकांत@shivkant

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए?

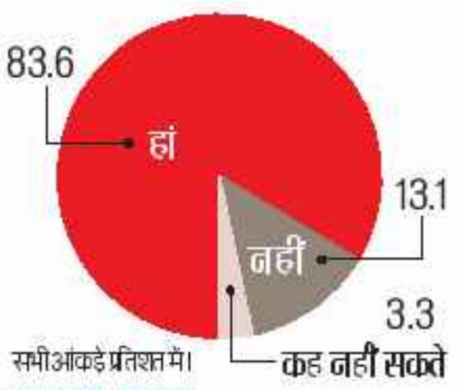

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जीएसटी वापस लेने की मांग सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

खेला ऐसा हो गया बिगड़ गया सब काम,
बाहर हुई विनेश जी वजन बढ़ा सौ ग्राम।
वजन बढ़ा सौ ग्राम हुआ ये इतना मुश्किल,
खुद विनेश के साथ देश का भी टूटा दिल।
दर्द दे गया आज बड़ा पेरिस का मेला,
बुरे स्वप्न सा याद रहेगा अब यह खेला।
- ओमप्रकाश तिवारी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक,
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश डायरी

देवभूमि की व्यथा-कथा

मैं हिमाचल प्रदेश! आपदा से जूझ रहा हूं, पर पहले से बेहतर हो रहा हूं। आप जानते हैं कि आपदा आने के बाद मौसम भले ही अगले दिन साफ हो जाए...वास्तव में, आपदा दशकों तक नहीं जाती। यह शरीर ही नहीं, हृदय पर भी छप जाती है। सच कहूं तो प्राकृतिक बताई जाती आपदा उतनी प्राकृतिक भी नहीं है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब कुछ दिन पहले एक महिला और उसकी गोद में छिपी दुधमुंही बच्ची के शव मिले। एक साथ कई स्थानों पर बादल फटे थे। बादल कोई कपड़ा नहीं कि अचानक फट जाए। यूं समझें कि बादल पानी से भरा हुआ था, पहाड़ से टकराया और एक ही स्थान पर इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई।

पहले भूकंप डराता था, कुछ दशकों से बादल डरा रहे हैं। हर नदी उफान पर होती है। 10 वर्ष में 20 बड़ी घटनाएं बादल फटने की हो चुकी हैं। इस बार कई लोगों की मौत हुई, 50 से अधिक लापता थे। कुछ के बाजू मिले रहे हैं, कुछ पता नहीं कब मिलेंगे। हर बार बादल बेशक नया फटता है, उसके बाद की पटकथा वही रहती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रतिपक्ष और समाज के स्तर पर। ऐसा लगता है जैसे हर वर्ष वही सब दोहराया जाता है, जो हो चुका होता है। कैसे? ऐसे, जैसे इस बार हुआ। आपदा आई, सरकारी तंत्र सक्रिय हुआ। मुख्यमंत्री, मंत्रिगण पहुंचे, प्रशासन पहुंचा। आपदा राहत की घोषणा हुई। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य दूरभाष पर संवाद हुआ और हरसंभव सहायता की मांग और आश्वासन मिला। उसके बाद पक्ष-प्रतिपक्ष की मुद्रा परस्पर ताने देने वाली हो जाती है।

मेरी एक सांसद हैं कंगना रनौत। उन्होंने पहले तो यह कहा कि उन्हें कुछ अधिकारियों ने कहा है कि वह अभी न आएं। स्थिति सामान्य होने पर ही आएं। यह ठीक है कि अति महत्वपूर्ण लोगों के आने से राहत एवं बचाव कार्य ही बाधित होते हैं, पर जहां इतने लोगों की जान गई हो, वहां भली बात भी बुरी तरह कहने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसा बहुत आता है, पर राज्य सरकार खर्च नहीं करती। इस पर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार पर विश्वास नहीं तो स्वयं बांट लें। मेरे अधिकारियों की बात करें तो वे इतने चुस्त हैं कि हिमाचल प्रदेश से बाहर का कोई व्यक्ति वेबसाइट पर कुछ देखना चाहे तो जारी आपदा पर कुछ नहीं मिलता, 1905 के भूकंप और दशकों पहले की बाढ़ से जुड़ी जानकारी अवश्य मिलती है। बाहर से व्यक्ति फोन करे तो कंट्रोल रूम का फोन नहीं उठता। आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री कहेंगे कि केंद्र से कुछ नहीं मिला और केंद्र या भाजपा सांसद कहेंगे कि बहुत कुछ मिला।

आपदा के घाव : रामपुर के समेज में आई बाढ़ में बहे स्वजन की याद में बिलखती महिला। जागरण

इस सबके बीच मेरी नदियों, खड्डों और नालों की बात कोई नहीं सुनता। ब्यास की गोद में क्यों घर या होटल बनते हैं, शिमला के नाले किसने रोके, सतलुज के किनारे निर्माण का क्या अर्थ है। कौन देता है अनुमति? कई बार सोचता हूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न हो तो मुझे कौन सुने। ब्यास पूछती है कि पिछले वर्ष नितिन गडकरी कह गए थे कि नदी को सीधा करेंगे...ब्यास ने फिर सबको सीधा कर दिया। आपदा में अवसर तलाशना है इसलिए मलबा दूर नहीं, वहीं आसपास ही रहता है, ताकि कोई धनवान बन सके। पहाड़ चेतावनी देता है कि शिमला, धर्मशाला और डलहौजी को दिल्ली मत बनाओ, जोशीमठ मत बनाओ...इन्हें पहाड़ ही रहने दो। मेरे पेड़ों की बात भी नहीं सुनी जाती। चीड़ के पेड़ क्यों आज तक नहीं हटाए गए। चौड़ी पत्ती वाले पेड़ क्यों तैयार नहीं हुए? बरसात से पहले सड़कों के किनारे की नालियां ठीक करने की औपचारिकता लोक निर्माण के दल पूरी करते हैं...वास्तव में झाड़ियों को पुचकारते हैं। उपायुक्त को रिपोर्ट जाती है कि बरसात के लिए सब तैयार हैं। कालांतर में वही रपट मुख्य सचिव को चली जाती है। पानी सड़कों पर आ जाता है और कार का रूपांतरण हो जाता है। वह स्टीमर बन जाती है। न कचरा निस्तारण के प्रबंध हैं और न अवैध या अनियोजित निर्माण को रोकने के लिए कोई मुस्तैदी। अवैज्ञानिक खनन एक अलग समस्या है मेरी। नदियों को खोखला कर रहे हैं एक्सकेवेटर आदि।

और इस सबमें वह क्या करता है जिसे आम आदमी कहते हैं। वह चुपचाप कचरा बोरी में भरता है, नदी या खड्ड में बहा आता है। उसे कोई न पूछे तो वह नदी में बाढ़ के अगले दिन दोबारा वहीं निर्माण कर सकता है। आप लोग, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश से आते हैं, कृपया कचरा न लाया करें। मेरी हरियाली को क्षति पहुंचाने के बाद यह कचरा पानी के माध्यम से आप तक ही पहुंचेगा। मैं आपकी प्राणवायु का हरा आश्वासन हूं...मेरे प्राणों पर तरस खाइए! आप तो अतिथि हैं, आपसे उतना गिला नहीं, जितना मेरे हितैषियों से है। जब शिक्षण संस्थानों की जमीन लेकर अधिक से अधिक पर्यटन की योजना बन रही हो तो मैं इतना तो पूछ ही सकता हूं कि हमें शिक्षा, पर्यावरण और सुरक्षा चाहिए या कथित पर्यटन?

आपका ही हिमाचल प्रदेश।

मध्य प्रदेश डायरी

नई कृषि क्रांति की जगी उम्मीद

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख,
मध्य प्रदेश

शिवराज सिंह चौहान सत्रह वर्ष मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद देश के कृषि मंत्री बने हैं। वह न केवल खुद अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती करते हैं, बल्कि दो दशक से प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों के बीच सक्रिय भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दो कार्यकाल में किसान आंदोलन बेहद बड़ी समस्या बने थे। हालांकि तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को चतुराई से सुलझा लिया था। अब संभावना बढ़ गई है कि किसान शिवराज की नई कृषि नीति से खुशहाली की ओर बढ़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान उस धारणा को तोड़ना चाहते हैं, जिसमें किसानों के बीच यह बात बैठ गई है कि बिना रासायनिक खाद के अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को प्रोत्साहित करते हुए मुहिम आरंभ की है कि किसान इस दिशा में आगे बढ़ें। सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। उन्हें तीन अगले वर्ष तक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

शिवराज कहते हैं कि प्राकृतिक खेती के लाभ अनेक हैं। इसमें पानी कम लगता है, खाद का खर्च भी कम लगता है और लागत कम आती है। मूल्य भी अधिक मिलता है। प्राकृतिक खेती में पहले एवं दूसरे वर्ष उत्पादन कुछ कम होता है, लेकिन तीसरे वर्ष से उत्पादन बढ़ जाता है। शिवराज की यह नीति काफी हद तक देशहित में भी है। इन दिनों भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना कर रही है। फर्टिलाइजर के अधिकाधिक उपयोग से कृषि उत्पादन तो खूब बढ़ रहा है, लेकिन उसके दुष्परिणाम स्वरूप कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी देश में बढ़ रही हैं। भूमि की उर्वरता कमजोर पड़ रही है। उसका प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो गया है। अब आपको वर्षाकाल में भी खेत में केंचुआ दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौतियां हैं।

ऐसा नहीं कि शिवराज ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का अभियान कृषि मंत्री बनने के बाद ही आरंभ किया हो। वह तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी जैविक खेती का प्रदेश में रिकार्ड बनवा चुके हैं। देश के कुल जैविक उत्पाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा सर्वाधिक 40 प्रतिशत है। लगभग 17 लाख हेक्टेयर में एक लाख से अधिक किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, तुअर, उड़द, बाजरा, रामतिल, मूंग, कपास, कोदो-कुटकी आदि फसल उपज शामिल हैं। अब तो मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे निकल चुका है। खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब प्रदेश में समूह बनाकर प्राकृतिक यानी जैविक खेती करवाई जाएगी। पांच-पांच सौ किसानों के समूह बनाए जाएंगे। इन्हें खेती करने के तौर-तरीके सिखाने के साथ उपज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर रही है। इसका जिम्मा किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ उपज की ब्रिकी का प्रबंध करना होगा। इस खेती का लाभ किसानों को समझाने के साथ उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर पांच-पांच हजार रुपये तीन वर्ष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तीन वर्ष तक किसान द्वारा की जाने वाली खेती का पूरा रिकार्ड रखा जाएगा। जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण भी करवाया जाएगा, ताकि उपज का अच्छा मूल्य मिले। जैविक खेती के लिए चयनित इन किसानों पर लगातार नजर रखी जाएगी। आंतरिक निरीक्षण होगा और उपज का मूल्यांकन होगा। साथ ही जैविक उत्पादों के ब्रांड निर्माण के लिए व्यापक विपणन कार्ययोजना तैयार की जाएगी। विशिष्ट बाजारों में स्टाल लगाने और खुदरा व्यापारी के साथ सीधे बाजार जुड़ाव की सुविधा के लिए आयोजन किए जाएंगे।

किसानों की समस्या दूर करने में शिवराज सिंह चौहान के अनुभवों का मिलेगा लाभ। फाइल

कृषि मंत्रालय में अब एक नवाचार भी शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य के कृषि मंत्री और उनके अधिकारियों के साथ शिवराज बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में केंद्र सरकार के भी कृषि विभाग के सारे अधिकारी शामिल होते हैं। राज्य के मंत्री अपनी समस्याएं बताते हैं और वहीं उनका समाधान किया जाता है। शिवराज द्वारा आरंभ संवाद से समाधान का यह प्रयास भी बेहतर परिणाम ला रहा है। वह स्वयं भी सभी राज्यों में जाकर संवाद कर रहे हैं। इन प्रयासों का स्पष्ट आशय है कि शिवराज देश के किसानों के चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं। वही हैं जो इन दिनों संसद के दोनों सदनों में किसानों के मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों पर भारी पड़ रहे हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर संसद में अप्रमाणित बात बोली तो शिवराज ने तर्कों और तथ्यों से उनकी बोलती बंद कर दी। शिवराज सिंह चौहान जुनूनी व्यक्ति हैं, जो ठान लेते हैं, वह करते हैं। मध्य प्रदेश की सफलता के बाद अब उन्होंने देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अभियान चलाया है। उम्मीद है इसमें भी वह सफल रहेंगे।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बिजनेस
गुरुवार 8 अगस्त, 2024
www.jagran.com

चीन का जुलाई में निर्यात सात प्रतिशत बढ़ा

बैंकाक: चीन का निर्यात जुलाई माह में सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, यह अर्थशास्त्रियों के करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि के पूर्वानुमान से कम है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात 7.2 प्रतिशत बढ़कर 215.9 अरब डालर हो गया, जो अन्य एशियाई देशों के साथ मजबूत व्यापार के दम पर गति पकड़ रहा है। अमेरिका को निर्यात में सालाना आधार पर 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को निर्यात में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (एपी)

मैं फिनटेक से आग्रह करूंगा कि वे स्वयं समाधान बनाने और फिर बैंकों से संपर्क करने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि बैंकों का दायरा बड़ा है और वे बड़े मुद्दों को देखते हैं।
— विवेक जोशी, वित्तीय सेवा सचिव

सेंसेक्स	79,468.01	▲ 874.94
निफ्टी	24,297.50	▲ 304.95
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 71,350	▼ ₹350
चांदी प्रति किलोग्राम	₹82,200	▲ ₹200
डालर	₹83.95	▲ ₹0.03
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 77.34	

एक नजर में

टाटा मोटर्स ने पेश की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व

नई दिल्ली: टाटा मोटर्स ने बुधवार को मझोले आकार की अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व.ईवी को पेश किया। इस नई एसयूवी की कीमत 17.49 लाख रुपये से शुरू होती है। महज 8.6 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की टाप स्पीड के साथ ही 500 लीटर का बूट स्पेस और 35 लीटर के फ्रंट स्टोरेज स्पेस वाली इस कार की सिंगल चार्ज रेंज 585 किमी तक है। (प्रेट्र)

छुट्टा नहीं होने पर जोमैटो खाते में जुड़ जाएंगे रुपये

नई दिल्ली: जोमैटो के ग्राहक अब नकद भुगतान के दौरान अगर कोई शेष राशि रहती है तो ग्राहक 'डिलिवरी पर्सन' को उसे अपने 'जोमैटो मनी' खाते में जोड़ने के लिए कह सकते हैं। वे इसका उपयोग भविष्य के आर्डर देने या बाहर खाने के लिए कर सकते हैं। कंपनी को इस विचार की प्रेरणा बिगबास्केट से मिली है। (प्रेट्र)

सकारात्मक गति से जुलाई में भर्ती गतिविधि 11% बढ़ी

मुंबई: जुलाई के महीने में भर्ती गतिविधियां सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ गईं। हालांकि जून की तुलना में भर्ती गतिविधियों में एक प्रतिशत की गिरावट आई है। रोजगार परिदृश्य पर नजर रखने वाले 'फाउंडइट इनसाइट्स ट्रैकर' के मुताबिक, दूसरी श्रेणी के शहरों में भर्ती गतिविधियों में वृद्धि के मामले में कोयंबटूर 24% वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा है। इसके बाद 23% वृद्धि के साथ जयपुर रहा। (प्रेट्र)

एनएसई का मुनाफा 39% बढ़कर 2,567 करोड़ हुआ

नई दिल्ली: नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का जून, 2024 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2,567 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन आय 51 प्रतिशत बढ़कर 4,510 करोड़ रुपये हो गई। एक्सचेंज ने कहा कि उसने इस दौरान सरकारी खजाने में 14,003 करोड़ का योगदान दिया है। (प्रेट्र)

बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 875 अंक चढ़ा

धातु और ऊर्जा शेयरों में जमकर हुई खरीदारी से एनएसई का निफ्टी एक बार फिर 24,000 अंक के पार

मुंबई, प्रेट्र: स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को पिछले तीन दिन से जारी गिरावट पर विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 875 अंक चढ़ गया। वहीं एनएसई निफ्टी फिर से 24,000 के स्तर को पार कर गया। दुनिया के अन्य प्रमुख बाजारों में तेजी तथा निचले स्तर पर शेयरों की लिवाली से बाजार में मजबूती आई।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 874.94 अंक यानी 1.11 प्रतिशत उछलकर 79,468.01 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,046.13 अंक चढ़कर 79,639.20 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 304.95 अंक यानी 1.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,297.50 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 345.15 अंक उछलकर 24,337.70 अंक पर पहुंचा था। इस तेजी में ज्यादातर क्षेत्रों का योगदान रहा। हालांकि धातु, ऊर्जा और औषधि क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेगमेंट रहे।

- यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी रही तेजी, मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार
- इंडेक्सेशन का लाभ फिर से लागू किए जाने से रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में रही तेजी

"बैंक आफ जापान के डिप्टी गवर्नर के वित्तीय अस्थिरता के दौरान ब्याज दर नहीं बढ़ाने के फिर से आश्वासन के बाद वैश्विक बाजारों में उल्लेखनीय तेजी आई। घरेलू बाजार में चौतरफा लिवाली हुई। रियल्टी क्षेत्र में इंडेक्सेशन लाभ फिर से लागू किए जाने से जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी रही।" -**विनोद नायर**, रिसर्च हेड, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज

"हाल की गिरावट के बाद बाजार में बुधवार को तेजी लौटी। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख से बाजार को समर्थन मिला।" -**अजित मिश्रा**, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च), रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड

अदाणी पोर्ट्स के शेयर में 3.42 प्रतिशत की तेजी

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से अदाणी पोर्ट्स एंड सेज 3.42 प्रतिशत और पावरग्रिड 3.39 प्रतिशत मजबूत हुए। इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से लाभ में रहे। इसके उलट नुकसान में रहने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा और टाइटन शामिल हैं।

सोना 350 रुपये टूटा, चांदी 200 रुपये मजबूत हुई

बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 350 रुपये गिरकर 71,350 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। हालांकि, लगातार चार दिनों की भारी गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में उछाल आया। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, चांदी 200 रुपये बढ़कर 82,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 82,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

रुपया तीन पैसे की गिरावट के साथ 83.95 प्रति डालर पर बंद

रुपया बुधवार को सीमित दायरे में मजबूत होने के बाद डालर के मुकाबले तीन पैसे की गिरावट के साथ 83.95 पर बंद हुआ। डालर में सुधार और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव का दबाव भारतीय मुद्रा पर पड़ा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि मजबूत डालर और कच्चे तेल की उच्ची कीमतों के कारण बुधवार को रुपये में गिरावट आई। हालांकि, घरेलू बाजारों में मजबूती ने गिरावट को सीमित रखा।

2.63 प्रतिशत उछला बीएसई मिडकैप | **2.39** प्रतिशत लाभ में रहा बीएसई स्मालकैप | **8.97** लाख करोड़ रुपये बढ़ी निवेशकों की संपत्ति | **5.43** ट्रिलियन डालर हो गया कंपनियों का मार्केट कैप

मशीन पंजीकृत नहीं कराने पर पान मसाला निर्माताओं पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र: पान मसाला और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के मैन्यूफैक्चरर्स पर अपनी मशीन का पंजीकरण नहीं कराने पर एक अक्टूबर से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जीएसटी नेटवर्क ने इससे पहले मई तथा जून में ऐसे विनिर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीन को पंजीकृत करने तथा खरीदे गए कच्चे माल और संबंधित उत्पादन की रिपोर्ट कर प्राधिकारियों के पास भेजने के लिए दो फार्म जीएसटी एसआरएम-1 और 2 अधिसूचित किए थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने जनवरी में पान मसाला तथा तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के वास्ते एक अप्रैल से एक नए पंजीकरण तथा मासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। बाद में तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी थी।

कई राज्यों में काम करने वाली कंपनियों को आइएसडी में खुद को कराना होगा पंजीकृत

कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाली तथा शाखा कार्यालयों के साथ 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' बांटने वाली कंपनियों को एक अप्रैल 2025 तक जीएसटी प्राधिकरणों के समक्ष 'इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर' (आइएसडी) के रूप में पंजीकरण कराना होगा। फरवरी में पेश किए वित्त विधेयक, 2024 के जरिये सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन करते हुए कहा था कि बहु-राज्य जीएसटी पंजीकरण वाले व्यवसायों को सेवाओं के लिए किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) को अपनी शाखाओं के बीच वितरित करने के लिए खुद को अनिवार्य रूप से आईएसडी के रूप में पंजीकृत कराना होगा। आइटीसी को साझा करने की व्यवस्था जीएसटी नियमों में निर्धारित है और मोटे तौर पर समान आईटीसी को एक ही पैन वाली विभिन्न शाखाओं के टर्नओवर के अनुपात में विभाजित किया जाता है।

चीन के विशेषज्ञों के लिए वीजा को सुगम बनाने का पोर्टल शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र: चीन के तकनीकी विशेषज्ञों के लिए कारोबारी वीजा को सुगम बनाने से जुड़े पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। इन विशेषज्ञों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) से जुड़े क्षेत्रों में जरूरत है। मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों ने चीनी विशेषज्ञों के लिए वीजा प्राप्त करने में देरी का मामला उठाया था।

इन विशेषज्ञों की श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के अलावा कुछ मशीनों को लगाने या मरम्मत जैसे कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। इस लिहाज से यह कदम महत्वपूर्ण है। एक अधिकारी ने कहा, 'पोर्टल पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ है। यह उस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए है जहां पीएलआइ क्षेत्र में चीनी विशेषज्ञों को कारोबारी वीजा दिया जाएगा।' गृह मंत्रालय ने विभिन्न विभागों के साथ बातचीत की है ताकि उन्हें इस बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।

गलत रिटर्न भरा है तो उसे निरस्त कर फिर से कर सकते हैं दाखिल

- 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने वालों को विभाग ने दी सहूलियत
- आयकर रिटर्न खारिज करने के बाद उसे फिर फाइल करना होगा

जागरण संवाददाता, कानपुर: आपने जो रिटर्न फाइल किया है यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसे निरस्त कर नया रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर चुके करदाताओं को यह सुविधा दी है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने वाले भी विलंब शुल्क के साथ यह सुविधा ले सकते हैं। रिटर्न फाइल करते समय कई बार कुछ खर्च या प्राप्तियों के आंकड़े छूट जाते हैं। कई बार आंकड़े गलत अपलोड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में करदाता के लिए अपने रिटर्न में संशोधन कराना मुश्किल होता था। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को आइटीआर-यू का अवसर दिया था, लेकिन उसे उन्हीं स्थिति में ठीक किया जा सकता है, जब कोई नई आय दिखानी हो। इसके जरिये न तो टैक्स को कम कर सकते हैं, न रिफंड को बढ़ाने के लिए इसे फाइल किया जा सकता है। इसे देखते हुए विभाग ने यह मौका दिया है कि करदाता पूरा रिटर्न खारिज कर दे। जिन लोगों ने रिटर्न खारिज करने के बाद उसे 31 जुलाई से पहले ही दोबारा फाइल कर दिया, उन्हें विलंब शुल्क नहीं देना पड़ा, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सके और अब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें विलंब शुल्क देना होगा।

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन दीप कुमार मिश्रा के मुताबिक इसमें एक शर्त यह भी है कि अगर आयकर रिटर्न ई-वेरीफिकेशन से सत्यापित हो चुका है, तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

माइक्रोसाफ्ट, टीसीएस, अमेजन इंडिया सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड

नई दिल्ली, प्रेट्र: माइक्रोसाफ्ट भारत का सबसे 'आकर्षक नियोक्ता ब्रांड' बनकर उभरा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और अमेजन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। रैंडस्टैड एंप्लायर ब्रांड रिसर्च (आरईबीआर)-2024 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माइक्रोसाफ्ट ने वित्तीय स्वास्थ्य, अच्छी प्रतिष्ठा और करियर में प्रगति के अवसरों पर बहुत ऊंचा स्कोर हासिल किया है। चौथे स्थान पर टाटा पावर और इसके बाद क्रमशः टाटा मोटर्स, सैमसंग इंडिया, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मर्सिडीज-बेंज हैं। रैंडस्टैड इंडिया के एमडी विश्वनाथ पीएस ने कहा कि अधिकांश कार्यबल को अपने नियोक्ताओं से महंगाई को देखते हुए अतिरिक्त लाभ मिला है। प्रतिभाएं अपने काम में कृत्रिम मेधा (एआइ) का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हैं।

रिलायंस ने दिया 1.86 लाख करोड़ का टैक्स

मुंबई, एएनआइ: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विभिन्न करों और शुल्क के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी खजाने में 1,86,440 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले नौ हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। 2024-25 के लिए सरकार के 48.21 लाख करोड़ रुपये के बजटीय व्यय लक्ष्य को अगर ध्यान में रखें तो कंपनी का योगदान इसके 3.86 प्रतिशत को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त है। यह सरकार के कृषि के लिए नियोजित व्यय से अधिक है, जिसका बजट 2024-25 के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये है। यह लगातार छठा साल है जब समूह का राष्ट्रीय खजाने में योगदान एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2024 तक पिछले सात वर्षों में इसका योगदान अब 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।

Reliance Industries Limited

2018 से 2024 तक यानी पिछले सात सालों में कंपनी का सरकारी खजाने में योगदान 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया

रिलायंस पहली भारतीय सूचीबद्ध कंपनी है, जिसने बाजार मूल्यांकन में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। रिलायंस समेकित राजस्व में 10,00,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी है। वर्ष 2023-24 में उसका शुद्ध लाभ 79,020 करोड़ रुपये के रिकार्ड उच्च स्तर पर रहा। वर्ष 2023-24 के लिए आरआइएल का निर्यात 2,99,832 करोड़ रुपये था। रिलायंस ने वित्त वर्ष 2024 में आरएंडडी पर 3,643 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कंपनी ने सामाजिक जिम्मेदारी के मद में कुल 1,592 करोड़ रूपये खर्च किए।

गौतम अदाणी ने सेवानिवृत्ति की समयसीमा तय नहीं की

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सेवानिवृत्त होने और उसकी कमान अपने बेटों एवं भतीजों को सौंपने को लेकर कोई समयसीमा तय नहीं की है। समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर बाजारों को इससे अवगत कराया है। कंपनी ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट में अदाणी को उत्तराधिकारियों और पारिवारिक ट्रस्ट में समान लाभकारी हितों को लेकर गलत ढंग से पेश किया गया है। 'ब्लूमबर्ग न्यूज' ने पांच अगस्त की रिपोर्ट में कहा था कि 62 वर्षीय अदाणी 70 वर्ष की आयु में पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में अदाणी के बेटों-करण (37) एवं जीत (26) के अलावा भतीजों प्रणव (45) एवं सागर (30) को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में बताया गया।

अंतरराष्ट्रीय

न्यूज गैलरी

लाओस में साइबर स्कैम सेंटर से 14 भारतीय युवा मुक्त कराए गए

वियनतियाने: लाओस में भारतीय दूतावास ने बुधवार को कहा, उसने दक्षिण पूर्व एशियाई देश के बोकेओ प्रांत में गोल्डन ट्राएंगल स्पेशल इकोनामिक जोन (एसईजेड) में चल रहे साइबर-घोटाला केंद्रों से 14 भारतीय युवाओं को मुक्त कराया है। उनकी सुरक्षित घर वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 548 युवाओं को मुक्त कराया जा चुका है। लाओस में जाब आफर को लेकर भारतीय नागरिकों के लिए एडवायजरी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी ऐसे लुभावने आफर में न फंसे, जो साइबर स्कैम को लेकर लालच दे रहा हो। भारत, दुबई, सिंगापुर और बैंकाक में बैठे एजेंट इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। (एएनआइ)

पाक के 12 अरब डालर कर्ज को बढ़ाने को चीन, सउदी, यूएई राजी

इस्लामाबाद: आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के 12 अरब डालर के कर्ज को एक साल बढ़ाने के लिए चीन, सउदी अरब व यूएई राजी हो गए हैं। यह फैसला इस बीच आया है, जब पाकिस्तान को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) इस माह के अंत में सात अरब डालर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे सकता है। इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि आइएमएफ ने कार्यकारी बोर्ड की बैठक से पहले तीन से पांच साल के रोलओवर की बात कही थी। हालांकि, सिर्फ एक वर्ष का रोलओवर काफी है। (प्रेट्र)

पेटा प्रदर्शनकारियों ने पोप के संबोधन को किया बाधित

वेटिकन सिटी: पशु अधिकार समूह पेटा के दो प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को पोप फ्रांसिस के संबोधन को बाधित कर दिया। उन्होंने बुलफाइटिंग के खिलाफ बैनर लहराया, जिसमें लिखा था, "बुलफाइटिंग पाप है। प्रदर्शनकारियों ने पोप से बुलफाइटिंग से कैथोलिक चर्च का नाता खत्म करने और इस खूनी खेल की निंदा करने का अनुरोध किया। पेटा के अनुसार, हर साल विश्व स्तर पर बुलफाइटिंग उत्सव में हजारों जानवर मारे जाते हैं। इनमें से कई कैथोलिक संतों को समर्पित होते हैं। (एपी)

इजरायल बोला, हमास के नए प्रमुख याह्या को जिंदा या मुर्दा पकड़ना लक्ष्य

तेल अवीव, एएनआइ: हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद याह्या सिनवार को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया है। हमास के सैन्य प्रमुख याह्या को राजनीतिक प्रमुख बनाए जाने से गाजा संगठन की शक्ति का केंद्र बन गया है। वहीं, इजरायली विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर आफ द डिजिटल डिप्लोमेसी ब्यूरो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि हमास की राजनीतिक व सैन्य शाखा में कोई अंतर नहीं है। हमारा अभियान याह्या के जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने तक जारी रहेगा। कतर की राजधानी दोहा में छिपे सिनवार को गत वर्ष सात अक्टूबर को इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। ईरान ने हानिया की हत्या का बदला लेने की इजरायल को धमकी दी है इससे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को ईरान व इजरायल दोनों से पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ाने को कहा है। साथ ही पेंटागन ने चेतावनी दी कि वह क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा, याह्या सिनवार की हमास के नए नेता के रूप में नियुक्ति से दुनिया में तेजी से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर, तुर्किये ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र अदालत में इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर नरसंहार मामले में शामिल होने का अनुरोध प्रस्तुत किया है।

हाउती विद्रोहियों के हमले को अमेरिका ने किया विफल: अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों के एक ड्रोन और दो पोतरोधी बैलेस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया है।

▸ अमेरिका ने कहा, पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ाएं इजरायल व ईरान

याह्या सिनवार का फाइल फोटो। एपी

इजरायली सेना का फलस्तीनियों से बेत हनौन को खाली करने का फरमान

ईरान के मैक्रों से कहा, आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी

दुबई, रायटर: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बुधवार को फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात की और कहा, "अगर अमेरिका व पश्चिमी देश वास्तव में क्षेत्र में युद्ध रोकना चाहते हैं, तो उन्हें इजरायल को गाजा में नरसंहार रोकने और युद्धविराम स्वीकार करने के लिए मजबूर करना होगा। ईरान आक्रामकता पर चुप नहीं रहेगा।

रूस की दक्षिण-पश्चिमी सीमा को भेदने की कोशिश में यूक्रेन : पुतिन

कीव, एपी: यूक्रेन ने बुधवार को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में ड्रोन व राकेट हमला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताते हुए कहा, यूक्रेनी बल रूस की दक्षिण-पश्चिमी सीमा भेदने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी अधिकारियों ने कहा, उन्होंने लगातार दूसरे दिन सीमा पार से छापे का सामना किया। वहीं, यूक्रेनी अधिकारी आपरेशन के दायरे के बारे में चुप रहे। वहीं, यूक्रेन के कीव क्षेत्र में रूसी हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस द्वारा लांच सभी 30 ड्रोन नष्ट कर दिए। पुतिन ने कैबिनेट अधिकारियों से कहा कि वह शीर्ष रक्षा और सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। यूक्रेनी हमले को उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ नागरिक इमारतों, घरों व एंबुलेंसों पर अंधाधुंध गोलाबारी कहा है। कुर्स्क क्षेत्र के प्रमुख ने भीषण लड़ाई के कारण निवासियों से रक्तदान करने का आग्रह किया है।

ब्रिटेन में इमिग्रेशन ला फर्म और सलाह एजेंसियां दंगाइयों के निशाने पर

लंदन, प्रेट्र: ब्रिटेन में दक्षिणपंथी समूहों ने देश भर में असाइलम सेंटरों और इमिग्रेशन ला फर्म और उनके वकीलों को निशाना बनाने की साजिश रची है। इमिग्रेशन फर्मों और सलाह एजेंसियों की एक सूची आनलाइन प्रसारित की जा रही है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को हमले के लिए उकसाया जा रहा है। इसबीच इमिग्रेशन ला फर्म और प्रवासी सहायता केंद्र बुधवार को बंद रहे। शरण चाहने वालों की मदद करने वाली असाइलम लिंक मर्सीसाइड का लिवरपूल कार्यालय भी बंद रहा। ब्रिटेन एक हफ्ते से अधिक समय से हिंसा झेल रहा है। 29 जुलाई को डांस क्लास में तीन बच्चियों की चाकू मारकर हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी थी। सार्वजनिक अभियोजन निदेशक स्टीफन पार्किंसन ने दंगाइयों को चेतावनी दी है कि उन्हें आतंकवाद के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्हें अपने कार्यों के लिए ता उम्र नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

▸ फर्म और सलाह एजेंसियों की सूची आनलाइन प्रसारित कर हमले को उकसाया जा रहा

पीएम किएर स्टार्मर ने मंत्रियों, पुलिस प्रमुखों व सुरक्षा विशेषज्ञों संग मंगलवार शाम आपातकालीन बैठक की। सरकार ने हिंसा से निपटने के लिए 6,000 विशेषज्ञ पुलिस अफसरों की टीमें बनाई है, जो बाडी कैम फुटेज व फेस रिकगनिशन का प्रयोग कर रही हैं। हिंसा में अब तक 400 से अधिक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 18 वर्षीय युवक जेम्स नेल्सन को पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त करने के मामले में दो माह की सजा सुनाई गई है। हिंसा मामले में सजा पाने वाला वह पहला शख्स है।

मस्क के गृहयुद्ध की कगार वाले पोस्ट पर ब्रिटेन की सख्त प्रतिक्रिया: एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा है कि ब्रिटेन गृहयुद्ध की कगार पर है। ब्रिटिश न्याय प्रणाली मुस्लिमों संग अधिक उदारतापूर्ण व्यवहार करती है। वहीं, ब्रिटिश न्याय मंत्री ने कहा कि मस्क जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें।

महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे

राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हाथ उठाकर अभिवादन करते नमल राजपक्षे। प्रेट्र

कोलंबो, प्रेट्र: राजपक्षे परिवार ने रानिल विक्रमसिंघे से दूरी बना ली है। उन्होंने श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट (एसएलपीपी) उम्मीदवार के रूप में महिंदा राजपक्षे के 38 वर्षीय बड़े बेटे नमल राजपक्षे को बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया। श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट ने बुधवार सुबह पार्टी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान इस उम्मीदवारी की घोषणा की। नमल के अलावा राष्ट्रपति विक्रमसिंघे, मुख्य विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा व मार्क्सवादी जेवीपी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके पहले से मैदान में हैं।

नेपाल में हेलीकाप्टर हादसे में पांच लोगों की मौत

काठमांडू, प्रेट्र: नेपाल में बुधवार को हेलीकाप्टर दुर्घटना में पांच लोग मारे गए। मृतकों में चार चीनी पर्यटक और पायलट शामिल हैं। दुर्घटना दोपहर करीब दो बजे काठमांडू से 30 किमी उत्तर-पश्चिम में नुवाकोट जिले के शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में हुआ। पांचों शव बरामद कर लिए गए हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तीन मिनट बाद ही हेलीकाप्टर का संपर्क टूट गया था। निजी एयरलाइन एयर डायनेस्टी का हेलीकाप्टर 9एन-एजेडी काठमांडू से रासुवा जा रहा था। यह काठमांडू से दोपहर 1.54 बजे रवाना हुआ। सिविल एविएशन अथारिटी आफ नेपाल ने कहा, दुर्घटना की सूचना के बाद वहां अन्य हेलीकाप्टर भेजा गया। हेलिकाप्टर का संचालन कैप्टन अरुण मल्ला कर रहे थे। इसमें तीन पुरुष और एक महिला चीनी नागरिक सवार थे। गत माह महीने 24 जुलाई को भी एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी।

नेपाल में नुवाकोट जिले के शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में बुधवार को हेलीकाप्टर दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे राहत-बचाव कर्मी। एपी

कमला बोलीं, हम ट्रंप के विरुद्ध नहीं, अमेरिका के भविष्य के लिए लड़ रहे

वाशिंगटन, रायटर: कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन हासिल करने के बाद अपने रनिंग मेट टिम वाल्ज के साथ पहली बार फिलाडेल्फिया में चुनावी अभियान शुरू किया। कमला ने कहा, हमारी लड़ाई रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध नहीं है, हमारा अभियान अमेरिका के भविष्य के लिए है। उन्होंने वाल्ज और खुद को मध्यवर्गीय परिवार के रूप में पेश करते हुए कहा, हम किफायती आवास, चाइल्ड केयर व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं।

फिलाडेल्फिया स्थित टेंपल यूनिवर्सिटी में आयोजित रैली में कमला ने कहा, लोगों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए हमें साथी की तलाश थी, जो पूरी हो गई। उन्होंने उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी टिम वाल्ज का परिचय भी कराया।

उपराष्ट्रपति प्रत्याशी टिम वाल्ज के साथ हैरिस ने शुरू किया चुनावी अभियान

फिलाडेल्फिया में चुनावी रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस तथा उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी टिम वाल्ज। एपी

मोदी को वीजा न देने के समर्थक रहे वाल्ज का बाद में हुआ हृदय परिवर्तन: गुजरात के सीएम रहने के दौरान नरेन्द्र मोदी को जब 2013 में अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, उस समय अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में वाल्ज कांग्रेस के प्रस्ताव के सह प्रायोजक थे। वाल्ज ने ट्वीट कर कहा, मोदी के पीएम बनने पर 2016 में उनके अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र के संबोधन के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र साथ है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया- बिल्कुल रिप्रजेंटेटिव वाल्ज। भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों से पूरी दुनिया को लाभ होगा।

****

जमात-ए-इस्लामी की सरकार में संभावित हिस्सेदारी से भारत सतर्क

भारतीय नीति निर्धारकों को उम्मीद- बांग्लादेश में कोई भी सत्ता में आए भारत की अहमियत बनी रहेगी

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

नई दिल्ली : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में लोकतंत्र का दमन करने के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना के साथ ही भारत को भी जिम्मेदार ठहराया है। भारत इससे ज्यादा चिंतित नहीं है, बल्कि असली चिंता अंतरिम सरकार के दूसरे सदस्यों को लेकर है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी की तरफ से इसमें बड़ी हिस्सेदारी लेने की कोशिश हो रही है। अवामी लीग को इसमें प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना नहीं है। सनद रहे कि जमात-ए-इस्लामी का रवैया हमेशा भारत विरोधी रहा है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जिस तरह से हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले हुए हैं, उसमें भी इसका हाथ है। ऐसे में भारत पूरे हालात पर सतर्क निगाह बनाए हुए है। दैनिक जागरण ने इस विषय पर नीति निर्धारकों से बात की। उनको भरोसा है कि सरकार किसी की बने, पर संबंध ठीक रखने की कोशिश जरूर होगी भले ही हसीना कार्यकाल जैसे मधुर संबंध न बनें। इसकी ठोस वजह हैं। आवश्यक वस्तुओं, बिजली, ईंधन आदि की जैसी आपूर्ति आज बांग्लादेश को भारत कर रहा है वैसा कोई देश नहीं कर सकता।

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है, 'अभी वहां हालात स्थिर नहीं है। भारत निश्चित तौर पर चाहता है कि वहां हिंसा खत्म हो, अल्पसंख्यकों व उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बंद हो। जब वहां सामान्य तौर पर सरकार काम करने लगेगी तभी कोई बातचीत होगी।' वैसे विदेश मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि बांग्लादेश के आम जनजीवन में जो स्थान भारत का है, उसकी भरपाई अन्य देश नहीं कर सकता। उदाहरण चीनी, चावल, गेहूं, आलू, प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से दिया जा सकता है। इनका बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। वर्ष 2022-23 में बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा 1.12 अरब डालर का चावल, 1.5 अरब डालर का गेहूं भारत से आयात किया था। दूसरा सबसे बड़ा आयात म्यांमार से था जोकि भारत के मुकाबले बहुत कम था। भारत ने पहले जब अंदरुनी वजहों से गेहूं और प्याज का निर्यात प्रतिबंधित किया था तब भी हसीना के अनुरोध पर बांग्लादेश को इन उत्पादों की आपूर्ति की थी। भारत की मदद से निर्मित मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति का प्रमुख जरिया है। यही नहीं, 2023 में 4.49 लाख बांग्लादेशियों ने भारत में इलाज करवाया, जो एक वर्ष पहले के मुकाबले 48% ज्यादा है।

कुछ अफसरों का कहना है कि यूनुस का अंतरिम सरकार का मुखिया बनना सकारात्मक कदम है। वजह- वह विकास कार्यों और धर्मनिरपेक्ष नीतियों का समर्थन करने वाले हैं। यह भारत-बांग्लादेश रिश्तों के लिए अच्छी खबर है।

भारत और बंग्लादेश का झंडा। फाइल

बांग्लादेश के लिए क्यों जरूरी है भारत

- चावल, गेहूं, चीनी, आलू व प्याज का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है भारत
- बांग्लादेश की कुल खपत की 15 प्रतिशत बिजली भारत आपूर्ति करता है
- 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति सिर्फ मैत्री पाइपलाइन परियोजना से
- बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत है इलाज के लिए पसंदीदा जगह

यूनुस का अमेरिकी कनेक्शन भी सकारात्मक पहलू

नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के अमेरिकी कनेक्शन को भी भारत सकारात्मक पहलू मान रहा है। यूनुस पर जब पूर्व हसीना सरकार की तरफ से कई तरह के मामले दर्ज किए जा रहे थे तब अमेरिका के सांसदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में यूनुस को अमेरिका के दो सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया था। भारत इस बात से फिलहाल संतोष कर सकता है कि अंतरिम सरकार की बागडोर पाक परस्त जमात के किसी नेता के हाथ में नहीं दी गई है।

बांग्लादेश में तैनात रहेंगे भारतीय राजनयिक, परिवारों की वापसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भारतीय उच्चायोग लगातार अपने देशवासियों के संपर्क में, टोल फ्री नंबर जारी किए
- जिन विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की संख्या ज्यादा, वहां भी संपर्क साधा जा रहा

बांग्लादेश के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। इसके बावजूद भारत ने राजधानी ढाका और दूसरे शहरों में स्थित अपने उच्चायोग के कार्यालयों में उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को तैनात रखने का फैसला किया है। हालांकि वहां कार्यरत गैर-आवश्यक व अराजनयिक पदों पर तैनात कर्मचारियों और राजनयिकों के परिवार के लोगों को स्वैच्छिक रूप से स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी गई है। ये लोग वाणिज्यिक फ्लाइटों से भारत लौट रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि वहां भारतीय उच्चायोग काम कर रहा है और उसे स्थानीय पुलिस से पूरी सुरक्षा दी गई है। भारत ने बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर अभी दो टूक फैसला नहीं लिया है। इनमें से अधिकांश छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं।

ज्ञात हो, एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी भी बांग्लादेश में 19 हजार भारतीय हैं जिनमें 9,000 छात्र हैं। यह स्थिति तब है जब गत एक माह में कई बार भारत सरकार ने बांग्लादेश को लेकर चेतावनी जारी की है। वर्ष 2022 में यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद बांग्लादेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ गई है। पहले काफी छात्र यूक्रेन जाते थे। भारतीय उच्चायोग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और भारतीयों से संपर्क करने को कहा गया है। जिन विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की संख्या ज्यादा है, वहां भी संपर्क साधा गया है।

बांग्लादेश से 800 भारतीय लौटे

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद नई दिल्ली व ढाका के बीच कुछ समय के लिए बाधित उड़ान सेवा अब शुरू हो चुकी है। एअर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी ढाका के लिए उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया है। मंगलवार मध्य रात्रि से बुधवार शाम तक चार फ्लाइटें ढाका से करीब 800 यात्रियों को लेकर नई दिल्ली पहुंचीं। वहां से आए यात्रियों ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। वहां भारतीयों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है।

तटरक्षक बल ने सुंदरवन क्षेत्र में तैनात किया होवरक्राफ्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। भूमि के साथ-साथ जल सीमा क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बंगाल के दुर्गम सुंदरवन जल सीमा क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक बल ने भी निगरानी बढ़ाने के लिए होवरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। होवरक्राफ्ट दक्षिण 24 परगना जिले में सुंदरवन के नदी व समुद्री जल सीमा क्षेत्र में 24 घंटे गश्त करेगा। होवरक्राफ्ट तटरक्षक बल का विशेष जहाज है, जो जमीन, कीचड़ व पानी में भी चलने में सक्षम है। बीएसएफ ने उत्तर बंगाल से गुवाहाटी फ्रंटियर तक कड़ी सुरक्षा की है। काफी संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं।

ओडिशा तट सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल (आइसीजी) ने ओडिशा तट सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। एहतियात के तौर पर आइसीजी के जहाज को बंगाल के हल्दिया और ओडिशा के पारादीप में तैनात रखा गया है। आइसीजी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अनधिकृत लोगों द्वारा भारतीय जलक्षेत्र में घुसने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तटरक्षक बल को चौकन्ना रहने को कहा गया है। कुछ दिन पहले तक आइसीजी और बांग्लादेश तटरक्षक बल के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल था।

भाजपा ने अपने नेताओं से कहा- बांग्लादेश मुद्दे पर न करें टिप्पणी

बीएल संतोष। फाइल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के बाद अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी अपने प्रदेश के नेताओं को बांग्लादेश मुद्दे पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने बंगाल नेतृत्व को इस बाबत सतर्क करते हुए बांग्लादेश के हालात पर खुलकर बोलने या कोई भी विवादित टिप्पणी से बचने को कहा है। पार्टी चाहती है कि इस स्थिति में दोनों देशों के रिश्ते खराब न हों।

खालिदा के समर्थकों की भीड़

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और जमात-ए-इस्लामी की नेता खालिदा जिया की रिहाई के बाद बुधवार को ढाका में उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली में उमड़े समर्थक। एएफपी

जान बचाने को बांग्लादेश में होटल की चौथी मंजिल से कूदे दो भारतीय युवक

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों को एंबुलेंस से सीमा पार करके लाया गया बंगाल
- होटल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के एक वरिष्ठ नेता का बताया जा रहा है

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच वहां के जसोर इलाके में स्थित एक होटल में आग लगा दी गई। वहां ठहरे दो भारतीय युवक जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कूद गए। बुरी तरह घायल हालत में उन्हें इलाज के लिए एंबुलेंस से पेट्रापोल सीमा पार करके बंगाल लाया गया है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। घायलों के नाम रबिउल इस्लाम व शहीद अली हैं। दोनों भाई हैं और असम के रहने वाले हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रबिउल का व्यवसाय के सिलसिले में नियमित रूप से बांग्लादेश आना-जाना लगा रहता है। वह अपने भाई शहीद अली के साथ जसोर इलाके के एक होटल के 12वीं मंजिल पर ठहरे थे। गत सोमवार को होटल में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। दोनों भाई सीढ़ियों से जितना हो सके, नीचे उतरे। चूंकि, आग तीसरी मंजिल तक फैल चुकी थी, ऐसे में बचने के लिए उन्होंने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। इसमें शहीद अली के दोनों पैर की हड्डियां टूट गईं और रबिउल की पीठ में गंभीर चोट लगी है। होटल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के एक वरिष्ठ नेता का बताया जा रहा है।

बांग्लादेश के जासोर में एक होटल में आग लगाए जाने के बाद जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कूदने पर घायल हुए भारतीय युवक शहीद अली को एंबुलेंस से बंगाल लाया गया। सौ. इंटरनेट मीडिया

यूनुस को दी गई छह माह की कैद की सजा रद

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस बीच बांग्लादेश के न्यायालय ने मुहम्मद यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए दी गई छह महीने के कारावास की सजा रद कर दी है। हसीना सरकार के कार्यकाल में दर्ज मामले में यह सजा दी गई थी। यह जानकारी समाचार एजेंसी रायटर ने दी है। कई मामलों में सजा पाकर 2018 से घर में कैद देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मंगलवार को रिहाई हुई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा ने कहा है कि लोगों ने अपने संघर्ष से असंभव को संभव करके दिखा दिया है। अब गुस्से और बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी बल्कि प्रेम और शांति से देश का पुनर्निर्माण किया जाएगा। खालिदा की पार्टी भी अंतरिम सरकार का हिस्सा होगी।

बेटे ने कहा, हसीना कुछ दिन भारत में रहेंगी

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगी।

यह बात उनके बेटे सजीब वाजेद जाय ने कही है। सोमवार को ढाका में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ वायुसेना के मालवाही विमान से दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरबेस पहुंची थीं। भारत सरकार ने वहां उन्हें सेफ हाउस रखा है। एक जर्मन अखबार से साक्षात्कार में सजीब ने बताया कि उनकी मां हसीना को कहां रहना है यह उन्होंने अभी तक निश्चित नहीं किया है लेकिन अभी वह भारत में हैं।

चुनाव हारने के बाद देश को अराजकता में धकेलना चाहती है कांग्रेस : अनुराग

- सलमान खुर्शीद ने कहा-बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह भारत में भी हो सकता है
- भाजपा का पलटवार, देश को पीछे धकेलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में विपक्षी दलों के नेता सरकार के विरोध में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश की घटना को जायज ठहराने लग गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने जहां कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह भारत में भी हो सकता है, वहीं शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि बांग्लादेश का संदेश यह है कि लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इस पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि लगातार तीन लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस देश को अराजकता में धकेलना चाहती है।

एक पुस्तक विमोचन समारोह में खुर्शीद ने कहा कि यद्यपि सतह पर सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह भारत में भी हो सकता है। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की इस तरह की ''बेतुकी टिप्पणियां'' पार्टी की मानसिकता को दर्शाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को पीछे धकेलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसे आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है।

अनुराग ठाकुर। फाइल

जनता की अदालत ने बांग्लादेश में फैसला सुना दिया : उद्धव

शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना को हटाने से दुनिया भर में यह संदेश गया है कि जनता सर्वोच्च है और सत्ता में बैठे लोगों को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ने कहा कि बांग्लादेश में जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बांग्लादेश में अत्याचार का शिकार हुए हिंदुओं को बचाने की चुनौती दी।

वाट्सएप पर लिखा-'बांग्लादेश हो गया, अब भारत का नंबर'

जागरण संवाददाता, बरेली

- बरेली में अवैध लैब संचालक ने किया माहौल बिगाड़ने का प्रयास, आरोपित पर प्राथमिकी

बांग्लादेश में तख्तापलट का संदर्भ देकर बरेली में अवैध केयर पैथालाजी लैब संचालक अफसार अहमद ने खुराफात की। बुधवार को उसने अपने वाट्सएप स्टेटस पर लिखा-' श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब भारत का नंबर है। आठ हजार करोड़ का हवाई जहाज वैसे तैयार है। झोला भी तैयार है। अंधभक्तों डरा नहीं रहा हूं। आगाह कर रहा हूं। बांग्लादेश में तो छात्र परेशान थे...।' उसके विरुद्ध सांप्रदायिक माहौल एवं सद्भाव बिगाड़ने, आइटी एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी लिखी गई है।

अफसार के वाट्सएप स्टेटस का स्क्रीन शाट बुधवार दोपहर को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसे एक्स अकाउंट यूजर हिमांशु पटेल ने मुख्यमंत्री कार्यालय, डीजीपी कार्यालय, उप्र पुलिस और बरेली आइजी को टैग किया। उन्होंने लिखा कि आपत्तिजनक शब्द लिखकर माहौल खराब किया जा रहा है। इसके बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस के अनुसार, रामपुर निवासी अफसार सिरौली में प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के सामने केयर पैथालाजी लैब चलाता है। प्राथमिकी की भनक लगते ही वह लैब बंदकर फरार हो गया। इसकी जानकारी सीएमओ डा. विश्राम सिंह को दी गई। एसीएमओ एवं निजी अस्पताल-लैब संचालन के नोडल अधिकारी लईम अहमद ने कहा कि गुरुवार को लैब सील करेंगे। साथ ही संचालक को नोटिस दिया जाएगा, उसका जवाब आने के बाद प्राथमिकी या अन्य कार्रवाई की जाएगी। एसपी दक्षिणी मानुष पारीक का कहना है कि अफसार के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर उसकी तलाश की जा रही है।

एससीबीए ने पूछा, क्या शेख हसीना ने किए हैं प्रत्यर्पण योग्य अपराध

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अदिश सी. अग्रवाल ने बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि क्या उनके देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रत्यर्पण करने योग्य अपराध किया था।

बांग्लादेश एससीबीए के अध्यक्ष एएम महबूब खान खोकोन को लिखे पत्र में अग्रवाल ने उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है कि वहां उथल-पुथल के दौरान हिंदुओं को जानबूझकर निशाना न बनाया जाए। अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने खबरों में पढ़ा है कि आपने भारत से अनुरोध किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एवं उनकी बहन शेख रेहाना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंप दिया जाना चाहिए। 2013 की प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक यह जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति ने प्रत्यर्पण योग्य अपराध किया हो। ऐसी कोई खबर नहीं है कि शेख हसीना या उनकी बहन पर किसी आपराधिक मामले में आरोप लगाया गया है। अगर आपका दावा है तो इस संबंध में तत्काल जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि बार भारत सरकार पर इस सिलसिले में दबाव बना सके।

जान बचाने के लिए जल्दबाजी में भागीं हसीना और उनके सहयोगी

नई दिल्ली, एएनआइ : अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों को खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में भागना पड़ा। उनके साथ भारत पहुंचे अधिकांश लोगों को अपने साथ जरूरी सामान लेने का भी समय नहीं मिला। शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और अन्य सहयोगी सोमवार को ढाका से सी-130 जे परिवहन विमान से भारत पहुंचे।

सूत्रों ने बताया कि उनके दल में शामिल सभी सदस्य जल्दबाजी में भारत आए थे। उनमें से कई लोग अपने साथ कपड़े या कोई अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी नहीं ले सके थे। उनके भारत पहुंचने के बाद भारतीय प्रोटोकाल अधिकारियों ने हसीना की टीम के सदस्यों को कपड़े और अन्य सामान खरीदने में मदद की। सूत्रों ने बताया कि हसीना के सहयोगी पिछले कुछ दिनों में स्वदेश में मिले अनुभव और दृश्यों के कारण सदमे की स्थिति में थे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आने वाली शेख हसीना और उनकी बहन के सहयोगियों की संख्या दोहरे अंक में है। वे सभी उनके साथ ही भारत आए हैं।

राष्ट्रीय फलक

एनबीईएमएस ने नीट-पीजी प्रश्न लीक होने के दावों को किया खारिज

- कहा, नीट-पीजी के प्रश्न पत्र अब तक तैयार नहीं किए गए हैं
- इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने बुधवार को नीट-पीजी के छात्रों को दलालों से सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही टेलीग्राम मैसेंजर प्लेटफार्म पर किए जा रहे उन दावों को खारिज कर दिया है कि उनकी पहुंच नीट-पीजी 2024 परीक्षा के प्रश्नों तक है। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। एनबीईएमएस द्वारा कहा गया है कि नीट-पीजी के प्रश्न पत्र अब तक तैयार नहीं किए गए हैं। बोर्ड ने कहा कि झूठे दावे नीट-पीजी लीक्ड मेटेरियल नामक टेलीग्राम चैनल पर किए गए हैं।

बोर्ड ने कहा कि एनबीईएमएस के संज्ञान में आया है कि टेलीग्राम मैसेंजर प्लेटफार्म के माध्यम से झूठे और फर्जी दावे किए जा रहे हैं। वह अच्छी खासी रकम के बदले आगामी परीक्षा के लिए प्रश्न उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। पैसे के बदले प्रश्न उपलब्ध कराने के नाम पर नीट-पीजी उम्मीदवारों को बेवकूफ बनाने के प्रयास के लिए ऐसे धोखेबाजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ पहले ही पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बयान जारी कर इन दावों को फर्जी बताया है। साथ ही कहा है कि प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा करने वाले द्वारा उम्मीदवारों से संपर्क किया जाता है, तो वह इसकी सूचना बोर्ड के संचार वेब पोर्टल या पुलिस को दे सकते हैं।

****

घेरे में फंसे आतंकियों को मार गिराने में धुंध और वर्षा बनी चुनौती

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर

- ऊधमपुर के बसंतगढ़ के जंगल में सुरक्षा बलों का अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल आतंकियों पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए हैं। ऊधमपुर के बसंतगढ़ के जंगलों में फंसे आतंकियों को मार गिराने के लिए संयुक्त अभियान चलाकर घेरा कस दिया है, पर वर्षा, धुंध और घने जंगल के कारण इसमें अड़चन आ रही है। डीआइजी मोहम्मद रईस भट्ट भी बसंतगढ़ का दौरा कर अभियान का जायजा ले चुके हैं।

सुरक्षाबलों ने पिछले एक सप्ताह से बसंतगढ़ इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। मंगलवार को खनेड़ क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास जंगल में तीन से चार आतंकियों को घेर कर आपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई और आतंकी दो समूहों में बंट गए। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सेना और स्पेशल फोर्स ने पूरे खनेड़ इलाके को घेर रखा है। कठुआ जिले से लगती सीमा पर होने के कारण वहां भी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। सियोज की तरफ जाने के सभी मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। एक तरह से खनेड़ छावनी में तबदील हो चुका है और जंगल को खंगाला जा रहा है, पर वर्षा व धुंध बड़ी चुनौती है। मंगलवार को बसंतगढ़ के खनेड़ पहुंचे ऊधमपुर-रियासी रेंज के डीआइजी मोहम्मद रईस भट्ट ने कहा कि आतंकियों का दल सुरक्षा बलों के घेरे में फंसा हुआ है। घनी धुंध के बीच भी अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि आतंकियों को जल्द ही मार गिराया जाएगा।

विनेश के साथ क्या हुआ ऐसे समझें

विनेश ने पिछले कुछ सालों में 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। इस बार अंतिम पंघाल ने इस वर्ग में क्वालीफाई किया और विनेश को 50 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए वजन कम करना पड़ा।

ओलिंपिक, एशियाई खेल, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप के लिए किसी भी पहलवान को एक ग्राम की भी छूट नहीं मिलती है। रैंकिंग सीरीज और आमंत्रण स्पर्धाओं के लिए किसी को दो किलोग्राम की रियायत मिलती है, जिसका मतलब है कि इन स्पर्धाओं में कोई भी पहलवान 50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने पर भी मुकाबले के दिन 52 किलोग्राम का हो सकता है।

ओलिंपिक खेलों में कुश्ती प्रतियोगिता दो दिनों में आयोजित की जाती है और दोनों दिनों में प्रतिस्पर्धी पहलवानों को वजन जांच से गुजरना पड़ता है। प्रतियोगिता के पहले दिन पहलवान को अपना 'सिंगलेट' (कुश्ती परिधान) पहनना होता है और 30 मिनट की अवधि में कई बार अपना वजन मापना होता है।

स्वर्ण पदक, कांस्य पदक के प्लेआफ और रेपेचेज मुकाबलों के लिए क्वालीफाई करने वालों को दूसरे दिन फिर से वजन करने के लिए आना होता है। लेकिन दूसरे दिन प्रतियोगिता की सुबह वजन करने के लिए केवल 15 मिनट का समय होता है। यहीं पर विनेश का वजन 50.1 किलोग्राम पाया गया। 15 मिनट की अवधि समाप्त होने के बाद विनेश की पदक की उम्मीदें धराशायी हो गईं।

विनेश ने वजन घटाने को माना था चुनौती

कोटा प्राप्त करने के बाद विनेश ने कहा था, मैं ओलिंपिक तक सिर्फ वजन नियंत्रित करना चाहती हूं

नई दिल्ली, जेएनएन: 'मुझे अपने वजन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना होगा। मैंने इतने लंबे समय के बाद अपने वजन को कम कर 50 किलोग्राम तक किया है इसलिए मैं इसे जितना संभव हो उतना बनाए रखने की कोशिश करूंगी।' इस वर्ष अप्रैल में किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई विश्व चैंपियनशिप में जब विनेश फोगाट ने 50 किग्रा वर्ग के लिए ओलिंपिक कोटा प्राप्त किया था, तब यब बात खुद उन्होंने स्वीकार की थी।

हरियाणा की 29 वर्षीय पहलवान ने कहा था कि मेरी मांसपेशियां मजबूत हैं, इससे मेरा वजन जल्दी बढ़ जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी फिट हूं, फिर भी मेरा वजन बढ़ता है। मैं सिर्फ अपना वजन नियंत्रित करना चाहती हूं। मेरे पास चार महीने बचे हैं और हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने वजन में बदलाव इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने 50 किग्रा वर्ग में अपने देश के लिए कोटा जीता। मुझे खुशी है कि मैं ओलिंपिक में जा सकती हूं। दरअसल, विनेश हमेशा ही 53 किलो भार वर्ग में खेलती थीं, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध आंदोलन करने की वजह से विनेश की जगह इस वर्ग में अंतिम पंघाल ने ओलिंपिक कोटा प्राप्त किया था। आंदोलन कर रहे पहलवानों के कहने पर बनाई गई समिति ने विनेश को 50 किलोग्राम भर वर्ग के लिए क्वालीफाई करने का मौका दिया। उन्होंने ये क्वालीफाई भी कर लिया, लेकिन अपने मूल भारवर्ग से कम में खेलने की वजह से उन्हें पहले को अपेक्षा ज्यादा वजन कम करना पड़ा जो एक चुनौती होता है। पहलवान जिस वजन वर्ग में खेलते हैं उसमें भी एक दिन पहले भी काफी वजन कम करते हैं। विनेश तो मूल वजन से कम में खेल रही थीं इसलिए उन्हें ज्यादा दिक्कत हुई। पेरिस में एक दिन में तीन बाउट लड़ने के बाद विनेश का वजन बढ़ा तो उनके कोच व सहयोगी स्टाफ इसे कम करने में जुट गए। सेमीफाइनल बाउट जीतने के तुरंत बाद वह खेल गांव में कोच के साथ रस्सी कूदती दिखीं थीं।

खेल गांव के पाली क्लीनिक में विनेश से मिलतीं आइओए अध्यक्ष पीटी ऊषा ● प्रेट्र

कोच से बोलीं विनेश, ये खेल का हिस्सा

पेरिस, प्रेट्र : महिलाओं के राष्ट्रीय कोच वीरेंद्र दहिया और मंजीत रानी ने इस पहलवान से मुलाकात की। दहिया ने बताया, इस खबर से कुश्ती दल में हड़कंप मच गया। हमने विनेश से मुलाकात की और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसने हमसे कहा, 'यह खेल का हिस्सा है'।

रातभर वजन कम करने का प्रयास किया गया : डा. पारदीवाला

पेरिस, प्रेट्र: पेरिस ओलिंपिक में विनेश फोगाट को बढ़े वजन के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारतीय दल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. दिनशा पारदीवाला ने बताया कि मंगलवार को तीन बाउट लड़ने के बाद विनेश का वजन तेजी से बढ़ा, जिसके बाद मेडिकल टीम ने विनेश का वजन कम करने के लिए पूरा प्रयास किया है। वजन कम करने में खुराक, पानी व अन्य चीजों का ध्यान रखना पड़ा है। इसके अलावा एथलीट को पसीना भी निकालना होता है। पारदीवाला के अनुसार, विनेश के तीन बाउट थे, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कुछ मात्रा में पानी देना पड़ा। हालांकि देखने में आया कि, बाउट के बाद विनेश का वजन सामान्य से अधिक बढ़ रहा था। इसके लिए कोच ने विनेश पर सामान्य प्रक्रिया शुरू की, और उन्हें पूरा भरोसा था कि रात के बाद विनेश का वजन नियंत्रण में आ जाएगा। हमने विनेश का वजन कम करने के लिए सब उपाए किए। यहां तक कि विनेश के बाल भी काटे, उनके कपड़ों को भी छोटा किया गया। लेकिन इन सब प्रयासों के बाद बाद भी वजन कम नहीं हो पाया। फिलहाल विनेश को स्थानीय ओलिंपिक पालीक्लीनिक में तरल पदार्थ दिए जा रहे हैं। उनके सभी स्थिति सामान्य हैं। उन्होंने पीटी ऊषा से भी बात की है। वह शारीरिक तौर पर बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन तीसरे ओलिंपिक में भी पदक नहीं जीत पाने का मानसिक कष्ट है।

डाक्टर दिनशा पारदीवाला

डब्ल्यूएफआइ की मांग स्टाफ पर कार्रवाई हो

पेरिस: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के अध्यक्ष संजय सिंह ने बुधवार को विनेश के पेरिस ओलिंपिक से बाहर होने के बाद उनके साथ जुड़े सहयोगी स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि फाइनल से पहले वजन को दायरे में नहीं रखने की गलती स्वीकार्य नहीं है। यह विनेश की गलती नहीं है। वह शानदार प्रदर्शन कर रही थी। कोच, सहयोगी स्टाफ, फिजियो और पोषण विशेषज्ञों को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह कैसे हुआ और वह कैसे वजन सीमा से अधिक हो गया इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से सभी जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।'

विनेश ने छह अगस्त को क्या-क्या खाया?

नई दिल्ली, जेएनएन: पहली जीत के बाद सबसे पहले विनेश ने जूस पिया, जिससे उनका वजन 300 ग्राम तक बढ़ा। फिर बाउट से पहले दो लीटर तरल पदार्थ लिया जिससे वजन दो किलोग्राम बढ़ा। इसके बाद दिनभर शरीर में ऊर्जा के लिए हल्का-फुल्का खाना खाया जिससे 700 ग्राम वजन और बढ़ गया। दिन के आखिरी तक विनेश फोगाट का वजन 52.7 किलो था।

केवल 100 ग्राम नहीं घट पाना कोई संयोग नहीं

अभ्यास करने के बाद बैठीं विनेश फोगाट ● आइएएनएस

सुकांत सौरभ ● जागरण

नई दिल्ली : छह अगस्त को लगातार तीन मुकाबले जीतकर पदक पक्का कर इतिहास रचने वाली भारत की शेरनी विनेश फोगाट को शायद ही अंदाजा होगा कि अगली सुबह उनके लिए पहाड़ बनकर आएगी। छह अगस्त की सुबह अपने पहले मुकाबले से पूर्व 49.9 किग्रा वजन आने के बाद विश्व को अपने तीसरे ओलिंपिक अभियान में फुर्ती और अद्भुत रक्षात्मक शैली से चौंकाने वाली विनेश का अगली सुबह केवल 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित होना कोई संयोग नहीं है। टोक्यो ओलिंपिक के रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया के कोच रहे ललित कुमार ने विशेष बातचीत में पूरे घटनाक्रम को समझाया। बुधवार की सुबह विनेश में पानी की मात्रा अत्यधिक कम होने की वजह से वह 100 ग्राम वजन कम नहीं कर सकीं और परिणामस्वरूप अयोग्य घोषित हो गईं।

कोच ललित से यह पूछने पर कि क्या ऐसा पहलवानों के साथ पहले भी होता आया है, इस पर उन्होंने कहा, 'इससे पहले केवल 2016 में एक बार ओलिंपिक क्वालीफायर में विनेश को ही 48 किग्रा वर्ग में वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। ऐसा नहीं है कि विनेश ने पहले वजन कम नहीं किया है, पर बुधवार की परिस्थितियां थोड़ी अलग थीं।' ललित ने बताया, 'जब किसी पहलवान को एक दिन में तीन मुकाबले खेलने पड़े और वह भी विश्व की शीर्ष पहलवानों से तो बहुत थकान हो जाती है। मांसपेशियों को रिकवर होने के लिए समय देना होता है, परंतु विनेश की समस्या यह है कि उनका प्राकृतिक वजन 55-57 किग्रा है और सामान्यतः वह 53 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं। हालांकि, इस बार वह क्योंकि 50 किग्रा वर्ग में भाग ले रही थीं उन्हें प्रतिदिन वजन घटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रही ती। तीन मुकाबलों के कारण उन्हें अपनी डाइट भी थोड़ी अधिक लेनी पड़ी थी और मंगलवार देर रात उनका वजन 52.7 किग्रा हो गया था। लगातार तीन मुकाबलों से हुई थकान और इसके बाद लगातार रातभर मेहनत करने से विनेश में पानी की अधिक कमी हो गई।

वजन घटाने के लिए एथलीट करते हैं कई उपाय

नई दिल्ली, जेएनएन: एथलीट कई तरह से अपना वजन कम करते हैं। इसके लिए वे हैवी वर्कआउट करते हैं और इसके लिए खास तरह के कपड़े आते हैं, जिन्हें पहनकर वर्कआउट किया जाता है। इससे शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है और कुछ ही घंटों में वजन कम हो जाता है। एथलीट इस स्थिति में एक एफबीटी (फैमिली बेस्ड बिहेवियोरल ट्रीटमेंट) सूट पहनते हैं, जिससे शरीर में काफी गर्मी पैदा होती है और उससे पहनकर सोना बाथ लेते हैं। सोना बाथ से शरीर से काफी तेज पसीना निकलता है। ऐसा करने से शरीर से पानी की मात्रा कम होने लगती है। इस तरह बहुत वजन कम कर दिया जाता है। इसके अलावा भी पानी की मात्रा कम करने के उपाय होते हैं, जिससे शरीर से पानी निकाला जाता है और वजन कम हो जाता है।

विनेश से बात के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी : महावीर

सचिन गुप्ता ● जागरण

चरखी दादरी: विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण अयोग्य ठहराए जाने पर उनके ताऊ और द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट भी भावुक हो गए। पहलवान महावीर फोगाट ने बताया कि बुधवार सुबह उनके दामाद पहलवान बजरंग पूनिया व बेटी संगीता फोगाट ने उन्हें फोन पर वजन अधिक होने के कारण विनेश के अयोग्य होने की सूचना दी। पहलवान महावीर फोगाट ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की साजिश है, लेकिन विनेश से बात होने के बाद ही सब स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि देश को स्वर्ण की उम्मीद थी, लेकिन अब इस घटना से सदमा लगा है।

मेहनती, जिद्दी है विनेश: पहलवान महावीर फोगाट ने बताया कि विनेश का इरादा था कि वह 2024 में ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद और नहीं खेलेगी, लेकिन इस बार वह तकनीकी कारण से अयोग्य ठहरा दी गईं। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट काफी मेहनती और जिद्दी हैं। ऐसे में वे अब दोबारा से उसे 2028 में होने वाले ओलिंपिक के लिए तैयार करेंगे। उन्हें भरोसा है कि वर्ष 2028 में होने वाले ओलिंपिक में देश के लिए जरूर स्वर्ण पदक जीतेगी।

झोझू कलां स्थित अकादमी में बात करते पहलवान महावीर फोगाट ● जागरण

महिला पहलवानों के लिए भार वर्ग बदलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वजन घटाना इतना आसान नहीं होता। पिछले छह महीने से विनेश वजन घटा रही थीं। इसके लिए रोजाना कम डाइट ले रही थीं। - **बजरंग पूनिया**, ओलिंपियन पहलवान

जिंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष का नाम विनेश फोगाट है। बहन इस वक्त जो तकलीफ आप महसूस कर रही होंगी, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर सच्चे हिन्दुस्तानी की आज आंखें नम हैं।

-**गीता फोगाट**, विनेश की चचेरी बहन

वजन कम करतीं विनेश फोगाट ● आइएएनएस

विनेश आपके साहस और दृढ़ संकल्प ने पूरे देश को प्रेरित किया है। अयोग्यता के दुख के बावजूद, फाइनल तक की आपकी अविश्वसनीय यात्रा ने हमारी प्रशंसा अर्जित की है।

- **सचिन तेंदुलकर**, पूर्व क्रिकेटर

यह साजिश हो सकती है। 100 ग्राम, मतलब मजाक है क्या। हम खिलाड़ी एक रात में पांच से छह किलो वजन घटा सकते हैं। हमें पता होता है कि अपनी भूख और प्यास पर कैसे काबू रखना है।- **विजेंद्र सिंह**, ओलिंपिक पदक विजेता

मुझे उम्मीद है कि अधिकारी कड़ा विरोध जताएंगे क्योंकि यह शुरुआती दौर का मुकाबला नहीं था। हम पदक दौर की बात कर रहे हैं। आइओए और सरकार को इसका सख्त विरोध करना चाहिए।'

- **सुनील गावस्कर**, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

अपने कमरे से चलते समय विनेश ने वजन चेक किया था, यह पूरा 50 किलो था। 10 कदम चलते ही यह 100 ग्राम बढ़ गया। मशीन की जांच होनी चाहिए थी। इसमें साजिश की बू आ रही है। - **राजपाल राठी**, विनेश फोगाट के ससुर

हमें पूरा विश्वास है कि वह कुश्ती के मैदान में और मजबूत होकर वापसी करेंगी। विनेश आपने हमेशा ही देश को गौरवान्वित किया है। इस मामले में आइओए मजबूती से चुनौती देगा - **राहुल गांधी**, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

आज भाला फेंककर इतिहास रचने उतरेंगे नीरज चोपड़ा

पेरिस, प्रेट्र: नीरज चोपड़ा ने क्वालीफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंक कर अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ा संदेश दिया लेकिन मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को गुरुवार को भारतीय खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चोपड़ा ने टोक्यो ओलिंपिक की तरह यहां भी कुछ सेकेंड में फाइनल के लिए क्वालीफाई कर दिया था लेकिन इस बार पिछले ओलिंपिक की तुलना में चुनौती अधिक कड़ी है। भारत का यह 26 वर्षीय खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरह से समझता है क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले आठ वर्षों से चुनौती पेश कर रहे हैं। नीरज फाइनल में ओलिंपिक के इतिहास में खिताब बरकरार रखने वाले पांचवां पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी बनने के इरादे से उतरेंगे।

लास एंजिलिस की तैयारी शुरू की: मनु

नई दिल्ली, प्रेट्र: पेरिस में इतिहास रचने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने शुक्रवार को वतन वापसी करते ही 2028 में होने वाले लास एंजिलिस ओलिंपिक में अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। पेरिस ओलिंपिक में भारतीय दल ने देश के नाम तीन पदक किए जिसमें अकेले मनु भाकर ने अपने कौशल के दम पर दो कांस्य पदक जीते। एक ओलिंपिक में लगातार दो पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट मनु भाकर ने वतन वापसी करते हुए बताया, 'अब मेरे दिमाग में 2028 में होने वाला ओलिंपिक है और इसकी यात्रा शुरू हो चुकी है, थोड़े ब्रेक के बाद मैं इसकी तैयारी में लग जाऊंगी।'

पेरिस में विनेश के वर्ग में खेलने वाली अंतिम पंघाल पहले ही दौर में हारीं

पेरिस, प्रेट्र : पेरिस ओलिंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती में भारतीय अभियान को दूसरा झटका लगा, जब पदक की प्रबल दावेदार अंतिम पंघाल को बुधवार को 53 किग्रा प्रीक्वार्टर फाइनल में तुर्किये की जेनेप येतगिल के हाथों तकनीकी श्रेष्ठता (0-10) के आधार पर हार का सामना करना पड़ा। चौथी वरीयता प्राप्त अंतिम दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन और पिछले साल हांगझू में एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता हैं। हालांकि तुर्किये की पहलवान के सामने वह अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं सकीं।

अन्नू रानी 15वें स्थान पर: महिलाओं की भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकार्ड धारक अन्नू रानी ने क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान 55.81 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास दर्ज किया। अन्नू 62 मीटर के योग्यता मानक को पूरा नहीं कर पाई। पुरुषों की ऊंची कूद में कुशारे 2.29 मीटर योग्यता मानक से पीछे रह गए। राष्ट्रीय रिकार्डधारी भारत की 100 मीटर की बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी पहली हीट में खराब प्रदर्शन के बाद सातवें स्थान पर रही। याराजी ने चौथी हीट में 13.16 सेकेंड का समय लिया।

दीक्षा डागर पहले दिन संयुक्त सातवें, अदिति 13वें स्थान पर

नई दिल्ली, जेएनएन : भारत की दीक्षा डागर और अदिति अशोक बुधवार को पेरिस ओलिंपिक की महिला गोल्फ स्पर्धा में भाग लेते हुए पहले राउंड की समाप्ति के बाद क्रमशः संयुक्त रूप से सातवें और 13वें स्थान पर रहीं। गोल्फ में प्रतिस्पर्धा करते हुए दीक्षा डागर ने एक अंडर-71 का स्कोर दर्ज किया और वह पांच अन्य खिलाड़ियों के साथ सातवें स्थान पर रहीं। 2021 के डेफलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता ने दिन के अधिकांश समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 17वें और 18वें होल पर बोगी करने की वजह से वह लीडरबोर्ड पर नीचे खिसक गईं। पेरिस 2024 में महिला गोल्फ में 60 गोल्फर शामिल हैं, जो चार दिनों में चार राउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक राउंड में 18 होल हैं। इस बीच, भारत की नंबर एक गोल्फर अदिति अशोक ने पहले नौ होल में दो बर्डी के साथ अच्छी शुरुआत की। हालांकि, उन्हें 18वें होल पर पानी मिलने की वजह से डबल बोगी से जूझना पड़ा और वह शीर्ष तीन से नीचे खिसक गईं।

टेबल टेनिस में समाप्त हुआ अभियान: अर्चना कामथ ने बुधवार को महिला टेबल टेनिस टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में कुछ देर तक चुनौती पेश की लेकिन उनका प्रदर्शन भी काफी नहीं था जिससे भारतीय टीम को तकनीकी रूप से बेहतर जर्मनी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टेबल टेनिस में भारतीय अभियान समाप्त हो गया।

मिजेन ने लगाया 'स्वर्णिम पंजा'

ओलिंपिक में विश्व

पेरिस, रायटर: क्यूबा के दिग्गज पहलवान मिजेन लोपेज ने मंगलवार को 130 किग्रा ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में लगातार पांचवें ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह एक ही स्पर्धा में लगातार पांच ओलिंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस जीत के साथ ही उन्होंने कुश्ती को भी अलविदा कह दिया।

41 वर्षीय पहलवान अंतिम बार 2015 में तुर्किये के पहलवान रिजा कयाल्प से विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में हारे थे। इसके बाद से वह एक भी मुकाबला नहीं हारे। चिली के रजत पदक विजेता पहलवान यस्मानी अकोस्टा को 6-0 से हराकर स्वर्ण जीतने वाले क्यूबाई पहलवान के लिए यह जीत विशेष है क्योंकि अंतिम बार वह वैश्विक स्तर पर तीन वर्ष पूर्व टोक्यो ओलिंपिक के फाइनल में खेले थे।

इस जीत के बाद उन्होंने मैट पर अपने जूते रखकर संन्यास की घोषणा कर दी। लोपेज ने कहा, 'यह प्रदर्शित करने का क्षण है कि किसी ने कुश्ती से आधिकारिक तौर पर संन्यास ले लिया है। साथ ही यह संदेश भी है कि अब युवा पीढ़ी के लिए दूसरों को प्रेरित करने का रास्ता खुल गया है।' उन्होंने जीत के बाद एक कोच पर दांव लगाया। लोपेज ने अंत में अलविदा कहने से पूर्व मैट पर मत्था भी टेका।

सीन नदी में अभ्यास कर रहे मैराथन तैराक: पेरिस के आयोजकों द्वारा यह निर्धारित करने के बाद कि इसमें गोता लगाना सुरक्षित है, ओलिंपिक के खुले पानी के तैराकों ने बुधवार को लंबे समय से प्रदूषित सीन नदी में प्रशिक्षण लिया।

ड्रग्स खरीदने पर हाकी खिलाड़ी क्रेग हिरासत में

पेरिस, एपी: आस्ट्रेलियाई ओलिंपिक फील्ड हाकी टीम के खिलाड़ी टाम क्रेग को कोकीन खरीदने के प्रयास के बाद हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मंगलवार की रात पेरिस में एक इमारत के बाहर ड्रग लेन-देन रोका। यह मामला पुलिस की ड्रग रोधी इकाई को सौंप दिया है। यह कथित खरीदार आस्ट्रेलियाई फील्ड हाकी टीम का 28 वर्षीय सदस्य था और 17 वर्षीय कथित विक्रेता को भी हिरासत में लिया गया। आस्ट्रेलियाई ओलिंपिक समिति ने एक बयान में कहा कि कोई आरोप दायर नहीं किया गया है और कहा कि वह टीम के सदस्य के लिए सहायता की व्यवस्था कर रही है।

आज के कार्यक्रम

गोल्फ: महिला व्यक्तिगत स्पर्धा राउंड 2, दोपहर 12:30 बजे, **दीक्षा डागर, अदिति अशोक**

एथलेटिक्स: महिला 100 मीटर बाधा दौड़ रेपचेज, दोपहर 2:05 बजे, **ज्योति याराजी**

- भाला फेंक फाइनल, रात 11:55 बजे, **नीरज चोपड़ा**

कुश्ती: पुरुष 57 किग्रा प्री क्वार्टर फाइनल, दोपहर 2:30 बजे, **अमन सहरावत बनाम व्लादिमीर इगोरोव**

- महिला 57 किग्रा फ्रीस्टाइल प्री क्वार्टर फाइनल, दोपहर 2:30 बजे, **अंशु मलिक बनाम हेलेन लुइस**

हाकी: कांस्य पदक मुकाबला, शाम 5:30 बजे, भारत बनाम स्पेन

तालिका

देश	सोना	चांदी	कांस्य	कुल
1 अमेरिका	25	33	32	90
2 चीन	24	22	16	62
3 आस्ट्रेलिया	17	12	10	39
4 फ्रांस	13	16	20	49
5 ग्रेट ब्रिटेन	12	16	20	48
6 जापान	12	6	12	30
7 द. कोरिया	11	8	7	26
8 इटली	9	10	8	27
9 नीदरलैंड्स	9	5	6	20
10 जर्मनी	8	5	4	17
64 भारत	0	0	3	3

पदक तालिका *रात 12 बजे तक

****

27 वर्ष बाद भारतीय टीम श्रीलंका में हारी वनडे सीरीज

249 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 26.1 ओवर में 138 रनों पर आलआउट हो गई रोहित की टीम

कोलंबो, प्रेट्र : 1997 के बाद भारतीय टीम बुधवार को श्रीलंका में वनडे सीरीज हार गई। ये बताता है कि कुछ महीने पहले बारबाडोस में रोहित की कप्तानी में टी-20 जीतने वाली भारतीय टीम की हालत क्या है। भारत को अगले साल वनडे प्रारूप में होने वाली चैंपियंस ट्राफी जीतने का लक्ष्य रखा है लेकिन उससे पहले नए कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित की टीम को सिर्फ छह वनडे खेलने थे जिसमें से तीन वनडे की सीरीज वह 0-2 से हार गई। एक मैच टाई हुआ था।

अपने चोटिल खिलाड़ियों से परेशान दुनिया की सातवें नंबर की टीम श्रीलंका ने अंतरिम कोच सनथ जयसूर्या के आते ही दुनिया की नंबर वन भारतीय टीम को तीनों मैचों में मजा चखाया। आखिरी मैच में तो भारतीय टीम 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 138 रनों पर आलआउट हो गई। भारतीय टीम को 110 रनों से हार मिली। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों की हालत खराब हो गई और उसे 27 सालों के बाद श्रीलंका में द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 35 रनों की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर 30 रन बनाकर आउट हुए। कोहली 20 और रियान 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विराट ने इस सीरीज में 19.33 के औसत से रन बनाए। यह श्रीलंका के विरुद्ध सात द्विपक्षीय वनडे सीरीज में उनका न्यूनतम औसत है। इसके अलावा 2008 में अपनी पदार्पण सीरीज में श्रीलंका के विरुद्ध उनका औसत 30 से कम रहा था। श्रीलंका की तरफ से दो स्पिनरों वेलालागे और वेंडरसे ने सात विकेट लिए। तीन मैचों की सीरीज में भारतीय बल्लेबाज श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने जूझते रहे। कभी भारतीय टीम को स्पिनरों को खेलने में माहिर माना जाता था लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे बल्लेबाज उसमें भी असफल साबित हुए हैं।

आते ही छा गए पराग : इस मैच में वनडे में पदार्पण करने वाले आलराउंडर रियान पराग ने अपनी आफ स्पिन का कमाल दिखाते हुए नौ ओवर में 54 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने बीच के ओवरों में भारत को वापसी दिलाने की कोशिश की लेकिन बाद में हमारे बल्लेबाजों ने दिखाया कि वे इतने रन बनाने की भी क्षमता नहीं रखते हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर सिर्फ एक-एक विकेट ले सके। फर्नांडो और कुसाल मेंडिस ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से रन जुटाकर श्रीलंका को मजबूत स्थिति में रखा। फर्नांडो ने सिराज के खिलाफ आसानी से रन जुटाए। फर्नांडो ने पुल शॉट से सिराज पर लगातार दो छक्के मारे। फर्नांडो पराग की सीधी गेंद पर पगबाधा हो गए और अपने चौथे एकदिवसीय शतक से चूक गए। श्रीलंका का स्कोर 36वें ओवर में दो विकेट पर 171 रन था और मेजबान टीम 280 रन के करीब पहुंचने की स्थिति में दिख रही थी। पराग ने इसके बाद कप्तान चरिथ असलंका (10) को पगबाधा किया और फिर दुनिथ वेलालागे (02) को पवेलियन भेजकर लय तोड़ी। कुसाल मेंडिस और कामिंदु मेंडिस (नाबाद 23) ने सातवें विकेट के लिए 36 रन जोड़कर टीम का स्कोर 250 रन के करीब पहुंचाया।

विकेट लेने के बाद खुशी जताते श्रीलंकाई गेंदबाज वेलालागे ● प्रेट्र

स्कोर बोर्ड

श्रीलंका : 248/7 (50 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
निसांका का. पंत बो. अक्षर	45	65	5/2
अविष्का एलबीडब्ल्यू बो. पराग	96	102	9/2
कुसल का. शुभमन बो. कुलदीप	59	82	4/0
असलंका एलबीडब्ल्यू बो. पराग	10	12	0/1
समरविक्रमा एलबीडब्ल्यू बो. सिराज	00	01	0/0
लियानागे बो. सुंदर	08	12	1/0
वेलालागे बो. पराग	02	03	0/0
कामिंदु अविजित	23	19	0/1
तीक्षणा अविजित	03	04	0/0

अतिरिक्त : 2 (लेबा-1, वा-1)

विकेटपतन: 1-89 (निसांका, 19.5), 2-171 (अविष्का, 35.3), 3-183 (असलंका, 37.6), 4-184 (समरविक्रमा, 38.5), 5-196 (लियानागे, 42.4), 6-199 (वेलालागे, 43.3), 7-235 (कुसल, 48.4)

गेंदबाजी: सिराज 9-0-78-1, दुबे 4-0-9-0, अक्षर 10-1-41-1, सुंदर 8-1-29-1, कुलदीप 10-0-36-1, पराग 9-0-54-3

भारत : 138 (26.1 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
रोहित का. कुसल बो. वेलालागे	35	20	6/1
शुभमन बो. असिथा	06	14	0/0
कोहली एलबीडब्ल्यू बो. वेलालागे	20	18	4/0
पंत स्टं. कुसल बो. तीक्षणा	06	09	1/0
श्रेयस एलबीडब्ल्यू बो. वेलालागे	08	07	2/0
अक्षर बो. वेलालागे	02	07	0/0
पराग बो. वेंडर्से	15	13	2/0
दुबे एलबीडब्ल्यू बो. वेंडर्से	09	14	1/0
सुंदर का. वेंडर्से बो. तीक्षणा	30	25	2/3
कुलदीप एलबीडब्ल्यू बो. वेलालागे	06	30	0/0
सिराज अविजित	00	00	0/0

अतिरिक्त : 1 (लेबा-1)

कुल: 26.1 ओवर में 138 रन पर सभी आउट

विकेटपतन : 1-37 (शुभमन, 4.3), 2-53 (रोहित, 7.1), 3-63 (पंत, 9.2), 4-71 (कोहली, 10.5), 5-73 (अक्षर, 12.1), 6-82 (अय्यर, 12.5), 7-100 (पराग, 15.6), 8-101 (दुबे, 17.3), 9-138 (सुंदर, 25.6)

गेंदबाजी: असिथा 5-0-29-1, तीक्षणा 8-0-45-2, वेलालागे 5.1-0-27-5, वेंडर्से 5-0-34-2, असलंका 3-1-2-0

आपके लिए 'डार्क पैटर्न' शब्द नया हो सकता है, लेकिन इसका अनुभव निश्चित ही नया नहीं होगा। आनलाइन शापिंग या बुकिंग के दौरान हिडेन चार्जेज, भ्रामक सवाल, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जैसे शब्दों के जाल में आप कैसे उलझ सकते हैं, बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...

फोटो : फ्रीपिक

डार्क पैटर्न

लोकप्रिय एप के हैं बड़े धोखे भी

कुछ रील्स देखकर जतिन ने फ्री ट्रायल के लिए एक ओटीटी एप पर साइनअप कर लिया। बाद में कंटेंट उबाऊ लगा, तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का मन बनाया। अब कई दिनों की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी वह सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। संभव है जतिन एप के 'डार्क पैटर्न' का शिकार हो गए हैं। दरअसल, 'डार्क पैटर्न' ऐसी शातिराना चाल है, जहां न चाहते हुए भी एप के हितों में फैसले लेने पड़ते हैं और जोखिम में होते हैं- आपकी निजता, डाटा और आपके डिजिटल अधिकार। उदाहरण के तौर पर, आप ट्रैकिंग कुकीज के लिए 'असेप्ट आल' पर क्लिक कर बैठते हैं या फिर खरीदारी की जल्दबाजी में बिना पढ़े ही 'नियम-शर्तों' को स्वीकार कर लेते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआइ) और पैरेलल एचक्यू का एक नया अध्ययन है कि 79 प्रतिशत भारतीय एप्स निजी डाटा एक्सेस देने के लिए यूजर्स को बाध्य करते हैं। इनमें ई-कामर्स, हेल्थ और फिनटेक, कैब बुकिंग, डिलीवरी एप्स शामिल हैं, जिनके 21 अरब से अधिक डाउनलोड हैं।

क्या पैटर्न है डार्क पैटर्न का: आपने आनलाइन बिरयानी आर्डर की और जब पेमेंट करने लगे, तो अमाउंट बढ़ गया, ये भी डार्क पैटर्न हो सकता है। इसी तरह किसी सब्सक्रिप्शन को बंद करने या किसी एप से अपने अकाउंट को डिलीट करने में मुसीबत आ रही है, तो संभव है कि आप डिसेप्टिव या डार्क पैटर्न में फंस गए हैं। किसी आनलाइन सर्विस के 'नियम और शर्तों' को पढ़ या समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये डार्क पैटर्न का बुना जाल हो सकता है। 80 प्रतिशत एप्स की सेटिंग या प्रोफाइल सेक्शन में आमतौर पर डार्क पैटर्न होता है। मानव मनोविज्ञान, पूर्वाग्रह और कमजोरियों को समझते हुए, ऐसे प्रोग्राम डिजाइन होते हैं, जो अनपेक्षित व अनावश्यक खरीदारी, साइनअप, इंश्योरेंस कवरेज, रिकरिंग बिलिंग आदि के लिए बाध्य कर देते हैं।

क्या हो सकता है डार्क पैटर्न

- यूजर को इच्छा से अधिक जानकारी साझा करने के लिए बाध्य करना।
- कम कीमत का लालच देकर अनुपलब्धता दिखाना व वैकल्पिक तौर पर महंगा खरीदने के लिए प्रेरित करना।
- ग्राहक को प्रोग्राम इंस्टालेशन के दौरान अनपेक्षित शर्तों को स्वीकार कराना।
- भ्रामक भाषा का प्रयोग करना।
- सर्विस कैंसिलेशन के समय लंबी कालिंग प्रक्रिया, इंतजार कराना।
- कीमतों की तुलना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन कर देना।

एआइ ने बढ़ा दी है चुनौती: एआइ आधारित डार्क पैटर्न यूजर की निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित कर सकता है यानी एआइ मानव साइकोलाजी और बर्ताव को अधिक प्रभावित कर सकता है। डीपफेक के जरिए धोखा नया नहीं है। फेक इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल से जोखिम पैदा किया जा सकता है।

डार्क पैटर्न से बचने के उपाय

- कोई पुख्ता समाधान संभव नहीं है।
- आनलाइन सेवाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- एप्स के इंटरफेस की निगरानी आवश्यक है।

चार डिजिटल हैबिट हैं बड़े काम की

1. **जल्दबाजी से बचें:** डार्कपैटर्न प्रयोग करने वाली कंपनियां आपकी जल्दबाजी पर भी नजर रखती हैं। ठहरें, आनलाइन खरीदारी और निर्णय सोच-समझकर ही करें। सावधानी से चेकबाक्स को टिक करें। भुगतान से पहले शापिंग कार्ट की समीक्षा करें, साइनअप व सब्सक्रिप्शन लेते समय नियमों व शर्तों का ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. **निजता प्रबंधन की आदत बनाएं:** कोई कंपनी आपसे कौन सी निजी सूचनाएं ले रही है, इसे लेकर जागरूक रहें। प्राइवेसी सेटिंग जितना संभव हो सके, सख्त रखें। प्राइवेसी मैनेजमेंट प्लान को लेकर सक्रिय रहें, इससे जोखिम कम रहेगा। जैसे वेबसाइट की कुकीज को स्वीकारने से बचें और ऐसे ब्राउजर का प्रयोग करें जो डाटा को ट्रैक और सेल न करता हो।
3. **अपने अधिकारों को समझें:** उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, निजता से जुड़े कानूनों को भी जानें। डार्क पैटर्न को लेकर गत वर्ष भारत सरकार की तरफ से एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया था। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत भी नियमों को सख्त बनाया गया है।
4. **गलत बर्ताव को रिपोर्ट करें:** अगर किसी एप या वेबसाइट में आपको डार्क पैटर्न जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है या जिससे आपको नुकसान होने की आशंका है, तो पहले उसे कन्फर्म करें और उचित फोरम पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसकी जानकारी संबंधित कंपनी को टैग करते हुए आप इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर भी साझा कर सकते हैं।

गैजेट रिव्यू

गैलेक्सी जेड फ्लिप 6

किसी रफ स्केच को आर्टवर्क में बदलना हो, पसंदीदा भाषा में अनुवाद हो या फिर सर्कल बनाकर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, जेड फ्लिप 6 फोन का गैलेक्सी एआइ कुछ ही सेकंड में कर देता है। आटो फोकस फीचर तो आकर्षक हैं। खास बात है कि फोल्ड करने पर यह मिनी लैपटाप की तरह बन जाता है।

डिजाइन और डिस्प्ले : एल्युमिनियम मैट फिनिश से आकर्षक दिखता है। कवर स्क्रीन सुपर एमोलेड 3.4 इंच, 60 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यहां नोटिफिकेशन, क्विक सेटिंग और विजेट मिलते हैं। इंटरप्रेटर मोड, वाट्सएप नोटिफिकेशन (क्विक रिप्लाई की सुविधा के साथ) और मैप की भी सुविधा है, हालांकि मोटोरोला का प्रतिस्पर्धी माडल इस मामले में थोड़ा बेहतर है। अंदर की स्क्रीन 6.7 इंच (एफएचडी+ डायनेमिक एमोलेडस्क्रीन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट) की है, जिसमें 2600 निट्स तक ब्राइटनेस है। सूर्य की रोशनी में भी आप सहजता से काम कर सकते हैं। स्क्राल करते हुए गौर करने पर ही स्क्रीन पर क्रीज को हल्का सा महसूस कर सकते हैं।

कैमरा : 50 एमपी मेन कैमरा व 12 एमपी अल्ट्रावाइड और 10 एमपी का सेल्फी कैमरा है। अल्ट्रावाइड कैमरे से ग्रुप शाट और लैंडस्केप इमेज ले सकते हैं। कैमरा एप में आटो फोकस जैसे कुछ उपयोगी फीचर्स हैं।

परफार्मेंस एवं साफ्टवेयर : यह एंड्रायड 14 और वन यूआइ 6.1.1 आधारित है। इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिप है। 12 जीबी रैम एआइ फीचर के प्रयोग में सहजता प्रदान करती है। सबसे खास बात है कि फोन में सात वर्ष ओएस और सिक्योरिटी अपडेट की सुविधा दी गई है।

एआइ फीचर्स : कैमरा एप, नोट टेकिंग, ट्रांसक्राइबिंग के अलावा कवर स्क्रीन पर स्मार्ट रिप्लाई की सुविधा है।

बैटरी : 4000 एमएएच की बैटरी सिंगल चार्ज पर 24 घंटे चल जाती है। यह यूट्यूब पर वीडियो देखने, पिक्चर और वीडियो शूट करने और एआइ से इन्हें एडिट करने के लिए पर्याप्त है। 80 प्रतिशत तक चार्ज करने के लिए घंटे भर का समय लग जाता है, चार्जिंग स्लो है।

कीमत : 12 जीबी + 256 जीबी वैरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये और 12 जीबी +512 जीबी वैरिएंट की कीमत 1,21,999 रुपये है।

वर्ग पहेली - 2715

बाएं से दाएं

1. क्रमबद्धता, सिलसिला (4)। 3. छटपटाना, कुलबुलाना, बेचैनी होना (5)। 5. प्रलय, आफत, हंगामा (4)। 7. काल, वक्त (3)। 8. रुपया-पैसा (3)। 9. गहरा होना या करना (4)। 11. हाथ से फेंका जाने वाला विस्फोटक गोला (4)। 14. असुर (3)। 16. सरल, सुगम (3)। 17. भावुक होने का भाव (4)। 19. एक स्थान पर कैद (5)। 20. उहा-पोह, असमंजस की स्थिति (4)।

ऊपर से नीचे

1. उपयोग में नहीं लाया हुआ (5)। 2. क्रम संख्या (3)। 3. अधिक छोटा (4)। 4. विष्णु का यह भी नाम है (4)। 6. मांगना, प्रार्थना करना (3)। 7. सामर्थ्यवान (4)। 10. भगवान राम के आदर्श शासन का रूपक (4)। 11. गले की नली, कंठ (3)। 12. लाभ पहुंचाने वाला, लाभ दायक (2,3)। 13. नभ, आकाश, गगन (4)। 15. अदालत की पंचायत का सदस्य (4)। 18. आंख की पुतली, तारने वाला (3)।

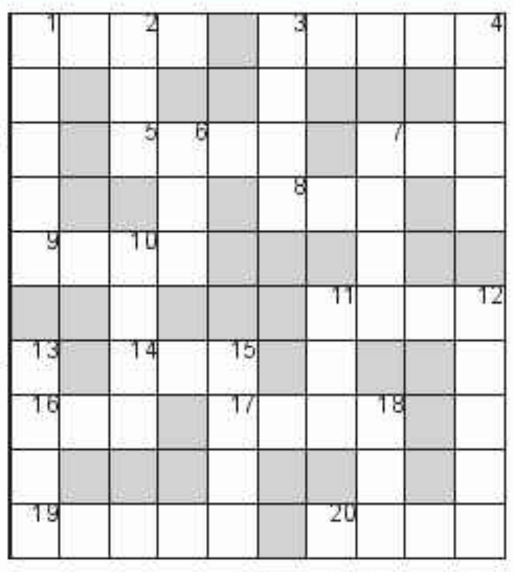

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

सु		सु	न	सा	न		म	जा	क
ले		ला					हा		
ख	ल	ना	य	क			ना	य	क
			ती		वि	ष	य		ज
त			म	जा	र		क		रा
र		गा		न	ह	र			रा
क		त	इ	ना		च			
श	रा	ब			ब	ना	ब	ना	या
		जा					ता		च
चौ	बा	ना		पु	का	र	ना		ना

जागरण सुडोकू-2715

		5		6		7		3
6	4				2			5
		1	7			6	4	
3			2			5		1
	7	2			9		8	
8				1				7
7				2		4	3	
	2	8		4			7	
4			1		6			2

कल का हल

5	7	9	3	6	8	2	4	1
1	8	6	4	2	7	3	9	5
4	3	2	5	1	9	6	8	7
2	1	5	7	9	3	4	6	8
6	9	3	1	8	4	5	7	2
8	4	7	2	5	6	1	3	9
9	5	4	8	3	2	7	1	6
3	2	8	6	7	1	9	5	4
7	6	1	9	4	5	8	2	3

आज का भविष्यफल- 08 अगस्त, 2024 गुरुवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आज का राहुकाल : दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक। दिशाशूल : दक्षिण। पर्व एवं त्योहार : दूर्वा गणपति चतुर्थी
आज की भद्रा : प्रातः 11 बजकर 22 मिनट से रात्रि 12 बजकर 37 मिनट तक।

कल 09 अगस्त, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : श्री नागपंचमी
विशेष : कालसर्प, गुरुचांडाल योग, अंगारक। वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तत्पश्चात षष्ठी हस्त नक्षत्र 26 घंटे 45 मिनट तक, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र सिद्ध योग 13 घंटे 45 मिनट तक, तत्पश्चात साध्य योग कन्या में चंद्रमा।

- **मेष :** पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
- **वृष :** आर्थिक सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा।
- **मिथुन :** सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
- **कर्क :** भाई-बहन का सहयोग मिलेगा। उपहार में वृद्धि होगी।
- **सिंह :** धनलाभ मिल सकता है। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
- **कन्या :** आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
- **तुला :** रिश्तों में निकटता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।
- **वृश्चिक :** पिता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सफलता मिलेगी।
- **धनु :** जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
- **मकर :** शासन का सहयोग रहेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।
- **कुंभ :** शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
- **मीन :** मन अशांत रहेगा। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद रहेंगे।

टेक अपडेट

चैटबाट के इस्तेमाल में रहे सतर्कता

बैंकिंग, ई-कामर्स से लेकर बुकिंग तक चैटबाट आज डिजिटल रिसेप्शनिस्ट हैं। समाधान के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले चैटबाट से आपको कैसे और क्या पूछना है, यह जानना आवश्यक है...

आनलाइन शापिंग, बैंकिंग, टिकट बुकिंग से लेकर हेल्थ, इंश्योरेंस जैसी तमाम जनकारियों के लिए आज चैटबाट एक मददगार टूल है। एआइ तकनीक के दौर में यह अनोखे सर्च इंजन की तरह काम करता है, जिससे सवालों के जवाब तुरंत हासिल किए जा सकते हैं। चैटबाट वास्तव में एक कंप्यूटर साफ्टवेयर है, जिससे 'इंसानी बातचीत' इंटरनेट के जरिए की जा सकती है।

कैसे प्रयोग में लाते हैं चैटबाट : जब हम किसी ड्रेस की शापिंग के लिए ई-कामर्स वेबसाइट पर होते हैं और साइज के बारे में चैट विजिट पर क्लिक कर पूछते हैं- साइज फिट नहीं होने पर इसे कैसे वापस कर सकता हूं? तो चैटबाट 'शिपिंग और रिटर्न' पेज के लिंक के साथ जवाब देता है। इसी तरह पालिसी, लोन, प्रोफेशनल कोर्स या रोग के उपचार के बारे में बता देता है। इसकी सटीकता हमारे सवाल पर भी निर्भर करती है, जैसे यात्रा संबंधी जानकारियों के लिए जगह का सही नाम, जिला या राज्य के नाम के साथ पूछा जाना चाहिए। इसी तरह माप के पैमाने में एमएम, सीएम और इंच आदि की जानकारी का ध्यान रखना चाहिए।

चैटबाट के प्रयोग में सावधानी : यह महत्वपूर्ण है कि चैटबाट के साथ आप एक सुरक्षित वेबसाइट पर हैं या नहीं, क्योंकि शुरुआती स्क्रिप्ट या नियमों में बंधे चैटबाट की तुलना में अब एडवांस्ड चैटबाट मशीन लर्निंग तरीके के चैटजीपीटी, बार्ड, जेमिनी या मेटा के एआइ साफ्टवेयर से जुड़े हैं। इसकी निर्भरता एनएलपी यानी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पर है। यह चैटबाट को लिखित और मौखिक जानकारी का विश्लेषण करने में मदद करता है। इसका मजबूत नेटवर्क इंसानी समझ को सोचने और अनुभव के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग करता है। इससे चैटबाट के जवाब में सटीकता और तीव्रता आती है।

शंभु सुमन

सुरक्षा के लिए कुछ बातों का रखें ध्यान

चैटबाट अनेक तरह के होते हैं- इंस्टेंट मैसेजिंग के नियम-आधारित चैटबाट, मशीन लर्निंग चैटबाट, भाषा माडल चैटबाट, हाइब्रिड चैटबाट, इंटरनेट मीडिया चैटबाट और वायस चैटबाट। समझना जरूरी है कि 24 घंटे सहायता देने वाले चैटबाट के इस्तेमाल में किस स्तर की सतर्कता बरतनी है? विशेषकर साइबर सुरक्षा के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है-

- **चैटबाट के साथ निजी जानकारी कतई साझा नहीं करें, जैसे- ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, खाता संख्या, पता, फोन नंबर आदि तब तक दर्ज नहीं करें, जब तक अनिवार्यता न हो।**
- **अज्ञात नंबरों से आने वाले संदेशों या काल का जवाब ना दें।**
- **अपरिचित लोगों या कंपनियों से आने वाले ई-मेल से सावधान रहें।**
- **बच्चों द्वारा चैटबाट के इस्तेमाल के दौरान उन पर नजर रखें, क्योंकि चैटबाट का उपयोग 13 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है।**
- **अनएन्क्रिप्टेड या असुरक्षित वेबसाइटों पर चैटबाट का उपयोग करने से बचें।**
- **चैटबाट प्रयोग की शर्तें और नियम बनाए गए हैं, यह ध्यान रखें कि इसका उपयोग सामान्य स्थिति के लिए है, आपातकालीन के लिए नहीं।**

राष्ट्रीय फलक

आज होंगे बाबा चट्टानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं की भारी भीड़

जागरण संवाददाता, जम्मू

- पूजा के बाद सुबह रवाना हुए पहले जत्थे का जम्मू से पुंछ तक भव्य स्वागत
- मंडलायुक्त ने 750 से अधिक श्रद्धालुओं को किया रवाना

बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा का पहला जत्था बुधवार तड़के ढोल नगाड़ों के बीच जम्मू से पुंछ रवाना हुआ। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी यात्रा का संचालन करता है। पहले जत्थे में शामिल देश भर से आए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। भगवती नगर यात्री निवास से पहले जत्थे में शामिल 750 से अधिक श्रद्धालुओं को मंडलायुक्त रमेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने भगवा झंडा दिखा कर यात्रा को रवाना किया। देर शाम जम्मू से यात्रा कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच पुंछ पहुंच चुकी थी। श्रद्धालु रात को मंडी में विश्राम करने के बाद रविवार सुबह राजपुरा स्थित बाबा बुड्ढा अमरनाथ के पवित्र मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। मान्यता है कि श्रावण मास में किसी समय बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की जा सकती है। पुंछ जिले में बाबा बुड्ढा अमरनाथ स्थल (बाबा चट्टानी, यानी सफेद चट्टान से बना शिवलिंग) की उतनी ही महत्ता है जितनी कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की।

मंडलायुक्त रमेश कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। एडीजीपी आनंद जैन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दनोरिया ने कहा बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी के क्षेत्र से पलायन कर चुके हिंदुओं को पुनः वहां बसाना ही बजरंग दल का उद्देश्य है। यात्रा के पहले जत्थे के साथ 750 श्रद्धालु छोटे बडे.13 वाहनों में रवाना हुए। अमरनाथ बुड्ढा अमरनाथ यात्री निवास के अध्यक्ष पवन कोहली, बाबा यात्री न्यास के महामंत्री सुदर्शन खजूरिया, बजरंग दल प्रांत संयोजक कार्तिक एवं कई अन्य बजरंगी उपस्थित थे। यात्रा का अखनूर में स्वागत किया। अखनूर में स्वागत करने वालों में महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास, शाम लाल शर्मा एवं कई लोग स्वागत के लिए पहुंचे थे।

रिमझिम फुहारों संग हिंडोले में झूले ठाकुर बांकेबिहारी

जागरण संवाददाता, मथुरा

- दिव्य स्वर्ण-रजत हिंडोले में आराध्य को आस्था की डोर से भक्तों ने झुलाया
- हरियाली तीज पर आराध्य ने आठ घंटे के बजाय भक्तों को दिए साढ़े 13 घंटे दर्शन

आसमान में उमड़ते-घुमड़ते काले बादल और रिमझिम फुहारों के बीच लाड़ले बांकेबिहारी ने स्वर्ण-रजत हिंडोले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए तो आस्था का समंदर मंदिर में उमड़ने लगा। हिंडोले में विराजित ठाकुर बांकेबिहारी की एक झलक पाने को मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सेवायतों ने भी हरियाली तीज पर बुधवार को तय समय से डेढ़ घंटे पहले मंदिर के पट खोल दिए। हिंडोले में आराध्य की छवि निहारते ही श्रद्धालु सुधबुध खो बैठे। हरे परिधान में स्वर्ण श्रृंगार कर ठाकुर बांकेबिहारी ने महारास की मुद्रा में दर्शन दिए तो मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। सुबह पांच बजे से ही श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर डेरा डाल दिया। भीड़ बढ़ते देख सेवायतों ने सुबह सवा छह बजे मंदिर के पट खोल दिए। मंदिर के जगमोहन में बेशकीमती स्वर्ण रजत हिंडोले में हरे परिधान और हीरे जवाहरात धारण कर आराध्य बांकेबिहारी झोटे ले रहे थे तो भक्तों की आस्था का ज्वार बढ़ता नजर आया। बांकेबिहारी के जयकारे और सावन की मल्हार के स्वर वातावरण में गूंज रहे थे।

झूलन चलो हिंडोला बृषभानु नंदनी को... राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा, झुक आए बदरा, झुकी आए बदरा..1 बुधवार को इस भजन की पंक्तियां रिमझिम वर्षा के दौरान हरियाली तीज के पर्व पर बरसाना में सुनने को मिलीं। लाड़ली महल में बृषभानु नंदनी ने अपने नंदलाल के साथ मोरपंख से सुसज्जित हरी पोशाक धारण कर स्वर्ण हिंडोले में झूला झूला। ब्रह्मांचल पर्वत पर छाई हरी छटा के बीच स्थित लाड़ली जी मंदिर का दृश्य मनोरम रहा। सुबह आठ बजे सेवायतों ने राधाकृष्ण के श्रीविग्रह को गर्भगृह से बाहर जगमोहन में स्थित सोने-चांदी से जड़ित स्वर्ण हिंडोले में विराजमान कराया। मोरपंख से सुसज्जित हरे वस्त्र की पोशाक धारण कर मनमोहनी श्रृंगार से प्रिया-प्रियतम की झांकी आलौकिक व अद्भुत नजर आ रही थी। सेवायतों ने छप्पन व्यंजनों से भोग लगाया। शाम पांच बजे राधारानी की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा को मंदिर के गर्भगृह से नीचे परिसर में बनी संगमरमर की सफेद छतरी में लाया गया, जहां से उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए।

वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में हरियाली तीज पर स्वर्ण-रजत हिंडोले में विराजे ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़। जागरण।

श्रद्धा का महासावन

ब्रह्मा व विष्णु भी भगवान शिव को मानते हैं आराध्य

श्रावण शिव भक्तों के लिए अपार श्रद्धा वाला महीना है। इस माह शिव पूजन का विशेष फल मिलता है। भगवान शिव को मात्र जलाभिषेक से प्रसन्न कर पुण्य मिलता है। श्रावण में भगवान शिव अपने भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो भक्त इस माह सोमवार का व्रत कर पूजा करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव कष्टों को हरने वाले देव हैं। अगर किसी को काल सर्प योग हो तो शिव का पूजन और हवन करने से इससे छुटकारा मिलता है। भगवान ब्रह्मा व विष्णु भी भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। वेद, पुराण व उपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों में शिव को आराध्य बताया गया है। भगवान शिव को महाकाल, भूतनाथ, नीलकंठ, अमरनाथ, मुकुटेश्वर महादेव व त्रिलोकीनाथ आदि नामों से भी पुकारा जाता है। श्रावण की महिमा सुनने से सिद्धियां मिलती हैं। संतान प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को गले में धारण कर जगत को बचाया था। बताते हैं कि श्रावण में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था। इसी माह भगवान शिव पहली बार पृथ्वी लोक पर उतरे थे और अपने ससुराल श्रावण माह ही गए थे। श्रावण में भगवान शिव पृथ्वी पर आकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस महीने कांवड़िए जल लाकर शिवालयों में अर्पित करते हैं।

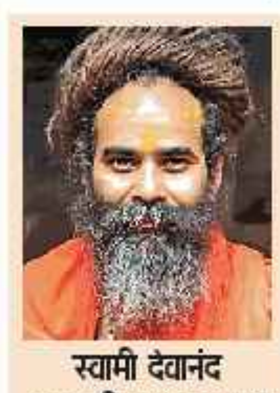
स्वामी देवानंद सरस्वती, महंत भूतनाथ मंदिर मंडी, हिमाचल प्रदेश

छत्तीसगढ़ में होगा देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास-तमोर पिंगला के जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पांच जिलों में फैले गुरु घासीदास उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्रों को सम्मलित करते हुए 2829.387 वर्ग किमी क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

क्षेत्रफल की दुष्टि से यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। 3296.31 वर्ग किमी के साथ आंध्र का नागार्जुन सागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व पहले व 2837.1 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ असम का मानस रिजर्व दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या अब चार हो गई है। बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क व तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा था।

नैनीताल के टिफिनटाप की दरकी पहाड़ी, पर्यटकों की आवाजाही बंद

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- मंगलवार रात दरकी चट्टान के बोल्डरों को नहीं छेड़ा जाएगा, सिंचाई विभाग करेगा ड्रिलिंग

शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टिफिनटाप में मंगलवार रात भूस्खलन से पहाड़ी दरकने के बाद अब प्रशासन ने सुरक्षात्मक कार्यों पर फोकस किया है। सिंचाई विभाग की ओर से टीम बनाकर टिफिनटाप व डोरोथी सीट की दरारों को क्रेक ड्रिलिंग से भरने की तैयारी है। चट्टान से मलबे के साथ पहुंचे बोल्डरों को नहीं छेड़ा जाएगा। इस क्षेत्र में पहुंचने वाले तीनों रास्तों से पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। वन विभाग की शुल्क वसूली चौकी के कर्मचारियों को पर्यटकों व घोड़े-खच्चरों को जाने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही खतरे वाले स्थान पर तारबाड़ कर दी गई है।

बुधवार को एसडीएम प्रमोद कुमार ने सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता डीसी सती व वन विभाग के कर्मचारियों के साथ टिफिनटाप क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। ट्रीटमेंट प्लान को लेकर चर्चा कर बताया कि टिफिनटाप में चट्टान कच्ची थी, जिसमें पहले भी दरारें थी। जिसका अस्थायी ट्रीटमेंट भी पूर्व में किया गया था। स्थायी ट्रीटमेंट यहां संभव भी नहीं है। चट्टान दरकने के बाद विशालकाय बोल्डर निचले हिस्से में सुरक्षित स्थान पर जमे हैं, ऐसे में उनको छेड़ा नहीं जाएगा। क्षेत्र का ड्रोन सर्वे भी कराया जा रहा है। पहुंच मार्गों में सुरक्षा के मद्देनजर तारबाड़ भी लगाई जा चुकी है।

टिफिनटाप भूस्खलन से बढ़ाई नयना पीक से निचले क्षेत्र की आबादी की चिंता: टिफिनटाप में भारी भूस्खलन के बाद अब शहर की सबसे ऊंची चोटी नयना पीक के निचले इलाकों की आबादी की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से नयना पीक चोटी का ट्रीटमेंट कराने की मांग की है ताकि आए दिन गिर रहे पत्थरों को रोका जा सके।

पहलगाम मार्ग पर मरम्मत के कारण बालटाल से अमरनाथ यात्रा से रवाना

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू : पहलगाम मार्ग पर मरम्मत कार्य चलाए जाने के कारण श्री अमरनाथ यात्रा शेष अवधि के लिए बालटाल मार्ग से जाएगी। बुधवार सुबह 635 श्रद्धालुओं का 40वां जत्था बालटाल के लिए रवाना हुआ, जो शाम को पहुंच भी गया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा है कि बारिश से मार्ग को नुकसान हुआ है। इसलिए शेष अवधि के लिए यात्रा बालटाल मार्ग से ही जाएगी।

29 जून से शुरू यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी। यात्रा का मार्ग बदले जाने पर श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन ने श्राइन बोर्ड से जानकारी मांगी है। संगठन ने कहा कि यदि मार्ग बदला गया है तो उन सभी भंडारों को राहत दें जो पहलगाम-चंदनवाड़ी-पवित्र गुफा मार्ग पर यात्रियों के न आने के कारण संचालन बंद करना चाहते हैं। संगठन ने कहा कि यह पहली बार नहीं है पिछले साल यात्रा के दौरान भी पहलगाम, चंदनवाड़ी-पवित्र गुफा मार्ग को बालटाल की ओर मोड़ दिया था।

सिरसा में पुलिस ने डेरा अनुयायियों को किया नजरबंद, इंटरनेट सेवाएं बाधित

डेरा जगमालवाली गद्दी विवाद

जागरण संवाददाता सिरसा/कलावाली

सिरसा के जगमालवाली स्थित डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना बिलोचस्तानी के संत वकील साहब की अंतिम अरदास आठ अगस्त को है। गद्दी विवाद के चलते हरियाणा सरकार ने सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। ये सेवाएं वीरवार रात नौ बजे तक बाधित रहेगी। दूसरी ओर बुधवार रात को डबवाली और कालांवाली पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा अनुयायियों को पकड़ लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर उन्हें नजरबंद कर दिया। इनमें से ज्यादातर वे अनुयायी थे जो कि वीरेंद्र सिंह के गद्दी पर बैठने के विरोधी हैं। अंतिम अरदास के चलते डेरे में भारी पुलिस बल तैनात है।

संत वकील साहब के निधन के बाद चल रहे गद्दी विवाद पर छह दिनों से भूमिगत वीरेंद्र ढिल्लों बुधवार को पुलिस सुरक्षा के बीच डेरे में पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने सचखंड के अंदर जाकर संत वकील साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही उनके स्वजन के साथ दुख साझा किए। दोपहर तीन बजे वीरेंद्र सिंह ने चुनिंदा मीडिया कर्मियों के सामने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि जब तक पूरे मामले की सीबीआइ या हाइकोर्ट से जांच नहीं हो जाती है और डेरा की साध संगत नहीं कहती है तब तक वह गद्दी पर नहीं बैठेंगे और न ही सत्संग करेंगे। मैनेजमेंट कमेटी डेरे का संचालन करेगी और वह पहले की भांति सेवा करूंगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दूसरे डेरे वाले जगमालवाली आश्रम की बदनामी चाहते हैं क्योंकि आज तक डेरे पर कोई उंगली नहीं उठी थी। उन्होंने अमर सिंह का ब्रेनवाश किया और संगत को पीछे लगाना चाहा, लेकिन संगत समझदार है। उसके पास पूरी वसीयत की वीडियो है और सभी प्रूफ है। डेरे की बदनामी न हो इसलिए मीडिया के सामने नहीं आया था।

संतों पर वसीयत के लिए कोई दबाव नहीं था: वीरेंद्र ने कहा कि वकील सुमेर सिंह ने मुझे बताया था कि वकील साहब ने उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम की घोषणा के लिए कहा था। लेकिन वे बीमार हो गए और संत भी बीमार हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा और ट्रस्ट के सदस्यों का क्या कसूर है।

डेरा जगमालवाली में वीरेंद्र सिंह मीडिया के समक्ष वसीयत का असली होने का दावा करते हुए। जागरण

****

दैनिक जागरण
राष्ट्रीय संस्करण
गुरुवार 8 अगस्त, 2024
आजकल
14
www.jagran.com

ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन

1942 में आज ही गांधीजी ने बंबई (अब मुंबई) में अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसी दौरान गांधीजी ने करो या मरो का नारा दिया था तथा देशभर में प्रदर्शन होने लगे थे। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत की आजादी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था।

अंतरिक्ष पहुंचने वाली पहली शिक्षिका बनीं बारबरा मार्गन

2007 में आज ही बारबरा मार्गन सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष पहुंचने वाली पहली शिक्षिका बनी थीं। वह नासा के स्पेस शटल एंडेवर से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थीं। इससे पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए चुनी गई पहली शिक्षिका क्रिस्टा मैकालिफ की 1986 में अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे भीष्म साहनी

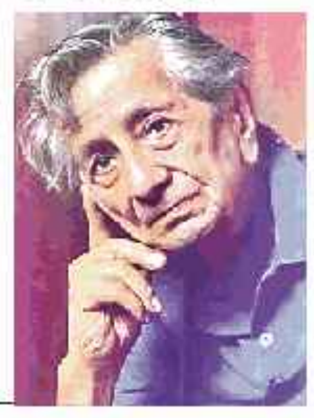

साहित्यकार भीष्म साहनी का जन्म 1915 में आज ही अविभाजित भारत के रावलपिंडी (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। करियर की शुरुआत में अध्यापन किया। बाद में बड़े भाई बलराज साहनी के मार्गदर्शन में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए एवं कई नाटक लिखे। 1974 में प्रकाशित उपन्यास तमस उनकी कालजयी रचना मानी जाती है। हानूश, झरोखे, कबिरा खड़ा बजार में उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं। 1998 में पद्मभूषण से सम्मानित हुए। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे।

आइआइटी इंदौर ने सेना के लिए बनाए विशेष जूते

टीईएनजी तकनीक के जूते ▸ जहां बिजली नहीं, वहां डिवाइस से चार्ज करने में मिलेगी मदद

जूतों को टेस्टिंग करते हुए आइआइटी के प्रोफेसर। सौ : आइआइटी इंदौर

जूतों में लगे हैं जीपीएस और आरएफआइडी सिस्टम भी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

आइआइटी इंदौर ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए ऐसे जूते विकसित किए हैं, जो पहनकर पैदल चलने पर ऊर्जा पैदा करेंगे। सैनिक इनसे अपनी इलेक्ट्रानिक डिवाइस चार्ज कर सकेंगे। जूते ट्राइबो-इलेक्ट्रिक नैनो जेनरेटर (टीईएनजी) तकनीक पर आधारित हैं। संस्थान ने ऐसे 10 जोड़े जूते रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को सौंपे हैं।

जूते बिजली पैदा करने के साथ ही जीपीएस के माध्यम से उस स्थान का भी पता लगा सकेंगे, जहां इन्हें पहनने वाला सैनिक खड़ा होगा। आइआइटी इंदौर के निदेशक प्रो. सुहास जोशी ने कहा कि जूतों को आइआइटी इंदौर के संकाय सदस्य प्रोफेसर आइए पलानी के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। विशेष तौर पर जूते उन सैनिकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जो दूरदराज के इलाकों में तैनात रहते हैं और उनके आसपास दूर-दूर तक विद्युत उपलब्ध नहीं होती। जो सैनिक या व्यक्ति इन जूतों को पहनेगा, उसे वर्षा, बर्फ, धूप जैसी स्थितियों में भी जूतों के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। टीईएनजी संचालित जूतों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) सिस्टम भी लगा है, जो विभिन्न सैन्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

टीईएनजी तकनीक पर आधारित जूते। फाइल

खिलाड़ियों, बुजुर्गों, श्रमिकों के भी आ सकेंगे काम : शोधकर्ता प्रो. पलानी ने कहा कि इन जूतों में टीईएनजी प्रणाली प्रत्येक कदम के साथ बिजली उत्पादन करने के लिए उन्नत ट्राइबो-जोड़े, फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपलीन (एफईपी) और एल्यूमीनियम का उपयोग करती है। ऊर्जा जूते के सोल के भीतर केंद्रीय उपकरण में संग्रहित होती है, जो छोटे पैमाने के इलेक्ट्रानिक सर्किट के लिए एक ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करती है। जीपीएस और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) प्रौद्योगिकियों से लैस ये जूते वास्तविक समय में सैनिकों को लोकेशन ढूंढने में मदद कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग अल्जाइमर पीड़ित बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और पर्वतारोहियों के स्थान को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। कारखानों में श्रमिकों की उपस्थिति और काम की निगरानी करने में भी यह मदद कर सकती है। जूते खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उनकी गतिविधियों का सटीक विश्लेषण भी कर सकते हैं। प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा है कि यह तकनीक सेना के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि यह सैनिकों के लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करती है और उनकी सुरक्षा को बढ़ाती है। इन जूतों में टीईएनजी सिस्टम अपग्रेड ट्राइबो-पयेर्स, फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपलीन (एफईपी) और एल्यूमीनियम का उपयोग करता है, ताकि हर कदम के साथ बिजली पैदा हो सके।

एक हजार मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज

इंडोनेशिया के वेस्ट जावा स्थित लेमाहसुगिह में सड़क पर एक हजार मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। यह देश के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के क्रम में लगा है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एएफपी

इधर-उधर की

सिर में जूं के कारण विमान की आपातकालीन लैंडिंग

एयरलाइन ने यात्रियों को दिए होटल वाउचर व 12 डालर। इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी : लासएंजिल्स से न्यूयार्क जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की विमान को एक यात्री के बालों में जूं देखने की सूचना मिलने के बाद फीनिक्स में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इस घटना की जानकारी उसी विमान में सवार यात्री एथन जुडेलसन ने इंटरनेट मीडिया पर दी है। जुडेलसन ने बताया कि एयरलाइन ने केवल आपातलैंडिंग की सूचना दी थी। कुछ सहयात्रियों से पता चला कि एक यात्री के बालों में रेंगते हुए कीड़े जैसा जीव देखने के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्हें 12 घंटे देरी हुई।

बच्चों में मोटापा बन सकता है खराब स्वास्थ्य का कारण

नई दिल्ली, आइएएनएस : विशेषज्ञों ने कहा कि बचपन में मोटापा स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख और लगातार बढ़ती चिंताओं में से एक है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा आयु वर्ग में आता है। बचपन में मोटापा एक बढ़ती हुई चिंता है जो वयस्कता में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।

भारत में बचपन में मोटापे की बढ़ती समस्या को संबोधित करते हुए विशेषज्ञ इससे जुड़े दीर्घकालिक स्वास्थ्य खतरों को लेकर समय रहते हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हैं। मोटापे के प्रबंधन और रोकथाम में स्कूल आधारित शिक्षा और स्वस्थ भोजन कार्यक्रम जैसी पहल महत्वपूर्ण हैं। जीवनशैली में बदलाव वयस्कता के खतरों को मैनेज करने का प्राथमिक साधन बना हुआ है। साथ ही अधिक गंभीर और विशिष्ट मामलों के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी एक विकल्प बनी हुई है। इस बारे में निजी अस्पताल में मिनिमल और बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जरी में कंसल्टेंट डॉ. दक्ष सेठी ने बताया कि हमारे देश में बचपन में मोटापा एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि हमारी बड़ी युवा आबादी है। मोटे बच्चों के मोटे वयस्क बनने की संभावना अधिक होती है, जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द और आब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी कई मेटाबोलिज्म स्थितियों का सामना करते हैं।

- मोटापे के प्रबंधन और रोकथाम में स्कूल आधारित शिक्षा और स्वस्थ भोजन कार्यक्रम जैसी पहल महत्वपूर्ण
- ब्लडप्रेशर, कोलेस्ट्राल और ग्लूकोज के स्तर की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी

मोटापे का बढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। फाइल

उन्होंने स्कूल आधारित पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला। अमेरिका से प्रेरणा लेते हुए जहां स्कूल मासिक रूप से बीएमआई को ट्रैक करते हैं और परिवारों के साथ उसी के अनुरूप कार्रवाई करते हैं। उन्होंने बचपन के मोटापे की निगरानी और प्रबंधन के लिए भारत के लिए एक समान दृष्टिकोण का सुझाव दिया। इसके इलाज के लिए उन्होंने कहा कि जीवनशैली में बदलाव महत्वपूर्ण हैं। बड़े बच्चों या विशिष्ट स्थितियों वाले बच्चों के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी पर विचार किया जाता है। इस दौरान वयस्क होने पर वजन बढ़ने का हृदय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की गई। इसका मुख्य समाधान संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ-साथ दीर्घकालिक हृदय संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच को अपनाना है।

इस बारे में गोवा के निजी अस्पताल में इंटरवेंशनल कार्डियोलाजी में कंसल्टेंट डा. ज्योति कुसनूर ने बताया कि वयस्क होने के बाद अधिक वजन के कारण उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मेटाबोलिज्म संबंधी विकारों के बढ़ते खतरे से जुड़ा हुआ है।

यह धमनियों में प्लाक के निर्माण में योगदान देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने संतुलित आहार बनाए रखने, नियमित व्यायाम करने और हानिकारक आदतों से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का जल्द पता लगाने और प्रबंधन के लिए ब्लडप्रेशर, कोलेस्ट्राल और ग्लूकोज के स्तर की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच महत्वपूर्ण है।

अस्पताल के बाद मरीज के परिवार में सुपरबग संक्रमण का खतरा

अनुसंधान

अस्पताल से छुट्टी के बाद मरीज के परिवार के सदस्यों को कुछ दिन उससे सुरक्षित संपर्क रखना ठीक रहता है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज के परिवार को मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफीलोकोकस एरियस (एमआरएसए) सुपरबग का उच्च जोखिम रहता है, चाहे मरीज में संक्रमण का निदान न भी हुआ हो।

शोध का निष्कर्ष इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हास्पिटल एपिडिमिओलाजी जर्नल में मंगलवार को प्रकाशित हुआ है। आयोवा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि समुदाय में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए अस्पतालों को गंभीरता से भूमिका निभानी चाहिए। एरोन मिलर के नेतृत्व में हुए शोध में कहा गया कि जितने अधिक समय तक मरीज अस्पताल में रहता है, एमआरएसए सुपरबग के संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। इससे परिवार के सदस्यों में संक्रमण फैल सकता है। इसलिए अस्पतालों को भी संक्रमण रोकने के लिए मरीज से संपर्क पर निगरानी रखनी चाहिए। इसमें मरीज को डिस्चार्ज करते समय एमआरएसए का परीक्षण भी जरूरी है। एमआरएसए को सुपरबग के रूप में जाना जाता है, इस पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। रक्त व फेफड़ों में संक्रमण होने पर यह घातक होता है। शोधकर्ताओं ने 4,24,512 एमआरएसए मामलों की समीक्षा की। शोध में पाया गया कि एमआरएसए से संक्रमित मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद परिवार के सदस्यों में संक्रमण की 71 गुना अधिक आशंका होती है, जबकि बिना एमआरएसए निदान वालों से 44 प्रतिशत संक्रमण की आशंका होती है। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

जहां हूं, अपनी पसंद की वजह से हूं : अनन्या पांडे

काल मी बे से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करेंगी अनन्या। इंस्टाग्राम (@ananyapanday)

काम जहां अच्छा मिले, उसे अपना लो। इसी राह पर चल रही हैं अभिनेत्री अनन्या पांडे। अनन्या उन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्हें कमर्शियल फिल्मों के साथ ही गहराइयां और खो गए हम कहां जैसी फिल्मों में भी मौका मिल रहा है, जो कमर्शियल जानर से थोड़ी अलग हैं। अनन्या का कहना है कि आज वह जिस स्तर पर पहुंची हैं, यह उनकी पसंद का ही नतीजा है। एक साक्षात्कार में अनन्या कहती हैं कि जब मुझे खो गए हम कहां, गहराइयां जैसे कंटेंट मिले, तो महसूस हुआ कि मैं संतुष्ट एक्टर बनती जा रही हूं। इन फिल्मों के लिए बतौर कलाकार जो प्रतिक्रिया फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों की तरफ से मिली, वह कमाल थी। मैं आज कह सकती हूं कि अपने करियर में जहां हूं, वह उन्हीं पसंद की वजह से हूं। बहुत स्वाभाविक तरीके से ऐसा होता गया। हालांकि मैं मसाला फिल्में भी करना चाहती हूं। कमर्शियल और कंटेंट वाली फिल्मों के बीच जो संतुलन है, वही बतौर एक्टर मैं चाहती हूं। आगामी दिनों में वेब सीरीज काल मी बे और फिल्मकार विक्रमादित्य मोटवाणी की साइबर थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली अनन्या अब हारर कामेडी फिल्म की तलाश में हैं। वह कहती हैं कि मुझे हालांकि हारर फिल्मों से डर लगता है लेकिन एक फिल्म करना चाहती हूं। मेरी पसंदीदा फिल्म भूल भुलैया है, जिसे देखकर मैं आज भी डरती हूं।

अब मानुषी छिल्लर को निर्देशक पुलकित की फिल्म का सहारा

साल 2022 में प्रदर्शित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने वाली अभिनेत्री मानुषी छिल्लर को अपनी पहली फिल्म से काफी उम्मीदें थी। हालांकि वह फिल्म नहीं चली और उसके साथ मानुषी को भी उम्मीदों के अनुसार मौके नहीं मिल पाए। यही हाल फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के साथ भी हुआ। अभी तक उनके हिस्से में कोई सफल फिल्म नहीं आई है। अब मानुषी को फिल्म भक्षक के निर्देशक पुलकित का सहारा मिला है। पुलकित निर्देशित 'भक्षक' में अभिनेत्री भूमि पेडणेकर के काम की काफी तारीफ हुई थी। फिल्म में उनके साथ अभिनेता राजकुमार राव मुख्य भूमिका होंगे। एक रिपोर्ट्स के अनुसार, राजकुमार और मानुषी दोनों ने इस फिल्म के लिए स्वीकृति दे दी है। यह एक थ्रिलर फिल्म होगी, हालांकि फिल्म की कहानी और पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राजकुमार फिलहाल आगामी फिल्म स्त्री 2 के प्रमोशन में व्यस्त हैं। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार तो राजकुमार और मानुषी अगले महीने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। जवानी जानेमन और फ्रेडी फिल्मों के निर्माता जय शेवक्रमणि के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को अगले साल सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने की योजना है।

कुछ अलग मौके देख रही हैं मानुषी। (@manushi_chhillar)

केंद्रीय भूमिका पाकर खुद पर यकीन नहीं कर पा रही हैं प्रिया ठाकुर

धारावाहिक वसुंधरा में शीर्षक भूमिका में होंगी प्रिया। टीम जी टीवी

वर्तमान से बेहतर स्थिति में जाने और बेहतर काम करने की इच्छा तो हर कलाकार में होती है। पर उन्हें ऐसे मौके कितने मिलते हैं यह उनके भाग्य और मेहनत दोनों पर निर्भर करता है। पंजाबी धारावाहिकों और वेब सीरीज की अभिनेत्री प्रिया ठाकुर अगले महीने से जी टीवी पर शुरू होने जा रहे धारावाहिक वसुंधरा में शीर्षक भूमिका में नजर आएंगी। राष्ट्रीय स्तर के टेलीविजन पर मौका मिलने की खुशी के साथ प्रिया पर एक दबाव भी है। दैनिक जागरण से बातचीत में वह कहती हैं, 'हां, दबाव तो ज्यादा है। इससे पहले मैंने पंजाबी धारावाहिकों में केंद्रीय भूमिका निभाई है, लेकिन किसी राष्ट्रीय स्तर के शो में पहली बार केंद्रीय भूमिका निभा रही हूं। ऐसे में मन में सवाल उठ रहे हैं कि शो दर्शकों को कैसे लगेगा, मेरे काम के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी।' प्रिया कहती हैं कि मैं करीब छह महीने से मुंबई में हूं। तभी से मैं लीड और पैरेलल लीड भूमिकाओं के लिए आडिशन दे रही थी। वसुंधरा की भूमिका मुझे मेरे जैसी चुलबुली और नटखट लगी। मैंने स्वाभाविक व्यक्तित्व के हिसाब से आडिशन दिया, जो कि सिर्फ एक टेक में ही हो गया। फिर फोन आया कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाओ, आप चुन ली गई हो। उस दिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था।

धनुष के साथ बन सकती है कृति की जोड़ी

रांझणा फिल्म की रिलीज के दस वर्ष पूरे होने पर निर्देशक आनंद एल राय ने पिछले साल धनुष के साथ एक नई एक्शन रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' की घोषणा की थी। धनुष की दक्षिण भारतीय फिल्मों की प्रतिबद्धताओं के कारण इस फिल्म को शुरू करने में विलंब हुआ। इस बीच फिल्म की अभिनेत्री और बाकी के कलाकारों को लेकर तरह-तरह के कयास सामने आए। हालांकि, अभिनेत्री को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आनंद अक्टूबर से फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। इस बीच अब फिल्म की अभिनेत्री के तौर पर कृति सैनन का नाम सामने आ रहा है। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म को लेकर कृति और आनंद एल राय के बीच पिछले कुछ महीनों से बातचीत चल रही है। कृति भी इस एक्शन लव स्टोरी फिल्म को करने में काफी दिलचस्पी ले रही हैं। उन्होंने फिल्म को मौखिक स्वीकृति दे दी हैं, अभी उनका कागजी तौर पर फिल्म साइन करना बाकी है। धनुष और कृति के अलावा निर्माता इस फिल्म में कई अन्य नामचीन कलाकारों को कास्ट कर रहे हैं। धनुष के साथ आनंद की यह तीसरी फिल्म है।

« कमर्शियल और विषय प्रधान फिल्मों के बीच संतुलन बनाकर चल रही हैं कृति ● जागरण आर्काइव

रीति रिवाजों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं

अब डिजिटल प्लेटफार्म पर तुषार अपने लिए देख रहे हैं बेहतर मौके ● मिडडे आर्काइव

ढोल और गोलमाल फिल्मों के अभिनेता तुषार कपूर अपने पिता जितेंद्र के पदचिन्हों पर चलते हुए रीति रिवाजों का पालन करने में पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने हाल ही में जिओ सिनेमा पर प्रदर्शित वेब सीरीज दस जून की रात से डिजिटल प्लेटफार्म पर कदम रखा है। शो में उनका पात्र कुंडली और ज्योतिष शास्त्र में काफी यकीन रखता है। निजी जिंदगी में इन चीजों के पालन पर दैनिक जागरण से बातचीत में तुषार कहते हैं, 'मेरे परिवार भी पारंपरिक हिंदुस्तानी परिवार की तरह है। हम रीति रिवाजों के साथ जीते आए हैं। हालांकि, मैं ज्योतिषशास्त्र में इतना ज्यादा भी नहीं पड़ता हूं कि हमेशा उसी बारे में सोचता रहूं। परिवार में हर नए काम की शुरुआत शुभ मुहूर्त के अनुसार की जाती है। मैं हर सप्ताह शनि मंदिर भी जाता हूं। साल में एक या दो बार तिरुपति मंदिर भी जाता हूं। मैं धार्मिक व्यक्ति तो हूं, लेकिन कट्टर नहीं हूं।'

'एक रुका हुआ फैसला' रीमेक नहीं है

कई ऐसी फिल्में हैं, जैसे जिन्हें कई सालों बाद आज की पीढ़ी के लिए समकालीन परिवेश में बनाया जा रहा है। उनमें बावर्ची और अंगूर जैसी फिल्मों के बाद अब साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म एक रुका हुआ फैसला का नाम भी शामिल हो गया है। इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। साल 1986 में रिलीज हुई बासु चटर्जी निर्देशित यह फिल्म 1957 में रिलीज हुई फिल्म 12 एंग्री मेन की रीमेक थी। इस फिल्म में काम करने को लेकर अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने दैनिक जागरण को बताया, 'मेरा इस फिल्म को करने को लेकर लालच यही था कि इसमें कई बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। फिल्म में अतुल कुलकर्णी, सुविंदर विक्की, नीरज काबी, तनिष्ठा चटर्जी समेत कई कलाकार हैं।' क्या फिल्म को शूट करने से पहले दिव्या ने मूल फिल्म देखी थी? इस पर वह कहती हैं, 'इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने जानबूझ कर नहीं देखी थी। यह रीमेक नहीं, बल्कि अडैप्टेशन है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं, कहानी अलग है, इस बार अभिनेत्रियां भी फिल्म की कहानी में शामिल की गई हैं।'

फिल्म में दिव्या संग होंगे कई कलाकार ● जागरण आर्काइव »

जो ज्यादा फीस लेते हैं, उन्हें मत लो : नवाजुद्दीन

फिल्म की कहानी अच्छी होनी चाहिए, फिर प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो या छोटा, फीस कितनी मिल रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यह मानना है अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। पिछले दिनों फिल्मकार करण जौहर ने कहा था कि ज्यादा फीस मांगने वाले बड़े कलाकारों को बाक्स आफिस की समीक्षा करके फिर फीस मांगनी चाहिए। नए निर्माता-निर्देशकों के साथ काम करने वाले नवाजुद्दीन खुद को बड़े कलाकारों से अलग मानते हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में वह कहते हैं कि हां, मैं करण की इस बात को मानता हूं। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि जो समीक्षा नहीं करते हैं या ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं, उनको मत लो। उन्हें फिर क्यों लेते हैं। मुझे खुद की समीक्षा की जरूरत इसलिए महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं इतनी फीस लेता ही नहीं हूं। । मैं खुद को इस रेस में नहीं मानता हूं। मुझे अपनी वास्तविकता पता है। मैं कोई आडंबर नहीं कर रहा हूं। यह सच है। मेरी ज्यादातर फिल्में छोटे बजट की होती है। वह लागत आराम से थिएटर रिलीज, ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स से निकल आती है। कला को देखने का नजरिया मेरा दूसरों से अलग है। मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं होता हूं। अच्छी फिल्में करने की ललक रहती है। मैं अगर फीस के बारे में सोचता, तो नए-नए निर्देशकों के साथ कैसे काम करता। मैं छोटी-बड़ी फिल्में कर रहा हूं।

वकील की भूमिका में दिखेंगे नवाजुद्दीन। (@nawazuddin._siddiqui)

अपनी धाक जमाने लौट आई हूं : मीनाक्षी शेषाद्री

हीरो, घायल, दामिनी फिल्मों की अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री भी 28 साल बाद हिंदी फिल्मों की ओर लौट आई हैं। शादी के बाद अमेरिका में कई वर्षों तक रहीं मीनाक्षी पुणे में रह रही थीं, लेकिन अब वह मुंबई में घर तलाश रही हैं। एक साक्षात्कार में मीनाक्षी कहती हैं, 'अपनी धाक जमाने आई हूं। काफी समय से मुंबई में रहने के निर्णय को टाल रही थी। फिर भीतर की आवाज सुनी, अब तीन-चार हफ्ते से जगह ढूंढ रही हूं। अपने अभिनय की पहली पारी में मैं बहुत ही सहमी सी थी। लोगों से ज्यादा मिलती नहीं थी। पार्टी में सबके आने से पहले मैं खाना खाकर, फोटो खिंचवाकर चली जाती थी, क्योंकि मुझे अपनी नींद पूरी करनी होती थी, ताकि अगले दिन की शूटिंग पर जा सकूं। इस बार आराम से हूं। दोस्त बनाने हैं। कई महिला निर्देशकों के साथ काम करना है। मैं खुशी-खुशी आडिशन देने के लिए भी तैयार हूं। मैंने इस रचनात्मक क्षेत्र को बहुत याद किया। फिर से प्रतिभाशाली लोगों से जुड़ना है। मैंने कामेडी कम की है, वह करना है। मेरा कोई आइटम गाना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आइटम गाने के लिए बीस साल की उम्र होना चाहिए, एक लुक होना चाहिए, उन सबको झुठलाना है। दो-तीन अच्छी स्क्रिप्ट्स सुनी है, हैरान हूं, जिस तरह के पात्र मुझसे मेकर्स करवाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक मैंने कुछ साइन नहीं किया है, सब कुछ बातचीत के स्तर पर है।'

आइटम गाने करना चाहती हैं मीनाक्षी ● @meenakshiseshadriofficial (इंस्टाग्राम)

****